संपादकीय

सीएमएस-03: भारतीय संचार का नया सितारा

पिछले दिनों श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से बाहुबली रॉकेट एलवीएम3-एम5 ने भारत के अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह सीएमएस-03 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया और उसी के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। यह प्रक्षेपण न केवल भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नई छलांग है बल्कि यह उस आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है, जिसकी परिकल्पना आज का भारत अपने वैज्ञानिक संकल्प से साकार कर रहा है। करीब 4,410 किलोग्राम वजनी सीएमएस-03 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) में स्थापित किया गया है। यह भारत की धरती से अब तक छोड़ा गया सबसे भारी संचार उपग्रह है। यह उपग्रह भारत तथा आसपास के समुद्री क्षेत्रों में मल्टी-बैंड संचार सेवाएं प्रदान करेगा और अगले 15 वर्षों तक देश की संचार प्रणाली की रीढ़ साबित होगा। इस मिशन की सफलता ने एक बार फिर इसरो की वैज्ञानिक दक्षता, तकनीकी परिपक्वता और अडिग संकल्प का प्रमाण दिया है। बाहुबली नाम अपने आप में इस रॉकेट की क्षमता का परिचायक है। एलवीएम3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-3) इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है, जो लगभग 43.5 मीटर ऊंचा और तीन चरणों में कार्य करने वाला रॉकेट है। इसकी भार वहन क्षमता ही इसे बाहुबली का दर्जा देती है। यह रॉकेट लगभग 4,000 किलोग्राम वजन तक के उपग्रहों को जीटीओ में और 8,000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा (लो अर्थ ऑर्बिट) तक पहुंचाने में सक्षम है। यह वही रॉकेट है, जिसने भारत को विश्व पटल पर गौरव दिलाने वाला ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया था, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का झंडा लहराया। एलवीएम3-एम5 रॉकेट तीन चरणों में कार्य करता है। पहले चरण में इसके दो ठोस बूस्टर रॉकेट एस-200 प्रारंभिक लिफ्ट ऑफ के लिए भारी थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। दूसरे चरण में एल-110 लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज आता है, जिसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित किया गया है। तीसरे और अंतिम चरण में क्रायोजेनिक इंजन सी-25 कार्य करता है, जो सैटेलाइट को सटीक रूप से उसकी कक्षा में स्थापित करने की अंतिम जिम्मेदारी निभाता है। यह जटिल प्रणाली और उसकी सटीक कार्यप्रणाली भारत की उस इंजीनियरिंग दक्षता की परिचायक है, जिसने आज विश्व की शीर्ष चार अंतरिक्ष शक्तियों में भारत को स्थापित किया है। इसरो के इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि यह भारत को भारी उपग्रह प्रक्षेपण में पूर्ण आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करता है। इससे पहले इसरो को अपने भारी उपग्रहों के लिए विदेशी लॉन्च सेवाओं का सहारा लेना पड़ता था, जैसे कि दिसंबर 2018 में जीएसएटी-11 को फ्रैंच गयाना से एरिएन-5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।

नई दिल्ली कार्यालय
एक्शन बालाजी हाउस, बी-244, मजलिस पार्क, दिल्ली- 110033

उत्तरी दिल्ली कार्यालय
शक्ति कॉम्पलैक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110042

चंडीगढ़ कार्यालय
फर्स्ट फ्लोर, देश सेवक बिल्डिंग, सेक्टर- 29डी, चंडीगढ़

पंजाब कार्यालय
7/2, थर्ड फ्लोर, मोनिका, टावर, ईआर-146, पक्का बाग, मिलाप चौक, जालंधर

करनाल कार्यालय
224, सेक्टर 32पी, करनाल- 132001

सोनीपत कार्यालय
एक्शन इंडिया कार्यालय, अपोजिट एनएस कम्प्यूटर, झंडी रोड़, गीता भवन चौक सोनीपत- 131001

शिमला कार्यालय
किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001

ऊना कार्यालय
कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना-174303

देहरादून कार्यालय
7/1, बल्लूपुर रोड़, कृष्णा नगर चौक, देहरादून

पहाड़ बनाम मैदान संघर्ष से जूझता उत्तराखंड

डॉ घनश्याम बादल

> पहाड़ पर जनसंख्या इसलिए कम हुई क्योंकि पिछले दो दशकों में पहाड़ों से रोजगार और शिक्षा की तलाश में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ।
> राजनीतिक दृष्टि से देखें तो विधानसभा की 70 सीटों में 44 सीटें पहाड़ी जिलों में,और 26 सीटें मैदानी जिलों में आती हैं। यही अनुपात आगे चलकर मंत्रीमंडल गठन में सत्ता-संतुलन का आधार बन गया। राज्य गठन से अब तक मंत्रिमंडलों नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, भुवनचंद्र खंडूड़ी, रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा, हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए

आज से 25 साल पहले उत्तर प्रदेश के पर्वतीय हिस्सों को अलग कर पहाड़ के विकास को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड का जन्म हुआ। उत्तराखंड का अस्तित्व एक जनांदोलन की परिणति था, जिसका मूलभाव था पहाड़ का शासन पहाड़ के हाथ में। 9 नवम्बर 2000 को जब उत्तरांचल के नाम से आज का उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, तो लोगों की अपेक्षा थी कि अब निर्णय, विकास और नेतृत्व स्थानीय आवश्यकताओं पर केंद्रित होंगे।लेकिन राज्य गठन के पच्चीस वर्षों में ही पहाड़ बना मैदान की बहस ने जन्म ले लिया। आज मैदाने के निवासी खुलकर यह कहते हैं कि उत्तराखंड की सत्ता केवल पहाड़ तक सिमट गई है, और मैदान की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही है? उत्तराखंड की राजनीति में पहाड़ बनाम मैदान का यह विभाजन अब सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों और सत्ता-संतुलन क प्रश्न बन भी बन गया है। जहां तक पहाड़ और मैदान की बात है तो आज भी जवानी और पानी पहाड़ पर नहीं रुक पा रहे हैं । पहाड़ से पलायन की समस्या जस की तस है । भुतहा गांवों की संख्या बढ़ती जा रही है । पहाड़ के लोग और नेता मैदान के लोगों को आज भी पूरी तरह अपना नहीं पा रहे हैं मैदान के लोगों का कहना है कि जो लोग मैदान से पहाड़ पर शिक्षा, रोजगार व्यापार या फिर दूसरे कारणों से जाकर बस रहे हैं वहां उन्हें देसी कहकर उनका तिरस्कार किया जाता है जबकि पहाड़ से एक बार व्यक्ति यदि उतर कर मैदान में बस गया तो फिर वह पहाड़ की ओर लौटता ही नहीं है। पहाड़ और मैदान के इस संघर्ष के पीछे सबसे बड़ी वजह है राजनीति और राजनीति में भी वर्चस्व की लड़ाई। उत्तराखंड के सभी मंत्रिमंडलों में मैदान के नेताओं की संख्या लगातार कम होती रही है,इसके पीछे राजनीतिक कारण काम करते हैं। राज्य गठन के समय उत्तराखंड में कुल 10 जिले थे, तीन जिले बाद में बनाए गए अब कल 13 जिलों में से 10 जिले पहाड़ी क्षेत्र के पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी हैं तो मैदानी क्षेत्र में देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर हैं। पहाड़ क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक

क्षेत्रफल का लगभग 70% है, परंतु जनसंख्या का लगभग 55% हिस्सा मैदानों में बसता है। पहाड़ पर जनसंख्या इसलिए कम हुई क्योंकि पिछले दो दशकों में पहाड़ों से रोजगार और शिक्षा की तलाश में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ।
राजनीतिक दृष्टि से देखें तो विधानसभा की 70 सीटों में 44 सीटें पहाड़ी जिलों में,और 26 सीटें मैदानी जिलों में आती हैं। यही अनुपात आगे चलकर मंत्रीमंडल गठन में सत्ता-संतुलन का आधार बन गया। राज्य गठन से अब तक मंत्रिमंडलों नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, भुवनचंद्र खंडूड़ी, रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा, हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए लेकिन इनमें से एक भी मैदान के क्षेत्र का नहीं है। उत्तराखंड में शुरू से ही कांग्रेस और भाजपा के बीच सरकार की अदला-बदली होती रही है और हर सरकार में पहाड़ी क्षेत्र का ही दबदबा रहा, जबकि मैदानी जिलों की भागीदारी 15% से 25% के बीच सीमित रही। यह असंतुलन केवल संयोग नहीं है, बल्कि राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है। उत्तराखंड की मांग मुख्यतः गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों से उठी थी। इसलिएआंदोलनकारी नेतृत्व, जनभावनाएं और पहाड़ की पीड़ा ही राज्य की पहचान बन गई। राज्य बनने के बाद सत्ता का प्रसाद भी उन्हीं क्षेत्रों को मिला जिन्होंने आंदोलन चलाया। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों के संगठनात्मक ढांचे पुराने और मजबूत हैं।पार्टी हाईकमान को चुनावी टिकट और पद इन्हीं परंपरागत गढ़ों के नेताओं को देना राजनीतिक रूप से सुरक्षित लगता रहा है। आज भी उत्तराखंड में मैदान की बाहरी छवि है । हरिद्वार और उधमसिंह नगर जैसे जिलों में बड़ी आबादी प्रवासी मानी जाती है । इस धारणा ने इन क्षेत्रों के नेताओं को पहाड़ी सत्ता संरचना में स्वीकार्यता सदैव कम की है। राजनीतिक और जातीय समीकरण भी इस असंतुलन के मुख्य कारण हैं। पहाड़ी जिलों में ब्राह्मण-राजपूत वर्ग का राजनीतिक दबदबा रहा है। वहीं मैदानों में पिछड़े वर्ग, दलित और व्यापारी समुदाय अधिक हैं। सत्ता का केंद्र हमेशा उच्च जातीय-प्रभाव वाले पहाड़ रहे, मैदान के लोगों काआप है कि वहां के नेताओं को शीर्ष पदों से दूर रखा गया। मैदान के लोगों का यह भी मानना है कि वे राज्य की आर्थिक रीढ़ है। उद्योग उधमसिंह नगर में, धार्मिक पर्यटन हरिद्वार में और प्रशासनिक राजधानी देहरादून में है. फिर भी राजनीतिक निर्णय पहाड़ को केंद्र मैं रखकर लिए जाते हैं जिस कारण मैदान की औद्योगिक नीति, भूमि विवाद,श्रमिक आवास, शिक्षा और रोजगार जैसी समस्याएं उपेक्षित ही रह जाती हैं। यह असमानता अब ध राजनीतिक असंतोष में बदल रही है, मैदान को उत्तर प्रदेश में पुनः मिलाने की मांग तक उठने लगी है।
इतना ही नहीं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली और बिजनौर तथा बुलंदशहर के साथ हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश उधम सिंह नगर और रुड़की जैसे शहरों को मिलाकर हरित प्रदेश की मांग धीरे-धीरे सुलग रही है। यदि मैदान के साथ भेदभाव कम नहीं हुआ तो फिर यह खाई बढ़ती चली जाएगी और हो सकता है निकट भविष्य में उत्तराखंड को भी एक विभाजन देखना पड़े।

मैदान और पहाड़ के बीच संतुलन की सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक स्वार्थ।

हर सरकार को यह भय रहता है कि यदि मंत्रिमंडल में मैदान का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया,तो उसे आंदोलन की भावना से विश्वासघात माना जाएगा इसलिए प्रतीकात्मक रूप से 2-3 मंत्री मैदान से रखे जाते हैं, ताकि आलोचना न हो जाए। मैदान के तीन जिलों की कुल विधानसभा सीटें केवल 26 हैं, इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री सांख्यिकीय अनुपात के आधार पर पहाड़ को वरीयता देना उचित ठहराता है। लेकिन जब सारे मंत्री पहाड़ से होंगे तब मैदान की अपेक्षा भी स्वाभाविक है और इससे असंतोष का पनपना भी। अब बीजेपी हो या फिर कांग्रेस दोनों में ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और प्रभारी अधिकतर पहाड़ी पृष्ठभूमि से आते हैं,जिससे टिकट वितरण और मंत्री पदों पर उनकी सिफारिश निर्णायक रहती है। मैदान के विधायक अक्सर जातीय और औद्योगिक मुद्दों पर मुखर रहते हैं। इससे भी मुख्यमंत्रियों को डर रहता है कि मैदान के अधिक मंत्री होने पर सत्ता-संतुलन बिगड़ सकता है।
इसलिए उन्हें सीमित पद देकर नियंत्रित रखा जाता है।

उत्तराखंड की मुख्य राजनीतिक समस्या है एक राज्य, दो मानसिकताएँ

इस असंतुलन ने पहाड़ की सत्ता बनाम मैदान के संसाधन की सांस्कृतिक और भावनात्मक अलगाव को बल दिया है. किस से राजनीतिक स्वास्थ्य की पूर्ति तो हो गई लेकिन आर्थिक और औद्योगिक चुनौतियाँ उपेक्षित रह गईं।पहाड़ी जनता यह मानती है कि मैदानों में राजनीति बाहरी प्रभावों से नियंत्रित होती है,जबकि मैदान की जनता को लगता है कि पहाड़ की राजनीति भावनाओं में डूबी है, व्यावहारिकता में नहीं। व्यावहारिक दृष्टि से देखे तो राज्य के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है।

सट्टा बाजार बिहार में बनवा रहा है एनडीए सरकार !

संजय सक्सेना

बिहार विधान सभा चुनाव कें पहले चरण के मतदान ने 121 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ 64.66 प्रतिशत वोटिंग के चलते चुनावी नतीजों का गणित लगाने वालों ने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया है। बड़े से बड़े राजनीति के जानकार और पत्रकार भी अपनी रिपोर्ट बैलेंस करके लिख रहे हैं,लेकिन रिकार्ड तोड़ वोटिंग के चलते आने वाले परिणामों को लेकर सट्टा बाजार पूरी तरह से निश्चिंत है। सट्टा बाजार को यह रुझान महाराष्ट्र 2024 के एनडीए तूफान की याद दिला रहा है और सट्टा बाजार में हलचल मचा दी है. सट्टा बाजार के जानकार महागठबंधन की सरकार बनने की संभावनाओं को लगभग शून्य करार दे रहा हैं.पहले चरण के मतदान के बाद अनुमान है कि 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए 145-150 से अधिक सीटें जीत सकता है,जो उसके 2010 के सर्वाधिक प्रदर्शन को भी पार कर सकता है और तेजस्वी यादव के गठबंधन को शर्मनाक हार की ओर धकेल सकता है. इस बार की भागीदारी बिहार के चुनावी इतिहास में सबसे अधिक रही है। 2020 के कोरोना महामारी के समय 57.29 प्रतिशत की तुलना में इस बार पूरे 7.37 प्रतिशत अंक अधिक. इससे एनडीए खेमे में जोश भर गया है. बेगूसराय (67.32फीसदी) और मुजफ्फरपुर (मीनापुर जैसे क्षेत्रों में 73 फीसदी से अधिक) जैसे जिलों में महिलाओं की लंबी कतारें दिखीं, जिसे बीजेपी नेताओं ने अपनी कल्याण योजनाओं के समर्थन के रूप में देखा है. कहा जा रहा है बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जा रहा है, मुंबई के एक सट्टेबाज ने जो कहा वह बीजेपी-नेतृत्व वाले गठबंधन की 2024 महाराष्ट्र की निर्णायक जीत की याद दिला रहा था, जिसने एंटी-इनकंबेंसी को दरकिनार कर विपक्ष को चकनाचूर कर दिया था. एनडीए खेमे के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पहले चरण की 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों पर बढ़त के संकेत हैं, और यह लहर 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण तक जारी रह सकती है. मुंबई और दिल्ली के सट्टा बाजार, जो हमेशा कानूनी धुंध में काम करते हैं, में 06 नवंबर के मतदान के बाद समीकरण काफी बदल गए हैं. पहले महागठबंधन सीमांचल और मिथिलांचल जैसे जातीय रूप से विभाजित इलाकों में मामूली बढ़त पर था, लेकिन 06 नवंबर की जबरदस्त वोटिंग ने विपक्षी दांव को तहस-नहस कर दिया. एक अनुभवी सट्टेबाज ने बताया, एनडीए की जीत की संभावनाएं अब 75-80 प्रतिशत तक पहुंच चुकी हैं, जबकि महागठबंधन की सीटों का अनुमान 80 से नीचे गिर गया है. खासकर अगर बाकी 122 सीटों पर ईबीसी और दलित मतदाताओं की भागीदारी बनी रही तो. सट्टा बाजार के कारोबारी अब एनडीए पर बड़े पैमाने पर दांव लगा रहे हैं।

विचार

महिला पत्रकारों के समक्ष डिजिटल हिंसा की चुनौती

अमरपाल सिंह वर्मा

पत्रकारिता का मकसद होता है सच को सामने लाना और पीड़ितों की आवाज को ताकत देना लेकिन जब वही पत्रकार खुद हिंसा और डर का शिकार बनने लगें तो इसे केवल पत्रकारिता के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी मानी जानी चाहिए। पूरी दुनिया में महिलाओं को डिजिटल हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है लेकिन अब वह महिला पत्रकार सबसे ज्यादा निशाने पर हैं जो सामान्य महिलाओं की आवाज उठाती हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की हाल में आई रिपोर्ट में इस खतरे की गंभीरता को उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में तीन-चौथाई महिला पत्रकारों को ऑनलाइन हिंसा का सामना करना पड़ा है। हर चार में से एक महिला पत्रकार को शारीरिक हमले या जान से मारने की धमकी मिली है। अब यह हिंसा केवल ट्रोलिंग या गालियों तक सीमित नहीं रही। एआई के जरिए डीपफेक, डॉक्सिंग और लैंगिक दुष्प्रचार जैसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है, इसका उद्देश्य महिला पत्रकारों को डराना, चुप कराना और उनकी साख को खत्म करना है। ऐसे लोग चाहते हैं कि महिला पत्रकारों को इस तरह भयभीत और हतोत्साहित कर दिया जाए जिससे वह अपना काम ठीक से न कर पाएं। वह आम महिलाओं की आवाज को बुलंद कर पाएं। यूनेस्को ने चेताया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू होने वाली यह हिंसा अब वास्तविक दुनिया में भी दिखने लगी है। हाल के एक अध्ययन में पाया गया है कि 14 प्रतिशत महिला पत्रकारों को ऑनलाइन धमकियों के परिणामस्वरूप असली जीवन में हिंसा झेलनी पड़ी है। बड़ा सवाल है कि आखिर महिला पत्रकार ही क्यों निशाने पर हैं? दरअसल, महिला पत्रकार ही आम महिलाओं पर होने वालेअन्याय, उनके साथ हो रही घरेलू, सावर्जनिक और डिजिटल हिंसा के मामले उजागर करती हैं। पीड़ित महिलाएं भी पुरुषों के बजाय महिला पत्रकारों के समक्ष अपनी बात को खुलकर कह पाती हैं। महिला पत्रकार लैंगिक हिंसा, सत्ता के दुरुपयोग या असमानता जैसे मुद्दों पर जब स्टोरी करती हैं तो यह न केवल पीड़ित महिलाओं की आवाज को बुलंद करती हैं बल्कि वह उन फासीवादी ताकतों को भी ललकारती हैं जो महिलाओं को सीमाओं में बंधे देखना चाहती हैं। इसी कारण महिला पत्रकारों को डराने और बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। यह केवल ऑनलाइन समस्या नहीं है। ऑनलाइन हिंसा और ऑफलाइन हिंसा के बीच गहरा संबंध है। डिजिटल दुनिया अब वास्तविक हिंसा की तैयारी का मैदान बन चुकी है। एआई तकनीक ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। डीपफेक के जरिए महिला पत्रकारों की फर्जी वीडियो या तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाना आम हो गया है। डॉक्सिंग के जरिए उनकी निजी जानकारी उजागर की जाती है, जिससे उनका और उनके परिवारों का असुरक्षित महसूस करना स्वाभाविक है।
यह पहला मौका नहीं है, जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। इससे पहले विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन 2020 के दौरान प्रकाशित एक स्नैपशॉट रिपोर्ट में भी यह सब उजागर हुआ था। स्नैपशॉट रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वेक्षण में उत्तर देने वाली 73 प्रतिशत महिला पत्रकारों ने अपने कार्य के दौरान ऑनलाइन हिंसा का अनुभव किया। 25 प्रतिशत को शारीरिक हिंसा की धमकियां मिलीं। 18 प्रतिशत को यौन हिंसा की धमकी दी गई जबकि 20 प्रतिशत महिला पत्रकारों के साथ ऑनलाइन हिंसा के संबंध में ऑफलाइन हमला किया गया। इसी प्रकार यूक्रेन में किए गए सर्वे के मुताबिक 81 प्रतिशत महिला पत्रकारों ने ऑनलाइन हिंसा का सामना किया जबकि जिम्बाब्वे में यह संख्या 63 प्रतिशत रही। हाल में दिल्ली में रात को घर लौट रही एक टीवी चैनल की महिला पत्रकार का कुछ लोगों ने पीछा किया। महिला पत्रकारों को सोशल मीडिया पर लगातार अपमानजनक टिप्पणियों, धमकियों और चरित्रहनन का सामना करना पड़ता है। इससे कई पत्रकार मानसिक दबाव में आकर संवेदनशील विषयों पर बोलना या लिखना छोड़ देती हैं।
यह पत्रकारिता और लोकतंत्र दोनों के लिए

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआई: DELHIN / 2006 / 19302

एक्शन इंडिया मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं रवि भारद्वाज द्वारा एक्शन बालाजी हाउस, 244, ब्लॉक- बी, लेन- 3, राकेश भारद्वाज चौक के नजदीक, दिल्ली - 110033 से प्रकाशित एवं मारुतिनंदन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, शक्ति कॉम्प्लेक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110042 से मुद्रित।
संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी
समूह संपादक : रवि भारद्वाज (9999889104)
मेट्रो संपादक : दीपचंद्र कांडपाल (8447314925)
'एक्शन इंडिया' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गये विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। संपादक केवल पीआरबी एक्ट के तहत ही उत्तरदायी। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

आलेख

क्या है 6जी प्लान जिसे 2030 तक पूरा करने का विजन है

रामस्वरूप रावतसरे

भारत ने 6जी को लेकर अपना विजन साफ कर दिया है। भारत उन देशों में शामिल होगा जहाँ सबसे पहले 6जी सेवा शुरू होगी। सरकार ने ह्य6जी विजनह्न लॉन्च कर दिया है। इसमें सभी स्टेकहोल्डर्स को एक साथ लाकर काम करने पर बल दिया गया है। मौजूदा 5जी से 6जी करीब 1000 गुना ज्यादा तेजी से डेटा ट्रांसफर कर सकेगा। पलक झपकते ही बड़े से बड़ा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। वहीं बहुत तेज गति से इंटरनेट एक्सेस किया जा सकेगा। केन्द्र सरकार के मुताबिक 5जी के रोल आउट और एडॉप्शन के बाद अब 6 जी पर पूरा फोकस किया गया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का ये लक्ष्य है कि साल 2030 तक भारत में 6जी तकनीक को विकसित किया जा सके। 6जी यानी छठी पीढ़ी की वायरलेस तकनीक, आने वाले समय में इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी। इसे 5जी से लगभग 1000 गुना तेज माना जा रहा है यानी इतनी रफ्तार कि एक माइक्रोसेकेंड में डाटा का आदान-प्रदान संभव होगा। जहाँ 5जी ने स्मार्ट डिवाइसों और तेज नेटवर्क का नया दौर शुरू किया था, वहीं 6जी उससे कहीं आगे जाकर मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र को बदलने की क्षमता रखता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा सर्जरी, खासकर दूरस्थ सर्जरी में देखने को मिलेगा जहां डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी रीयल टाइम में ऑपरेशन कर सकेंगे। इसके अलावा रोबोटिक्स, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के साथ-साथ रीयल टाइम ऑनलाइन गेमिंग जैसे क्षेत्रों में भी यह तेजी और सटीकता प्रदान करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार 6जी नेटवर्क 1 टेराबाइट प्रति सेकंड तक की डेटा स्पीड दे सकता है, जो सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और उद्योग जगत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। 6जी नेटवर्क उच्च तकनीक से लैस सटीक लोकेशन ट्रैकिंग और वर्चुअल अनुभव को ज्यादा रियल बनाने में मददगार साबित होगा।

जातिवादी दृष्टिकोण से नुकसान

संजीव

देश में अवसरवादी राजनीतिक दलों की उपस्थिति जातिवादी समीकरण के अतिवादी दृष्टिकोण से देश बहुत नुकसान पहुंचा है। अपरिपक्व लोकतांत्रिक संस्थाओं के परिचालन एवं आमजन की सीमित तर्क बुद्धि और अदूरदर्शिता की सोच के कारण कई बार जनता को हानि हुई है।

राजनीतिक पार्टियों की अवसरवादी तथा पद लोलुपता की अभिवृत्ति जनता को तुरंत लाभ देने की नीति लोकतंत्र को बहुत बड़े खतरे की ओर ले जाती है। इससे राष्ट्रीय विकास की क्षमता में बहुत ज्यादा स्खलन होने की संभावना होती है' जनता के हितों उनकी भावनाओं से खिलवाड़ अंततः राष्ट्रीय चरित्र तथा अनुशासन के स्थान पर आर्थिक तथा सामाजिक असुरक्षा चरित्र को जन्म देती है' अवसरवादीता राजनीति का एक अंग हो सकता है किंतु सदैव पद लोलुपता राजनीति को गर्त में ले जाने जैसा है। यह अलग मुद्दा है कि जन भावना बहुमत की भावना तथा सामाजिक प्रथाएं एवं तात्कालिक हित किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक अंग हो सकते हैं। लोकतंत्र में विशेष परिस्थितियों में जनता का समर्थन प्राप्त करना एवं उनके हितों की रक्षा के लिए नए उपायों की अवधारणा उचित हो सकते और आवश्यक भी, किंतु राजनीति में पद लोलुपता अवसरवादी ता एवं जातिवाद को विखंडित करने की नियत किसी भी दृष्टि से लोकतंत्र के हित में नहीं दिखाई देती हैं' भारतीय परंपरा में भी साम दाम दंड भेद सुशासन का प्रमुख उपकरण मान लिया गया है। इसके दूरगामी परिणाम तुष्टीकरण के साथ-साथ अनुशासन की महत्ता को कमतर करने का कार्य करते हैं' यह सुनिश्चित है कि बिना विकसित लोकतांत्रिक उपकरणों के लोकप्रियता को मापना एक दुष्कर कार्य हो जाता है। कई बार कम संख्या परंतु मजबूत संगठन वाले समूह के हित के लिए अनुचित साधन बनकर रह जाते हैं। यही कारक बहुमत के शासन के लोकतांत्रिक आदर्श और विकास के विपरीत चले जाते हैं' लोकतांत्रिक मूल्यों सिद्धांतों को अवसरवादी का पत्ता एवं दलबदल क्षति पहुंचाने के बहुत बड़े कारण हैं' अवसरवाद तथा सत्ता की चाहत लोकतांत्रिक मूल्यों के दूरगामी दुष्परिणामों का बड़ा संकेत हो चुका है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस रेमेडीज

वर्ष : 3 । अंक : 292

सम्पादकीय

कानून और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के बीच की खाई को पाटने का दिवस आज

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत में कानूनी सेवा दिवस आज मनाया जाएगा। यह दिवस कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 की स्मृति में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कमजोर और वंचित वर्गों के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य शामिल हैं। यह दिवस लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और लोक अदालतों जैसी वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य कानून और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के बीच की खाई को पाटना है, ताकि सभी को निष्पक्ष और समान न्याय मिल सके।यह अधिनियम वर्ष,1995 को लागू हुआ था और तब से हर साल इस दिन को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विधिक सेवा से संबंधित मानकों के निर्माण और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन तथा अधिकतम उपयुक्त और किफायती विधिक सेवा कार्यक्रम स्थापित करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। भारत में न्याय व्यवस्था के ढांचे में मुख्य संरक्षक का पद मुख्य न्यायाधीश का होता है। इसके अलावा यह गैर-सरकारी संगठनों और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को विधिक सहायता कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन और संचालन में सहायता के लिए धन और अनुदान प्रदान करता है।

BR

सूचना

इस पृष्ठ पर प्रकाशित सभी विशेष लेख व्यक्तिगत सोच के आधार पर है।
-संपादक

आत्मघाती होती शिक्षा प्रणाली: मौतों का भयावह यथार्थ

ललित गर्ग

भारत की शिक्षा प्रणाली को लेकर समय-समय पर प्रश्न खड़े होते रहे हैं। शिक्षा की विसंगतियों एवं दबावों के चलते भी अनेक सवाल खड़े हैं। इन्हीं से जुड़ा यह एक बेहद हृदय विदारक और चिंताजनक तथ्य है कि एक वर्ष देश में लगभग 14,000 स्कूली बच्चों ने आत्महत्या कर ली। इस तथ्य की पुष्टि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भी कर रही है। अधिक घातक तथ्य यह है कि बीते एक दशक में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 की तुलना में यह संख्या 34 प्रतिशत अधिक है। यह केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन मासूम सपनों की समाधियाँ हैं जिन्हें हमारी शिक्षा प्रणाली ने दम तोड़ने पर विवश कर दिया। यह स्थिति किसी एक स्कूल, राज्य या परिस्थिति की नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय शिक्षा तंत्र की विफलता का दर्पण है। पहली नजर में इतनी बड़ी संख्या में आत्मघात के मूल में पढ़ाई का दबाव, अभिभावकों की अतिश्योक्ति पूर्ण महत्वाकांक्षाएं, छात्रों की संवेदनशीलता और तंत्र की नाकामी बताई जा सकती है। लेकिन सवाल है कि हमारा तंत्र क्यों संवेदनहीन बना हुआ है? यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को तलब करके इस बाबत विस्तृत विवरण मांगा है। साथ ही सवाल पूछा है कि क्या देश के सभी शिक्षण संस्थान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी निभा रहे हैं? शिक्षा को प्रतिस्पर्धा का रणक्षेत्र कब तक बनने दिया जाता रहेगा?

आज का विद्यार्थी बचपन से ही एक ऐसी अंधी एवं प्रतिस्पर्धी दौड़ में धकेल दिया जाता है, जिसमें लक्ष्य अंक, ग्रेड, और रैंक बन गए हैं-ज्ञान, संवेदना और चरित्र नहीं। स्कूल अब शिक्षालय नहीं, बल्कि परीक्षा-केंद्र यानी गलाकाट प्रतियोगिता के केन्द्र बन चुके हैं। माता-पिता, शिक्षक और समाज-सभी ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है, जहाँ 'सफलता' का अर्थ केवल डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या उच्च वेतन वाली नौकरी तक सीमित हो गया है। शिक्षा अब व्यक्ति के भीतर के मनुष्यत्व, रचनात्मकता और संवेदना को विकसित करने का माध्यम नहीं रही, बल्कि उसने जीवन को 'प्रदर्शन की प्रतियोगिता' बना दिया है। छोटे बच्चों पर कोचिंग का बोझ, अभिभावकों की अपेक्षाएं, और असफलता का भय?-ये तीन त्रिकोणीय दबाव उन्हें धीरे-धीरे मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। शिक्षा अब एक बोझ और मानसिक तनाव का कारण बन गयी है। एनसीआरबी के आँकड़े बताते हैं कि छात्रों में आत्महत्या के प्रमुख कारण हैं- परीक्षा में असफलता, अभिभावकीय दबाव, भविष्य की चिंता और मानसिक अवसाद। भारत दुनिया के उन शीर्ष देशों में शामिल है जहाँ किशोरों में डिप्रेशन और आत्महत्या की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। कबीर ने कहा था-'पढ़ि-पढ़ि पंडित भया, पर भीतर का मन ना गया।' आज की शिक्षा बच्चों को केवल 'जानकार' बना रही है, 'ज्ञानी' नहीं। विद्यालयों में रट्टामार संस्कृति, अंक-केंद्रित मूल्यांकन और शिक्षकों की संवेदनहीनता बच्चों के भीतर आत्मविश्वास के बजाय भय भर रही है। कई प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर्स में तो यह प्रवृत्ति और विकराल हो जाती है। कोटा, पटना, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में हर वर्ष दर्जनों विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। विडंबना यह है कि वहाँ शिक्षा से ज्यादा 'प्रतियोगिता का उद्योग' पनप गया है। बच्चे अपने परिवारों से दूर, दबाव और भय में जीते हैं, और अंततः जीवन से हार जाते हैं। साल 2020 में आई नई शिक्षा नीति (एनइपी) को लेकर बहुत उम्मीदें थीं कि शायद यह शिक्षा को बच्चों के बोझ से मुक्ति देगी, उसे रचनात्मकता और नैतिकता से जोड़ेगी। नीति में 'होलिस्टिक लर्निंग', 'जॉयफुल एजुकेशन', 'रिड्यूस्ड बोर्ड प्रेशर' जैसे शब्द तो हैं, पर व्यवहारिक स्तर पर हालात में कोई ठोस परिवर्तन नहीं आया। स्कूलों में परीक्षा का दबाव जस का तस है, कॉलेजों में बेरोजगारी का डर और कोचिंग की होड़ बढ़ी है। शिक्षा नीति के भीतर आत्महत्या जैसे मानसिक स्वास्थ्य संकट पर कोई गंभीर विमर्श नहीं हुआ। जब तक शिक्षा नीति का केंद्र मानव-निर्माण नहीं होगा, तब तक यह प्रणाली केवल आंकड़े बढ़ाएगी-आत्महत्याओं के भी और बेरोजगारों के भी। सवाल यह भी है कि शैक्षणिक परिसरों में आत्महत्या रोकने के लिये जो कदम केंद्र व राज्य सरकारों को उठाने चाहिए थे, उसके बाबत देश की शीर्ष अदालत को क्यों पहल करनी चाहिए? इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय को कहना पढ़ा कि केंद्र व राज्य सरकारें आठ सप्ताह के भीतर वह विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करें, जो आत्महत्या रोकने के दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? महात्मा गांधी ने कहा था-'शिक्षा का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का सम्यक विकास।' स्वामी विवेकानंद ने भी कहा 'शिक्षा वह है जो व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्मसंयम और आत्मबल भर दे।' परंतु आज की शिक्षा न शरीर को स्वस्थ रख पा रही है, न मन को शांत, न आत्मा को ऊँचा। बच्चों को किताबों के बोझ तले दबा दिया गया है, पर जीवन की समझ नहीं दी गई। उन्हें बताया गया कि असफलता अपराध है, जबकि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक तो असफलता ही होती है। माता-पिता और शिक्षक दोनों को यह समझना होगा कि बच्चा कोई प्रोजेक्ट नहीं, एक जीवित आत्मा है। उसे सफलता के साँचे में ढालने से पहले उसे अपने ढंग से खिलने का अवसर देना जरूरी है। शिक्षक यदि केवल अंक देने वाले बन जाएं और अभिभावक केवल रिपोर्ट कार्ड से बच्चे की योग्यता मापें, तो बच्चे का आत्मसम्मान कुचलना निश्चित है। जरूरी है कि घर और स्कूल दोनों जगह एक भावनात्मक संवाद स्थापित हो-जहां बच्चा अपनी असफलता, डर और उलझन को बिना भय के साझा कर सके। भारत में मानसिक स्वास्थ्य को अब भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। अधिकांश स्कूलों में काउंसलिंग सिस्टम या तो है ही नहीं या नाममात्र का है। बच्चों को यह सिखाया ही नहीं जाता कि 'तनाव से कैसे निपटें', 'असफलता को कैसे स्वीकारें' या 'भावनाओं को कैसे व्यक्त करें।' जिन्हें हम 'टॉपर' कहते हैं, वे अक्सर भीतर से टूटे हुए होते हैं। आत्महत्या करने वाले बच्चों के पीछे अक्सर यह मनोवैज्ञानिक सत्य होता है कि उन्होंने कभी किसी से अपनी व्यथा कही ही नहीं। शिक्षा को केवल सूचना-प्राप्ति का माध्यम नहीं, जीवन-समझ का साधन बनाना होगा। जब तक बच्चों को यह नहीं सिखाया जाएगा कि जीवन अंक-पत्र से बड़ा है, तब तक यह संकट बना रहेगा। विद्यालयों में ध्यान, योग, संवाद, कला, संगीत और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए। सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, संवेदना-केंद्रित संस्कृति गढ़नी होगी।

देश में मोटी पगार वाली नौकरियों की गलाकाट स्पर्धा में शिक्षण संस्थाएं व शिक्षक उस दायित्व को भूल गए हैं, जो छात्रों को विषयगत शिक्षा के साथ विषम परिस्थितियों के बीच जीवन जीने की कला सिखा सके। उन्हें व्यावहारिक जीवन का कौशल सिखाने के साथ ही चुनौतियों से जूझने की मानसिक शक्ति विकसित करने के लिए तैयार कर सकें। आखिर किसी परिवार की उम्मीद को किस स्थिति में यह सोचना पड़ता है कि मौत को गले लगाना अंतिम विकल्प है? शिक्षा परिसरों में ऐसी स्थितियां क्यों विकसित हो रही हैं कि विद्यार्थी जीवन से हार मानने लगे हैं? निःसंदेह, शिक्षण संस्थानों का एक मात्र लक्ष्य किताबी ज्ञान देकर डिग्री बांटने तक ही नहीं हो सकता। यह प्रश्न अब टालने योग्य नहीं रहा कि क्या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या उन्हें धीरे-धीरे तोड़ रहे हैं? शिक्षा यदि आत्महत्या का कारण बन जाए, तो उससे बड़ा विडंबनापूर्ण पराजय कोई नहीं। जरूरत है ऐसी शिक्षा की जो बच्चों को जीवन से प्रेम करना सिखाए, न कि जीवन से भागना। महर्षि अरविंद ने कहा था-'सच्ची शिक्षा वह है जो भीतर की दिव्यता को प्रकट करे।' समय आ गया है कि हम शिक्षा की दिशा को पुनर्परिभाषित करें, जहाँ परीक्षा नहीं, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हो; रैंक नहीं, रचनात्मकता का मूल्य हो, और सफलता नहीं, संतुलन एवं सुख शिक्षा का लक्ष्य बने। यदि हम यह नहीं कर पाए, तो आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा 14,000 से बढ़कर, हमारी सामूहिक संवेदनहीनता की जीवित कब्र बन जाएगा। निःसंदेह, देश के स्कूली छात्रों में आत्मघात की प्रवृत्ति राष्ट्र की गंभीर क्षति है, जिसे संवेदनशील ढंग से दूर करने की तत्काल जरूरत है।

प्रोपर्टी

दैनिक बिज़नेस रेमेडीज
व्यापार एवं विकास की आवाज

सत्ताधिकारी मुद्रक व प्रकाशक पुनीत जैन द्वारा सीटी-01 वैदिक अपार्टमेंट्स, कापसहेड़ा, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं आदित्य ग्राफिक्स इंक, प्रताप भवन, 5 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से मुद्रित।

संपादक : पुनीत जैन
(पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी)
मो. 9929106227
ई-मेल: remediesbusiness@gmail.com

डिसक्लेमर

बिज़नेस रेमेडीज़ का उद्देश्य अपने पाठकों को व्यापार और विकास से जुड़ी सटीक, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी प्रदान करना है। हम प्रकाशित सामग्री की विश्वसनीयता बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन किसी लेख में व्यक्त विचार हमेशा संपादकीय टीम की राय से मेल नहीं खा सकते। इसलिए पाठकों से निवेदन है कि किसी भी जानकारी पर आधारित निर्णय लेते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें। प्रकाशित सामग्री के आधार पर लिए गए किसी निर्णय या कार्यवाही की ज़िम्मेदारी यह प्रकाशन नहीं लेता। इस प्रकाशन में दिखाए गए सभी विज्ञापन पूरी तरह से संपादकीय सामग्री से स्वतंत्र होते हैं। विज्ञापनों में किए गए दावों या दी गई जानकारी की पुष्टि या समर्थन बिज़नेस रेमेडीज़ द्वारा नहीं किया जाता। विज्ञापन से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत की पूरी ज़िम्मेदारी संबंधित विज्ञापनदाता की होगी। यहां प्रकाशित सभी लेख, रिपोर्ट और सामग्री चाहे वे स्टाफ लेखक, समाचार एजेंसियों या अतिथि लेखकों द्वारा दी गई हो, बिज़नेस रेमेडीज़ की बौद्धिक संपदा हैं। बिना पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी सामग्री का दोबारा प्रकाशन, वितरण या प्रसारण करना कानूनन वर्जित है।

भारत के रियल एस्टेट सेक्टर का आकार 2047 तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान: रिपोर्ट

गुरुग्राम/आईएएनएस। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर का आकार 2047 तक 5-10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि फिलहाल करीब 0.3 ट्रिलियन डॉलर है। यह जानकारी गुरुवार को जारी कोलियर्स-सीआईआई की एक रिपोर्ट में दी गई।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इस क्षेत्र का योगदान 2047 तक देश की जीडीपी में 14-20 प्रतिशत तक होगा और यह देश के विकास के आधार के रूप में काम करेगा।

'रियल एस्टेट@2047: भारत के भविष्य के विकास गलियारों का निर्माण शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में छोटी अवधि के रुझानों और मुख्य क्षेत्रों जैसे आवासीय, कार्यालय, खुदरा, औद्योगिक और वेयरहाउसिंग के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास, को-लीविंग और डेटा सेंटर्स जैसे उभरते अल्टरनेटिव

एसेट क्लास के बारे में बताया गया है।

इनमें से अधिकतर रुझानों को सरकार द्वारा संचालित सुधार और नीतिगत पहलों और तेज शहरीकरण, जनसांख्यिकीय बदलाव, इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि और तकनीकी संचालित इनोवेशनों से सपोर्ट मिल रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ये विकास इंजन मिलकर एक गुणक प्रभाव पैदा कर रहे हैं, रियल एस्टेट एसेट्स सेगमेंट में रोजगार और मांग को बढ़ावा दे रहे हैं, संस्थागत पूंजी को आकर्षित कर रहे हैं और देश भर में विकास के नए रास्ते खोल रहे हैं।

रियल एस्टेट में तेज शहरीकरण और बदलती जनसांख्यिकी का सबसे अधिक असर आवासीय क्षेत्र पर पड़ने की उम्मीद है। वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर-आधारित कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण से लाभ होगा, जो टियर II और III शहरों में ऑफिस सेंटर्स और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकेंद्रीकरण का समर्थन करेगा। सीआईआई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की उप सचिव, हरलीन कौर ने कहा कि भारत का इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार रियल एस्टेट परिदृश्य को नया रूप दे रहा है, नए विकास गलियारों को खोल रहा है और टियर II और III शहरों का कायाकल्प कर रहा है। रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो एक-दूसरे को मजबूत करने का काम करते हैं। एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारे कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाएंगे और यह शहरी विकास को गति देंगे और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य आर्थिक हॉटस्पॉट का निर्माण करेंगे।

सदस्यता कूपन

(केवल डाक या ई-मेल से प्राप्त करने के लिए)

अवधि	अंक	सदस्यता शुल्क
1 वर्ष	358	1050

E-mail
remediesbusiness@gmail.com

नामः ....
पताः ....
..........पिनकोड..........
फोनः.......... मो. ....
ड्राफ्ट/चैक का विवरणः ....
ई-मेलः ....

बिजनेस रेमेडीज प्राप्त करने के लिए सदस्यता शुल्क बैंक अकाउंट में जमा कराये या सदस्यता फार्म भरकर चैक/डीडी के साथ कार्यालय पर भिजवायें।
Bank Account:- Business Remedies
A/c No. 61233949765 Bank Name: SBI

पताः- सीटी-01 वैदिक अपार्टमेंट्स,कापसहेड़ा, नई दिल्ली
फोनः- 9166611333, 9929106227

#साधारण डाक द्वारा बिजनेस रेमेडीज की डिलीवरी में अनियमितता होने पर बिजनेस रेमेडीज प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा।

ब्रुकफील्ड रीट खरीदेगी 13,125 करोड़ रुपये की ऑफिस संपत्ति, रीट का बढ़ रहा आधार

बिजनेस रेमेडीज़/नई दिल्ली। ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट (रीट) ने बेंगलूरु में एक कार्यालय परिसर इकोवर्ल्ड का 13,125 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करने के लिए करार किया है। जेएलएल के पूंजी बाजार प्रमुख (उत्तर एवं पश्चिम भारत) निशांत काबरा ने बताया कि 'यह सौदा भारत के रीट इकोसिस्टम की बढ़ती परिपक्वता को रेखांकित करता है। रीट आज सक्रिय रूप से पूंजी लगा रहे हैं और परिसंपत्ति अधिग्रहण में मजबूत प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो वाणिज्यिक अचल संपत्ति में संस्थागत भागीदारी की बढ़ती दिलचस्पी का संकेत है।'

भारत के प्रमुख कार्यालय बाजार बेंगलूरु के सबसे व्यस्त इलाके में 48 एकड़ में बना इकोवर्ल्ड का परिसर आउटर रिंग रोड पर 77 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। ब्रुकफील्ड के निदेशक मंडल ने अधिग्रहण के लिए 3,500 करोड़ रुपये की नई ऋण प्रतिभूतियां करने, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में तरजीही निर्गम से 1,000 करोड़ रुपये की नकद आय और 2,500 करोड़ रुपये की नई इक्विटी जारी करने से प्राप्त रकम का उपयोग करने का प्रस्ताव किया है।

एनारॉक समूह के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि 'ब्रुकफील्ड द्वारा बेंगलूरु में 77 लाख वर्ग फुट के इकोवर्ल्ड ऑफिस परियोजना को 13,125 करोड़ रुपये में खरीदना भारत में अब तक की सबसे बड़ी कार्यालय अचल संपत्ति की बिक्री है। इस तरह ब्रुकफील्ड का सौदा भारतीय अचल संपत्ति के इतिहास में एक ही जगह कार्यालय संपत्ति खरीद का नया रिकॉर्ड है।

इस तरह के अन्य बड़े सौदों में 2016 में 12,000 करोड़ रुपये काडीएलएफ-ब्लैकस्टोन मुंबई भूमि सौदा और 2018 में प्रेस्टीज ग्रुप की कार्यालय परिसंपत्तियों में ब्लैकस्टोन का 7,200 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

ब्रुकफील्ड इंडिया रीट के मुख्य कार्याधिकारी और प्रबंध निदेशक आलोक अग्रवाल ने कहा कि इस अधिग्रहण से भारत के प्रमुख कार्यालय बाजारों में से एक में हमारा प्रवेश होगा और हमारे रीट का आकार 30 फीसदी तक बढ़ जाएगा। सही मायने में यह हमें अखिल भारतीय मंच के रूप में स्थापित करेगा। पट्टा गतिविधियों में तेजी के साथ हमारी अंतर्निहित वृद्धि की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं जिससे हम अपने यूनिटधारकों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

यह सौदा सकल परिसंपत्ति मूल्य के 6.5 फीसदी छूट पर किया गया है और इससे शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य में 1.7 फीसदी वृद्धि होने और यूनिटधारकों को प्रति यूनिट वितरण 3 फीसदी होने की उम्मीद है।

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ब्रुकफील्ड इंडिया रीट ने यूनिटधारकों को प्रति यूनिट 10.5 रुपये वितरित करने की घोषणा की है जो पिछले साल की समान अवधि से 15.38 फीसदी अधिक है।

ब्रुकफील्ड ने बताया कि यह परिसंपत्ति ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) से जुड़ी विभिन्न कंपनियों को किराये पर दी गई है। इन कंपनियों में हनीवेल, मॉर्गन स्टैनली, स्टेट स्ट्रीट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, शेल, केपीएमजी, डेलॉयट और कैडेंस आदि शामिल हैं।

इस सौदे से ब्रुकफील्ड इंडिया रीट के वितरण प्रोफाइल का नए सिरे से मूल्यांकन होगा और निकट भविष्य में लाभांश 16 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी होने की उम्मीद है। इससे यह व्यापक रूप से यूनिटधारकों के लिए आकर्षक बन जाएगा।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

संपादकीय

अमृतवर्षा संपादकीय

जेएनयू छात्र संघ चुनाव

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों में वामपंथी गठबंधन ने चारों सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया है। इसके साथ एक रिकार्ड भी बना है। छात्र संघ के सैंट्रल पैनल पर तीन लड़कियों का कब्जा हुआ है। सैंट्रल पैनल के चार में से तीन पदों पर छात्राओं ने जीत हासिल की है। चुनावों में लेफ्ट छात्र दल गठबंधन बनाकर मैदान में था जिसके तहत आईसा, एसएफआई, डीएसएफ ने महागठबंधन बनाया था। आईसा की अदिति मिश्रा ने अध्यक्ष पद पर, एसएफआई की गोपिका ने उपाध्यक्ष पद पर, डीएसएफ से सुनील ने महासचिव पद पर और आईसा से दानिश अली संयुक्त सचिव पद पर चुनाव जीते हैं। इन चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जेएनयू के चुनाव देशभर में चर्चा का विषय रहते हैं। पूरे देश में जब वामपंथी विचारधारा सिमट कर रह गई है लेकिन जेएनयू का राजनीतिक माहौल एक बार फिर लाल रंग में रंग गया है। चुनाव परिणामों से साफ हो गया है कि जेएनयू परिसर में लेफ्ट का दबदबा सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि उसकी मौजूदगी अभी भी मजबूत है। जेएनयू की अकादमिक और राजनीतिक चेतना की कहानी में सबसे बड़ा प्रतीक यह है कि यूनिवर्सिटी की राजनीति सिर्फ वोट तक सीमित नहीं यह हर बहस में और हर उस छात्र में जीवित है जो सवाल पूछने की हिम्मत करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि जेएनयू में चुनाव हमेशा मुद्दा आधारित राजनीति पर केन्द्रित रहे न कि राष्ट्रीय पार्टियों की छवि पर। 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जेएनयू की स्थापना इस विचार के साथ करवाई थी कि भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जहां रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील लोकतांत्रिक बहस को जगह मिले। इंदिरा गांधी ने विश्वविद्यालय का नाम जवाहर लाल नेहरू के नाम पर रखा लेकिन आज तक वहां कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष पद जीत पाई। इसमें कोई संदेह नहीं कि जेएनयू में लेफ्ट के बाद भाजपा समर्थित एबीवीपी तीसरे विकल्प के रूप में संघर्ष करती रही और उसने अपनी जगह भी बनाई। 2014 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते ध्रुवीकरण का असर जेएनयू परिसर पर भी पड़ा और एबीवीपी ने अपना प्रभाव बढ़ाया। विद्यार्थी परिषद ने 26 काउंसलर सीटों में से कई सीटों पर शानदार जीत हासिल की और कई संकायों में क्लीन स्वीप भी किया। पिछले वर्ष विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू छात्र संघ के सैंट्रल पैनल में संयुक्त संचिव का पद जीतकर वापसी की थी। 2015 में एबीवीपी ने आखिरी बार यह पद जीता था। वामपंथी गठबंधन ने संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारों पर चुनाव लड़ा, जबकि एबीवीपी ने राष्ट्रवाद, विकास और कैंपस में अनुशासन पर जोर दिया। अन्य मुद्दों में आम बजट में बढ़ौतरी, लाइब्रेरी में विस्तार और राजनीतिक स्वतंत्रता आदि शामिल हैं। यह वास्तविकता है कि इस संस्थान के छात्रों ने बहस और क्रांतिकारी सोच के जरिए जेएनयू का नाम दुनियाभर में किया है। लेफ्ट संगठनों की कैंपस में गहरी जमीनी पकड़ रही और छात्र हितों के लिए?आंदोलनकारी उपस्थिति ने लेफ्ट का प्रभाव बनाए रखा। जेएनयू कई मामलों में विवादित भी रहा। वर्ष 2015 में तत्कालीन जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी आयोजित करने का आरोप लगा। कन्हैया कुमार और उसकी साथी शहला राशिद पर देशद्रोह का मुकद्दमा दर्ज किया गया। जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद पर भी विवादित नारे लगाने के आरोप लगे। उमर खालिद पर 2020 के दिल्ली दंगे भड़काने का भी मुकद्दमा चल रहा है और वह पिछले 5 साल से जेल में बंद है। भारत तेरे टुकड़े होंगे लेके रहेंगे आजादी जैसे नारों के लिए भी जेएनयू विवादित रहा। जेएनयू छात्र संघ चुनावों का एक और आकर्षण पूरे देश में सबसे सस्ती शिक्षा जेएनयू में ही उपलब्ध है। देशभर के छात्र-छात्राओं का जेएनयू में पढ़ने का सपना होता है। जेएनयू में उनको पढ़ाई के साथ-साथ विचारधाराओं को समझना और उनको अपनाकर राजनीति करने का भी मौका मिलता है। इसलिए जेएनयू का चुनाव देशभर में चर्चा का विषय रहता है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के देशभर में चर्चा में रहने का एक और प्रमुख कारण यह है कि जेएनयू को वामपंथ का गढ़ माना जाता है और वामपंथी विचारधारा अब गिने चुने राज्यों में ही है। इसके अलावा जेएनयू इस विचारधारा के प्रचार प्रसार का मुख्य अड्डा है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में प्रचार का तारीका भी अलग ही होता है। सभी वामपंथी छात्र संगठन ढपली की थाप पर गाते-बजाते हुए चुनाव प्रचार करते हैं। यह भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है। प्रेसीडेंशियल डिबेट होती है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की तरह उम्मीदवार छात्रों के आगे अपना विजन रखते हैं। इस बार का चुनाव भी वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा पर केन्द्रित रहा। खास बात यह है कि छात्र संघ चुनावों का संचालन छात्र ही करते हैं। विचारधारा की लड़ाई में वामपंथ आगे रहा। इतिहास को देखें तो जेएनयू छात्र संघ से बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेता निकले हैं। इनमें से प्रमुख रूप से सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, डी. राजा, एनी राजा, योगेन्द्र यादव, देवी प्रसाद त्रिपाठी और कन्हैया कुमार के नाम शामिल हैं। वर्ष 2019 में सीपीआई से और पिछले साल कांग्रेस से कन्हैया कुमार ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा है, लेकिन जीत नहीं मिली। इनके अलावा विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सुब्रह्मण्यम स्वामी भी जेएनयू के ही छात्र रहे हैं। हालांकि, इन लोगों ने छात्र संघ चुनाव में भाग नहीं लिया।

संस्थापक संपादकः स्व. पारसनाथ तिवारी
स्वत्वाधिकारी एवं प्रकाशक रीता तिवारी,मुद्रक कुंज बिहारी के द्वारा आर डी प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लि., प्लॉट नं- सी 16-17 पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना-800013 से मुद्रित व B-14 जगत भवानी अपार्टमेंट, एसपी सिन्हा लेन, बोरिंग कैनाल रोड, पटना-1 से प्रकाशित
संपादक-बन बिहारी
दूरभाष - 9905463571, 8757425017, धनबाद कार्यालयः मास्टर पाड़ा जे.सी. मल्लिक रोड, हीरापुर, धनबाद दूरभाष - 2204991, दिल्ली कार्यालयः बी-49, जैन मंदिर गली, शकरपुर मेन मार्केट, दिल्ली-110092, फोन नं.- 011-22055208, आर.एन.आई नं. 44420/87
ईमेलः amritvarshanews2015@gmail.com

अब असली सवाल है 'वोट चोरी' की जांच कौन करेगा?

जब कथित तौर पर 'वोट चोरी' की गई थी, तब वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पद पर नहीं थे। फिर भी, वह 'वोट चोरी' में कथित रूप से शामिल सभी अधिकारियों और राजनीतिक व्यक्तियों का बचाव करते रहे हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनसे अपने खुलासे की पुष्टि करने और शपथ पर सामग्री को प्रमाणित करने के लिए कहा।

डॉ. ज्ञान पाठक

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अब हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर वोट चोरी को बढ़ावा देने के लिए मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने और जोड़ने में मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। आरोपों का खंडन करना आमतौर पर किसी भी आरोपी द्वारा किया जाने वाला पहला कदम होता है। वे आमतौर पर कहते हैं कि आरोप गलत हैं। फिर भी, प्राथमिकी दर्ज की जाती है और कानून के अनुसार मामलों की जांच की जाती है। हालांकि, वर्तमान मामले में, सभी आरोपी कानूनी रूप से विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं। यह किसी भी प्राथमिकी और आरोप की जांच को रोकता है। इसके अलावा, चूंकि कथित अपराध कई वर्षों तक चला और इसमें चुनाव आयोग के कई अन्य अधिकारी और सत्तारूढ़ भाजपा के नेता शामिल थे, इसलिए 'वोट चोरी' की जांच एक जटिल मामला है और इसमें काफी समय और मेहनत लगेगी। कानूनी न्यायशास्त्र में, एक अभियुक्त अपने खिलाफ मामले की जांच नहीं कर सकता और न ही उसे करना चाहिए, तो सवाल यह है कि 'वोट चोरी' के अपराध की जांच कौन करेगा? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इससे पहले 7 अगस्त, 2025 को कर्नाटक के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में 'वोट चोरी' का पदार्फाश किया था, ताकि यह दिखाया जा सके कि इसे कैसे व्यवस्थित रूप से अंजाम दिया जाता है। बाद में, 1 सितंबर को, उन्होंने उस खुलासे को 'परमाणु बम' बताया और कहा कि वह जल्द ही एक 'हाइड्रोजन बम' गिराएंगे। उन्होंने 5 नवंबर को कथित 'हाइड्रोजन बम' भी गिरा दिया, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से संबंधित है। जब कथित तौर पर 'वोट चोरी' की गई थी, तब वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पद पर नहीं थे। फिर भी, वह 'वोट चोरी' में कथित रूप से शामिल सभी अधिकारियों और राजनीतिक व्यक्तियों का बचाव करते रहे हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनसे अपने खुलासे की पुष्टि करने और शपथ पर सामग्री को प्रमाणित करने के लिए कहा। यह 'वोट चोरी' के शिकार लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं था, जिन्होंने अपराध के कुछ सुबूत बड़ी सावधानी से इक्ा किए हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक कथित 'वोट चोरी' की जांच शुरू नहीं की है। चुनाव आयोग के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर चुनावी नतीजों को भाजपा के पक्ष में हेरफेर करने की कोशिश की जा रही है। 'वोट चोरी' मुख्य रूप से असली मतदाताओं के नाम हटाकर और बाहरी मतदाताओं को जोड़कर की जाती है। मतदाता सूची में इस हेराफेरी का पदार्फाश राहुल गांधी ने किया है। फिर भी, चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया, जिसका विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक ने विरोध किया और आरोप लगाया कि यह केवल भाजपा के पक्ष में 'वोट चोरी' के उद्देश्य से मतदाता सूची में हेराफेरी करने का प्रयास है। देश की जनता ने देखा है कि कैसे लाखों बाहरी मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि लाखों असली वोट काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग का बचाव यह है कि मतदाताओं ने निर्धारित प्रपत्रों और तरीकों से नाम हटाने या जोड़ने के खिलाफ अपील नहीं की। यह एक कमजोर बचाव है, क्योंकि हम भारतीय जानते हैं कि बहुत से लोग अपराध की रिपोर्ट करने के लिए सामने आना पसंद नहीं करते क्योंकि पुलिस और प्रशासन पीड़ितों को अपमानित करते हैं। विपक्षी राजनीतिक दलों ने नाम हटाने और जोड़ने पर आपत्ति जताई है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि ये उचित प्रपत्रों में दर्ज नहीं किए गए हैं।

यह रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों का अपमान है। यहां तक कि प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग और गृह मंत्री भी विपक्ष के नेता को नहीं बख्श रहे हैं। 'वोट चोरी' और उसके पीछे की साजिश का मुद्दा उठाने के लिए उन्हें बार-बार अपमानित किया जा रहा है। अब, दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चलाया जा रहा है, और तीसरे चरण में पूरे देश को कवर किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में, राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में 'वोट चोरी' का नया आरोप विशेष महत्व रखता है। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 'वोट चोरी' हुई थी और भारतीय चुनाव आयोग पर भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया। राहुल ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर्नाटक की महादेवपुर विधानसभा सीट की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के प्रयास के पीछे के लोगों की तकनीकी जानकारी साझा करने से इनकार करके उन लोगों को बचा रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र को 'नष्ट' कर रहे हैं। हरियाणा में, उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की मतदाता सूची में 5,21,619 से ज्यादा नकली मतदाता थे। वोट चोरी की इस प्रणाली का औद्योगिकीकरण हो गया है, और उन्हें पूरा यकीन है कि वे बिहार में ऐसा ही करेंगे। एक खास आरोप में, राहुल गांधी ने कहा कि एक मतदाता की तस्वीर दो मतदान केंद्रों पर अलग-अलग नामों से 223 बार दिखाई देती है। उन्होंने कहा, 'हरियाणा में ऐसे हजारों उदाहरण हैं।' उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही तस्वीर वाले 1,24,177 मतदाता हैं। उन्होंने आरोप लगाया, 'चुनाव आयोग जगह बनाना चाहता है। वे सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर रहे हैं। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि हरियाणा में लगभग 25 लाख मतदाता फर्जी हैं। उन्होंने एक मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) भी दिखाया है जिसमें एक ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 10 मतदान केंद्रों पर 22 बार मतदान किया है। राहुल गांधी ने इस पूरे अभियान को 'ऑपरेशन सरकार चोरी' करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 'वोट चोरी' न केवल निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। विपक्ष के नेता के आरोप गंभीर हैं और उनकी गहन जांच की आवश्यकता है। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जांच कौन करेगा? सत्तारूढ़ सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप हैं, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक याचिकाकर्ता को महादेवपुरा में राहुल गांधी द्वारा 'वोट चोरी' के खुलासे के मामले में कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग जाने को कहा है। एक नागरिक क्या कर सकता है?

पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा के बीच टकराव

पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा के बीच टकराव चल रहा है। और इस तूफान के केंद्र में असम में पार्टी के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा हैं। सरमा अपने राज्य में भावनाओं का ध्रुवीकरण करने के लिए हमेशा किसी न किसी मुद्दे की तलाश में रहते हैं। इस बार, उन्होंने बंगाली राष्ट्रवाद पर रवींद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध गीत, आमार सोनार बांग्ला को चुना है। सरमा ने असम के करीमगंज में एक सभा में यह गीत गाने के लिए एक स्थानीय कांग्रेस नेता के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कराया है। उनका तर्क हैः यह एक राष्ट्र-विरोधी गीत है क्योंकि इसे बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। हालांकि यह मुद्दा असम में गूंज सकता है, लेकिन सरमा के इस कदम ने पड़ोसी पश्चिम बंगाल में आग लगा दी है। बंगालियों के लिए, 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल के विभाजन के समय लिखा गया आमार सोनार बांग्ला, बंगाली राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है। यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान हो सकता है, लेकिन वे इसे क्षेत्रीय गौरव का गान मानते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, वह यह है कि सरमा के इस कदम से वह मतदाता वर्ग खास तौर पर नाराज है जिसे पार्टी लुभाने की कोशिश कर रही है-बंगाली मध्यम वर्ग। बंगाली भद्रलोक, जैसा कि इस वर्ग को कहा जाता है, टैगोर को एक सांस्कृतिक प्रतीक मानते हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा द्वारा इस गीत को अब्दुल चाचा का गीत कहकर उपहास करने वाले पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। विडंबना यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में कोलकाता में अपनी पहली रैली में इस गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ी थीं। यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिससे असम और पश्चिम बंगाल, दोनों जगह भाजपा नेता सकते में हैं। जोहरान ममदानी के किस्से सोशल मीडिया पर वायरल अब जबकि भारतीय-अमेरिकी जोहरान ममदानी सभी बाधाओं को पार करते हुए न्यूयॉर्क शहर के दक्षिण एशियाई मूल के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं, उनके और उनके परिवार से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक खास तौर पर प्यारी कहानी उनकी फि ल्म निमार्ता माँ मीरा नायर के इर्द-गिर्द घूमती है। यह तब हुआ जब वह अपनी माँ को अपने साथ कान्स ले गईं जहाँ उनकी फि ल्म सलाम बॉम्बे की स्क्रीनिंग हो रही थी। वहाँ मीडिया ने साड़ी पहने उस खास महिला से संपर्क किया और उनसे पूछा कि फि ल्म में उनकी क्या भूमिका है। नायर की माँ ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, मैं निर्देशक की निमार्ता हूँ। नायर ने न्यूयॉर्क में अपने बेटे जोहरान के मेयर पद के चुनाव अभियान के दौरान थोड़े बदलाव के साथ अपनी माँ की यही बात दोहराई। जब मीडिया ने उनसे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछा, तो उन्होंने गर्व से कहा, मैं उम्मीदवार की निमार्ता हूं! यह दिलचस्प है कि जोहरान ममदानी का मध्य नाम, क्वामे, नई दिल्ली के विशिष्ट राजनयिक क्षेत्र चाणक्यपुरी की एक सड़क पर अंकित है।

चुनाव 'सुधारों' से चुनावी 'रेवड़ियों' तक

भारत के चुनाव आयोग की विश्वसनीयता में जिस प्रकार का क्षरण हो रहा है वह इस देश के लोकतन्त्र के लिए अति चिन्ता का विषय है, क्योंकि पूरे विश्व के लोकतान्त्रिक देशों में हमारे चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा किसी भी सन्देह से ऊपर मानी जाती रही है। भारत की चुनाव प्रणाली का अध्यन करने दुनिया के लोकतान्त्रिक देशों से समय-समय पर सरकारी प्रतिनिधिमंडल भी आते रहे हैं। इसकी कोई एक वजह नहीं है बल्कि कई वजहें हैं जिनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि चुनाव आयोग को भारतीय संविधान में स्वतन्त्र व स्वायत्त संस्थान का दर्जा दिया गया है। हमारे संविधान निमार्ताओं ने चुनाव प्रणाली को पूरी तरह शुद्ध व पवित्र रखने की गरज से ही यह व्यवस्था की थी और चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के मामलों में कुछ न्यायायिक अधिकार भी दिये थे जिससे यह संस्था प्रत्येक राजनीतिक दल को संविधान के दायरे में काम करने के लिए विवश कर सकें। चुनाव आयोग को ही इस बात के लिए अधिकृत किया गया कि वह ऐसी चुनाव प्रणाली विकसित करे जो पूरी तरह पारदर्शी व पवित्र हो, परन्तु सत्तर का दशक आते-आते चुनाव प्रणाली में बहुत सी खामियां नजर आने लगीं जिसकी वजह से चुनाव सुधारों की मांग राजनीतिक क्षेत्रों से उठने लगी। इस मांग को प्रभावी तरीके से लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने उस दौर में उठाया और अपने जन आन्दोलन का इसे भी एक मुद्दा बनाया। 1973 में गुजरात से शुरू हुआ छात्र आन्दोलन जब 1974 में बिहार पहुंचा तो यह नागरिक आन्दोलन में तब्दील हो गया और लोगों की प्रार्थना पर इसे नेतृत्व देने के लिए स्व. जय प्रकाश नारायण उर्फ जेपी आगे आये। जेपी के नेतृत्व में जब यह आन्दोलन चलने लगा तो इसे समग्र क्रन्ति का नाम दिया गया और जेपी ने मांग की कि सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम चुनाव प्रणाली में ही आधारभूत परिवर्तन किये जाएं। जेपी के आन्दोलन के साथ धीरे-धीरे देश के सभी मुख्य धारा के विपक्षी दल जुड़ते चले गये जिनमें भारतीय जनसंघ (भाजपा) भी शामिल थी। जनसंघ के तत्कालीन नेताओं ने जेपी आन्दोलन में शामिल होते ही चुनाव प्रणाली में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जताई और स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार की जड़ महंगी चुनाव प्रणाली ही है। इस दौरान एक घटना यह हुई दिल्ली सदर सीट का लोकसभा चुनाव अवैध घोषित हो गया। 1971 के लोकसभा चुनावों में यह सीट कांग्रेस पार्टी के श्री अमरनाथ चावला ने जनसंघ के कंवर लाल गुप्ता को हरा कर जीती थी। स्व. गुप्ता ने श्री चावला के चुनाव को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती इस आधार पर दी कि उन्होंने अपने चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च राशि से अधिक धन खर्च किया है। न्यायालय में यह बात साबित हो गई और श्री चावला का चुनाव अवैध घोषित हो गया। उस समय देश की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी थी। इस फैसले के बाद श्रीमती गांधी ने भारत के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में जो संशोधन किया उससे चुनावों के खचीर्ले होने से नहीं रोका जा सकता था। इन्दिरा सरकार ने प्रावधान किया कि चुनावों में किसी भी प्रत्याशी के चुनाव पर उसका कोई मित्र या शुभ चिन्तक अथवा संस्था (राजनीतिक दल) कितना ही खर्च कर सकते हैं। ऐसा चुनावी खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्चे में शामिल नहीं किया जायेगा। इसके बाद राजनीतिक दलों को चुनावों में कितना ही खर्च करने का लाइसेंस मिल गया। जेपी ने अपने आन्दोलन में जब महंगे होते चुनावों को एक मुद्दा बनाया तो अमरनाथ चावला बनाम कंवर लाल गुप्ता का मुकद्दमा उनके सामने था। जेपी चाहते थे कि भारत में चुनाव सरकारी खर्चे से कराये जाने चाहिए जिससे चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों को पूंजीपतियों पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए उन्होंने अपने आन्दोलन के दौरान ही बम्बई उच्च न्यायालय के रिटायर मुख्य न्यायाधीश श्री वी.एम. तारकुंडे के नेतृत्व में एक समिति बनाई और उससे चुनावी खर्चों को सीमित रखने के उपाय खोजने के लिए कहा। तारकुंडे समिति ने अपनी रिपोर्ट जेपी को सौंप दी, जिसमें सुझाव दिया गया था कि सरकारी खर्च से चुनाव कराने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक चुनाव कोष स्थापित किया जाना चाहिए और प्रत्याशियों को प्रचार करने के लिए सरकारी साधन आदि सुलभ कराये जाने चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय में फिर से मंडरा रहा है बेंच हंटिंग का डर

मुख्य न्यायाधीश का आक्रोश एक आंतरिक दुविधा को भी दशार्ता है। वह है राजनीतिक टकराव की स्थिति में आए बिना संस्था को सूक्ष्म घुसपैठ से कैसे बचाया जाए। न्यायपालिका को सरकार के साथ खुले टकराव में उतरे बिना अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सावधानी से कदम उठाने चाहिए। लेकिन चुप्पी की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब पीठों को स्थानांतरित करने या उनका विस्तार करने के प्रयासों को चुनौती नहीं दी जाती।

के रवींद्रन

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई द्वारा केंद्र सरकार को 'बेंच हंटिंग' के प्रयास के लिए कड़ी फटकार लगाने से न्यायिक स्वतंत्रता और भारत के शीर्ष न्यायालय पर कार्यपालिका के प्रभाव को लेकर एक पुरानी और असहज बहस फिर से शुरू हो गई है। इसकी तात्कालिक वजह सरकार की वह मांग थी जिसमें उसने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के अंतिम चरण में पहुंच चुके एक मामले को पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ को स्थानांतरित करने की मांग की थी। समय और योजना के मद्देनजर यह कदम मुख्य न्यायाधीश को अपनी पीठ के फैसले से बचने की कोशिश के रूप में प्रतीत हुआ, जिसने उस प्रवृत्ति को और पुष्ट किया जो वर्षों से न्यायालय को परेशान करती रही है। वह है शक्तिशाली वादियों द्वारा न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास कि कौन से न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेंगे। बेंच हंटिंग, एक ऐसी प्रथा रही है जो जितनी सूक्ष्म है उतनी ही विनाशकारी भी। यह न्याय के इस मूल सिद्धांत को कमजोर करती है कि कानून को सत्ता के प्रति 'अंधा' होना चाहिए। अपने सबसे निंदनीय रूप में, यह असुविधाजनक या स्वतंत्र विचारों वाली समझी जाने वाली बेंचों को दरकिनार करने और कार्रवाई को उन बेंचों की ओर मोड़ने का प्रयास करती है जो अधिक अनुकूल समझी जाती हैं। हालांकि अदालत के गलियारों में इस बारे में लंबे समय से चर्चा होती रही है, न्यायमूर्ति गवई की टिप्पणी ने इस मामले को फिर से खुलकर सामने ला दिया है। इस बार इसके पीछे मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय का जोर है। उनके शब्द न केवल प्रक्रियात्मक पैंतरेबाजी से बल्कि एक बार-बार होने वाले पैटर्न से भी निराशा दशार्ते हैं जो न्यायपालिका की संस्थागत विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करता है। इस आदान-प्रदान का संदर्भ महत्वपूर्ण है। विचाराधीन मामला न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, एक ऐसा कानून जिसकी अर्ध-न्यायिक निकायों में नियुक्तियों और सेवा शर्तों पर कार्यपालिका को व्यापक अधिकार देने के लिए आलोचना की जाती है। पीठ इस मामले की गहन जांच कर रही है, और याचिकाकताओं द्वारा अपनी दलीलें पूरी करने के बाद सरकार के अनुरोध के समय ने लोगों को चौंका दिया। मुख्य न्यायाधीश को यह एक ऐसे नतीजे को पटरी से उतारने या विलंबित करने का प्रयास लगा जो शायद सरकार को पसंद न हो। इसलिए, उनकी प्रतिक्रिया न केवल न्यायिक स्वायत्तता का बचाव थी, बल्कि उन सीमाओं की भी याद दिलाती थी जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करती हैं। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की चिंताएं सार्वजनिक हुई हैं। इस मुद्दे ने पहली बार जनवरी 2018 में राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था जब सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ - ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा द्वारा मामलों के मनमाने आवंटन का विरोध करने के लिए एक असाधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनकी शिकायत थी कि सरकार से जुड़े मामलों को चुनिंदा रूप से 'पसंदीदा पीठों' को सौंपा जा रहा है। वह क्षण अभूतपूर्व था। इससे पहले कभी भी कार्यरत न्यायाधीशों ने सार्वजनिक रूप से अपनी ही संस्था के आंतरिक कामकाज की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया था। इसने न्यायालय के भीतर गहरी दरारों को उजागर किया। उन्होंने एक संरचनात्मक समस्या को उजागर किया जो तब से चली आ रही है- वह अस्पष्ट तरीका जिससे मुख्य न्यायाधीश, 'रोस्टर के मास्टर' के रूप में, पीठों को मामले सौंपते हैं। चेलमेश्वर प्रकरण से संरचनात्मक सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन इसने एक स्थायी चेतावनी का निशान जरूर छोड़ा। उस समय व्यक्त की गई चिंताएं आज के माहौल में भी गूंजती हैं, बस फर्क इतना है कि अब आरोप बाहरी तौर पर, सरकार पर ही, प्रक्रियागत मांगों के ड्ारिए न्यायिक प्रक्रिया में हेरफेर करने की कोशिश करने के लिए निर्देशित हैं। मुख्य न्यायाधीश गवई की हताशा इस बढ़ती धारणा को दशार्ती है कि कार्यपालिका का हस्तक्षेप अधिक परिष्कृत हो गया है, जो प्रत्यक्ष दबाव पर कम और समय खरीदने, पीठों को बदलने, या न्यायिक परिदृश्य को बीच में ही बदलने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रियात्मक युक्तियों पर अधिक निर्भर करता है। जब कार्यपालिका द्वारा बेंच हंटिंग की जाती है, तो यह न केवल एक नैतिक चूक है, बल्कि एक संवैधानिक अपमान भी है। भारत के संस्थापक चार्टर में निहित शक्तियों का पृथक्करण, सरकार की प्रत्येक शाखा द्वारा दूसरे की अधिकार-सीमाओं का सम्मान करने पर निर्भर करता है। कार्यपालिका द्वारा किसी पीठ की संरचना को प्रभावित करने का प्रयास न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भीतर से ही नष्ट करना है। ऐसा हर कदम सार्वजनिक जीवन में न्यायालय के अधिकार को बनाए रखने वाली तटस्थता की धारणा को कमजोर करता है। भले ही कोई औपचारिक कदाचार सिद्ध न हो, लेकिन हेरफेर का आभास मात्र न्याय प्रणाली में विश्वास को नुकसान पहुंचा सकता है। न्यायाधीशों को राजनीतिक या संस्थागत प्रभाव से मुक्त रखने का सिद्धांत लोकतांत्रिक वैधता के मूल में है। जब वादी, विशेष रूप से राज्य की शक्ति का प्रयोग करने वाले, अपने पसंदीदा परिणामों के अनुरूप प्रक्रियात्मक कदम उठाते देखे जाते हैं, तो यह इस बारे में संदेह पैदा करता है कि क्या न्यायालय वास्तव में कार्यपालिका की अतिरेक पर अंकुश लगाते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

ट्रम्प भारत दौरे के इच्छुक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का असामान्य व्यवहार नजर आ रहा है। उससे यह कहीं नहीं लग रहा कि वह इस दुनिया की महाशक्ति का नेतृत्व कर रहे हैं। एक तरफ वे शांति का मसीहा बनकर दुनिया में सात युद्धों को खत्म कराने के दावे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद परमाणु हथियारों के परीक्षण का ऐलान कर देते हैं। उनके भाषणों का सार परस्पर विरोधी ही निकल रहा है। प्रवासियों को खतरे के रूप में पेश करना घृणा फोबिया को बढ़ावा देना ही है, जिसे वैश्विक समुदाय को बांटने की कुत्सित कोशिश ही माना जाएगा। प्रवासियों के विरुद्ध बयानबाजी से साफ है कि ट्रम्प मानवीय मूल्यों के विरोधी हैं। टैरिफ वॉर के बीच वे लगातार अपनी बयानबाजी बदलते रहे हैं। अब ट्रम्प ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक महान व्यक्ति बताया है और कहा है कि वे दोनों देशों में व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं। ट्रम्प ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी चर्चा बहुत अच्छी चल रही है और वह मेरे दोस्त हैं और हमारी बात चलती रहती है। ट्रम्प ने भारत के संबंध में बयानबाजी की है। उसके तुरन्त बाद ही उन्होंने कोई न कोई भारत विरोधी बम फोड़ा है। पहले उन्होंने रूस से कच्चा तेल खीदने के पैनल्टी के रूप में भारत पर भारी-भरकम टैरिफ लगाया, इसका सीधा असर भारत के कारोबार पर पड़ रहा है। ट्रम्प ने फिर दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी है। ट्रम्प के भारत दौरा करने का बयान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत पर टैरिफ लगाए जाने के फैसले के बाद ट्रम्प क्वॉड शिखर सम्मेलन के लिए भारत नहीं जाएंगे। अब सवाल उठने लगे हैं कि ट्रम्प भारत क्यों आ रहे हैं। इसका बड़ा कारण यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी शर्तों के आगे झुकने से साफ इंकार कर दिया और व्यापार वार्ता की मेज पर भारत कठिन वार्ताकार साबित हुआ है।

> **ट्रम्प के भारत दौरा करने का बयान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत पर टैरिफ लगाए जाने के फैसले के बाद ट्रम्प क्वॉड शिखर सम्मेलन के लिए भारत नहीं जाएंगे। अब सवाल उठने लगे हैं कि ट्रम्प भारत क्यों आ रहे हैं। इसका बड़ा कारण यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी शर्तों के आगे झुकने से साफ इंकार कर दिया और व्यापार वार्ता की मेज पर भारत कठिन वार्ताकार साबित हुआ है। भारत एक निष्पक्ष और संतुलित समझौते के लिए बातचीत कर रहा है।**

भारत एक निष्पक्ष और संतुलित समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। भारत का स्टैंड स्पष्ट है कि वह कोई ऐसा व्यापार समझौता नहीं करेंगे जिससे भारतीयों के हित प्रभावित होते हैं। ट्रम्प द्वारा मोदी की व्यक्तिगत तारीफ यह बताती है कि अमेरिका भारत की अहमियत को समझने लगा है। ट्रम्प को अपने ही देश में अनेक मोर्चों पर झटके लग रहे हैं। ट्रम्प ने जिस अंदाज में ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं उन्हें लेकर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात राजनीतिक की करते हैं जो सबसे ताजा मामला है। न्यूयॉर्क में हुए मेयर पद के चुनाव में जोहरान ममदानी ने जीत हासिल की है। ममदानी की जीत इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद विरोध करते हुए ममदानी के पक्ष में लोगों से वोट ना करने की अपील की थी। ट्रम्प ने तो यहां तक कहा था कि अगर ममदानी जीत गए तो वो फेडरेल फंडिंग रोक देंगे। अब जब ममदानी ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया है तो यह सियासी रूप में ट्रम्प के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वोटरों ने बता दिया है कि अमेरिका में भविष्य की राजनीति किस ओर करवट ले रही है।

न्यूयॉर्क में मिली सियासी हार से इतर बात करें तो अमेरिका इस वक्त बड़े संकट में घिरा नजर आ रहा है जिसका असर सबसे अधिक आम लोगों पर पड़ रहा है। अमेरिका में पिछले एक महीने से शटडाउन जारी है और राष्ट्रपति ट्रम्प इससे पूरी तरह बेपरवाह नजर आ रहे हैं। अमेरिका में जारी शटडाउन के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ा बयान दिया है। ट्रम्प ने कहा है कि वो सरकारी विभागों में कामकाज को दोबारा चालू करने के लिए डेमोक्रेट्स के दबाव में नहीं आएंगे। ट्रम्प ने साफ कर दिया है कि सरकारी 'शटडाउन' (सरकारी कामकाज के लिए वित्तपोषण की कमी) के जल्द ही छठा सप्ताह शुरू होने के बावजूद उनकी वार्ता करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि डेमोक्रेट नेता रिपब्लिकन नेताओं के सामने अंत में झुक जाएंगे। साफ है कि ट्रम्प ने इसे नाक की लड़ाई बना ली है और भुगतना लोगों को पड़ा रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में भी उन्हें विफलता ही हाथ लगी है। ट्रम्प द्वारा दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने को भी अदालतों में चुनौती दी जाने लगी है। अमेरिकी महसूस करते हैं कि सत्ता का संचालन अधिक केन्द्रीकृत हो चुका है और एजैंसियों को कमजोर किया जा रहा है। ट्रम्प मनमाने फैसले ले रहे हैं। लोकप्रियता का ग्राफ गिरने के बाद ट्रम्प ने अपनी नीतियों में जल्दी-जल्दी बदलाव किया है। पहले उन्होंने चीन के प्रति नरम रुख अपनाते हुए समझौते कर लिए। इसका बड़ा कारण यह भी था कि चीन से रेयर अर्थ नहीं मिलने के कारण अमेरिका खुद प्रभावित हो रहा था। ट्रम्प को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि उनकी एक तरफ मनमानी को दुनिया स्वीकार करने को तैयार नहीं है। टैरिफ वॉर से पैदा हुई व्यापार अस्थिरता से अंततः अमेरिका को ही नुक्सान हो रहा है।

भारत को यह बात भी नपसंद है कि एक तरफ ट्रम्प दोनों विशाल लोकतंत्रों के बीच व्यापार वार्ता के सुखद परिणामों की उम्मीद जताते हैं और वहीं पाकिस्तान और भारत को एक ही पाले में रखते हैं। ट्रम्प भारत-पाकिस्तान में युद्ध रुकवाने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर की तारीफ करते नहीं थकते। उनके रोज-रोज के बयानों से दुनिया के नेताओं ने उन्हें गम्भीरता से लेना बंद कर दिया है। कूटनीति में बयानों में लचीलापन अच्छा होता है लेकिन ट्रम्प अस्थिर मानसिकता वाले नेता के रूप में अपनी छवि बना चुके हैं। खुद को भारत का अच्छा दोस्त बताने वाले ट्रम्प भारत आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। वह यह भी जानते हैं कि चीन के प्रति नरम रुख अपनाकर भारत को नजरंदाज करना उनके लिए मुश्किल होगा। बेहतर है कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौता संतुलित तरीके से सम्पन्न हो और टैरिफ का तनाव खत्म हो।

जीत का सेहरा...

गीता पाढा

"सुधार से चुनाव बाजार तक आते देखे,
योजनाओं के नाम पर नेता भोली जनता को बेवकूफ बनाते देखे,
देश में तरह-तरह के तकनीकी परिवर्तन आते देखे,
और बाहुबली लोग अंधाधुंध पैसे के बल पर जीत का सेहरा सजाते देखे...।"

किस ओर जा रहा है बिहार चुनाव?

मिर्च मसाला
त्रिदीब रमण
gossipguru.in

'देखो कैसे तेरी बस्ती में ही अब तेरी चमक कितनी कम होने लगी है
कभी तुझसे रौशन था सूरज, आज तेरे चेहरे की चमक कम होने लगी है'

बिहार के पहले चरण की बंपर वोटिंग (65फीसदी) को पक्ष व प्रतिपक्ष गठबंधन अपने-अपने हिस्से की जीत बता रहा है। एनडीए के प्रभाव क्षेत्र माने जाने वाले पहले चरण के मतदान में मतदाताओं के जबर्दस्त उत्साह को देखते हुए महागठबंधन की बांछें खिली हुई हैं, वे इस अप्रत्याशित वोट प्रतिशत को व्यवस्था परिवर्तनकारी वोटों में शुमार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा नीत गठबंधन इसे वोटरों का अपने पक्ष में कदमताल बता रहा है। भाजपा का दावा है कि इस दफे वह बड़ी संख्या में अप्रवासी बिहारियों को वोट डालने के लिए बिहार लाने में कामयाब रही है, इस कार्य में भाजपा व संघ के नेता पिछले साल भर से मेहनत कर रहे थे, वहीं इस दफे 'एसआईआर' के तहत भले ही 70 लाख वोटरों के नाम कट गए हों, पर मतदान के रोज महिला व युवा मतदाताओं के उत्साह अलग ही कहानी बयां कर रहे थे, महागठबंधन युवा वोटरों के कदमताल को अपने पक्ष में मान रहा है तो एनडीए गठबंधन का कहना है कि 'महिला वोटर खुल कर नीतीश के समर्थन में बाहर आई हैं।' एक रिपोर्ट में पहले चरण के मतदान में कड़ी टक्कर बताई है और एडवांटेज एनडीए बताया है, पर इसके आंकड़े भी बता रहे हैं कि महागठबंधन 2020 के मुकाबले इस बार इस पहले फेज में शानदार वापसी कर रहा है। यह भी इशारे मिल रहे हैं कि भाजपा व एनडीए के कई हैवीवेट नेताओं का चुनाव इस बार थोड़ा फंस गया है, जो नेतागण कड़ी टक्कर में फंस गए हैं वे हैं-रामकृपाल यादव, विजय सिन्हा, विजय चौधरी, संजय सरावगी, मंगल पांडेय। वहीं सम्राट चौधरी को उनके कई अपनों से ही भीतरघात का सामना करना पड़ रहा है। लालू यादव का 'एमवाई' (मुस्लिम-यादव) समीकरण इस चुनाव में पूरी तरह एकजुट दिखा, इन दोनों को मिला कर बिहार में इसके 33 फीसदी के आसपास वोट शेयर हैं, अगर तेजस्वी यादव अपने इस परंपरागत वोट बैंक में कुछ अन्य जातियों को जोड़ने में कामयाब रहते हैं तो इस बार के चुनाव में लालटेन की चमक विरोधियों की आंखें चौंधिया सकती है। पीके की जनसुराज को लेकर जितना शोर-शराबा था वह उस कदर वोट में तब्दील होता नहीं दिखा। बिहार चुनाव की पूर्व बेला में हरियाणा चुनाव में कथित वोट चोरी को लेकर राहुल के खुलासे ने युवा व 'ज़ेनज़ी' पीढ़ी को वाज् आंदोलित किया, अब यह व्यवस्था विरोधी वोटों में कितना तब्दील हो पाया इसका पता तो 14 नवंबर को ही चल पाएगा।

क्या गेम चेंजर साबित होगा यह प्लॉन?

शह-मात की सियासी बिसात पर पीएम मोदी को अपने हर प्यादे की उपयोगिता, आक्रामकता व उनकी सामयिकता का बखूबी अंदाजा है। सो, जैसे ही उन्हें लगा कि बिहार की चुनावी हवा कोई और पैंतरा बदल सकती है, उन्होंने झट से वहां की पूरी चुनावी कमान अपने हाथों में थाम ली। जो नीतीश कुमार भगवा रणनीति में धीरे-धीरे किनारे कर दिए गए थे, उन्हें मुख्य रंगमंच पर अवतरित कराया गया। जिन इलाकों में जहां बड़े-बड़े चमकदार भाजपा नेताओं के पोस्टर लगे थे, वहां रातों-रात नीतीश के पोस्टर लगा दिए गए।

लल्लन को उनके मोकामा में दिए गए बयानों के लिए उन्हें प्रतिनायक साबित करने की होड़ मच गई। भाजपा ने इस नैरेटिव को भी सिरे से नकारने के प्रयास किए कि ऊंची जातियों के नेता ही उनकी स्वभाविक पसंद है। भाजपा को बखूबी इस बात का इल्म हो गया था कि खुद को एनडीए का सीएम फेस घोषित नहीं किए जाने से नीतीश बेतरह कुपित हैं, उन्होंने जाने-अनजाने जदयू कैडर में भी यह संदेशा दे दिया है कि 'अगर इस दफे राज्य में एनडीए बहुमत में आ भी जाएगा तो भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी', पीएम मोदी ने समय रहते इस बात को भांप लिया था और वे रातों-रात इसके निदान में जुट गए।

घटक दलों की ठसक से परेशान भाजपा

भाजपा को बिहार चुनाव में कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है, वह अपने गठबंधन साथियों की समय-असमय बेजा मांगों से भी परेशान है। सूत्रों की मानें तो पहले फेज के चुनाव से पहले जब भाजपा के एक बड़े नेता पटना में एक प्रेस कांफ्रेंस करने वाले थे तो उनके एक घटक दल के मुखिया उनसे पटना मिलने आ पहुंचे। उस नेता जी ने भाजपा के बड़े नेता से गुहार लगाई कि 'अब चूंकि चुनाव सिर पर है और उनका चुनाव फंड लगभग खत्म हो चुका है तो उन्हें प्रति निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाने के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाए।' इस पर बड़े नेता बेतरह भड़क गए बोले-'अब भी आपका ध्यान चुनाव बनाने की जगह, पैसा बनाने पर है, मैं आपको अपना सर्वे दिखाता हूं, आपके 6 में से 5 उम्मीदवार तो अभी ठीक से लड़ाई में भी नहीं आ पाए हैं, मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप जाओ, गांव-गांव घूमो और पूरी तरह चुनाव में लग जाओ, अपने उम्मीदवारों से भी कहें कि वे और मेहनत करें, हमारे लिए इस बार एक-एक सीट बहुत इंपोंटेंट हैं।' नेता जी उल्टे पैर घर को लौट आए।

...और अंत में

बिहार चुनाव में महागठबंधन की नज़र लगातार लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के पासवान वोटरों पर टिकी है, महागठबंधन इसमें डेंट लगाना चाहता है। यही सोचकर दरभंगा में एक-दूसरे के खिलाफ रणनीतियां बनीं। कहते हैं महागठबंधन को अपने इस पहल का फौरी लाभ मिला, एक अनुमान के अनुसार पहले चरण के मतदान में अकेले दरभंगा में लगभग 35 फीसदी पासवान वोटरों ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के पक्ष में वोट किया। इस बार भाजपा ने चिराग पासवान की पार्टी के लिए 29 सीटें छोड़ी है, पर माना जाता है कि इस दफे के चुनाव में चिराग की पार्टी के लिए जीत की दहाई का आंकड़ा छू पाना कतई आसान नहीं होगा।

एनटीआई

'नक्शा' आपकी भूमि की डिजिटल पहचान

शिवराज चौहान
केन्द्रीय ग्रामीण विकास और किसान कल्याणमंत्री

जब भारत एक समावेशी और विकसित भविष्य की कल्पना करता है, तो इसका सबसे मज़बूत आधार-स्तंभ भूमि है। चाहे घर हो, खेत हो, दुकान हो या स्मार्ट सिटी का सपना हो- विकास का प्रत्येक रूप भूमि पर अवस्थित होता है। हालांकि, सच्चाई यह है कि वर्षों से हमारे भू-अभिलेख अधूरे, भ्रामक और अक्सर विवादों में उलझे रहे हैं। परिणामस्वरूप, आम नागरिकों को संपत्ति खरीदने, ज़मीन विरासत में प्राप्त करने, ऋण प्राप्त करने या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

इन दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग ने "नक्शा" (राष्ट्रीय शहरी निवास-स्थल भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण) कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह भारत में भूमि प्रबंधन, प्रशासन और भूमि-रिकॉर्ड रख-रखाव में बदलाव लाने की एक पहल है। यह कार्यक्रम एक पारदर्शी, डिजिटल और सत्यापित भू-अभिलेख प्रणाली का निर्माण कर रहा है, जो न केवल नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगी, बल्कि कस्बों और शहरों के विकास को भी गति प्रदान करेगी। भारत में, भूमि पंजीकरण लंबे समय से एक जटिल व दस्तावेज-आधारित प्रक्रिया रही है। बिक्री विलेख, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, पटवारी सत्यापन और तहसील स्तर पर प्रस्तुतियां– ये सभी नागरिकों के लिए पूरी प्रणाली को बोझिल बना देती थीं। पुराने रजिस्टर और फाइलों में न केवल त्रुटियां मौजूद थीं, यही कारण है कि लाखों भारतीयों के लिए, सुरक्षा के स्रोत के रूप में भूमि का महत्त्व कम होता गया और यह जोखिम का प्रमुख स्रोत बन गई। नक्शा कार्यक्रम, सटीक और डिजिटल भू-रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण, जीएनएसएस मानचित्रण और जीआईएस उपकरण जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाता है। इस पहल के तहत, नागरिकों को 'योरप्रो' (शहरी संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड) कार्ड मिलता है, जो स्वामित्व का एक डिजिटल प्रमाण है और संपत्ति के लेन-देन को आसान बनाता है। सरकार 'योरप्रो' कार्यक्रम को समर्थन दे रही है। नक्शा के साथ, लोगों को अब स्वामित्व की पुष्टि के लिए दस्तावेजों या बिचौलियों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। नागरिक आसानी से ऑनलाइन प्रारूप मानचित्र देख सकते हैं और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। यह डिजिटल प्रणाली कराधान को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाती है।

नक्शा कार्यक्रम का प्रभाव व्यक्तिगत स्वामित्व और प्रशासनिक दक्षता से कहीं आगे तक फैला हुआ है और यह आपदा प्रबंधन और शहरी नीति-निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर रहा है। सत्यापित डिजिटल स्वामित्व रिकॉर्ड यह भी सुनिश्चित करते हैं कि मुआवजा और सहायता सही लाभार्थियों तक शीघ्रता से पहुँचे। इससे आपदा के बाद, पूर्वस्थिति को बहाल करने की प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाती है। इसके अलावा, नक्शा संतुलित और सतत अवसंरचना विकास को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक शहरी सुदृढ़ता का समर्थन करता है।

भारतीय इतिहास में, भूमि विवादों ने अक्सर असमानता, संघर्ष और विलंब को जन्म दिया है—लेकिन नक्शा कार्यक्रम भूमि प्रशासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित बनाकर इस विरासत को बदल रहा है। स्मार्ट शहर, पीएम गति शक्ति और पीएम स्वनिधि जैसे राष्ट्रीय मिशनों के साथ एकीकरण के जरिये, नक्शा भारत के विकास-केंद्रित भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। सुरक्षित, सत्यापित डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के साथ, अब नागरिकों के पास सचमुच अपने सपनों की कुंजी है—जो भारत को एक अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और विकसित भविष्य की ओर ले जा रही है।

भारत की श्रम संहिताएं व बढ़ेगा रोजगार

कार्तिक नारायण
मुख्य कार्याधिकारी, अपना जॉब्स

जैसे विश्व भर के देश प्रतिभाओं के लिए अपने भीतर देख रहे हैं। ऐसे में भारत को भी औपचारिक, औचित्यपूर्ण और गरिमामय रोजगार पैदा कर आगे बढ़ना होगा। समूची दुनिया में आव्रजन को लेकर चिंता, अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक व्यवस्थाओं को नया स्वरूप दे रही है। वैश्विक प्रतिभाओं का स्वागत करने वाले देश अब बदल रहे हैं, वे वैश्विक प्रतिभाओं के लिए पुल बनाने के बजाय अवरोध पैदा कर रहे हैं। उन्होंने प्रतिभाओं की तलाश अपने अंदर ही शुरू कर दी है। भारत इस बदलती हुई दुनिया में संपन्नता के लिए सिर्फ प्रतिभाओं के निर्यात पर निर्भर नहीं रह सकता। हमें उत्पादन के साथ ही अवसरों के लिहाज से भी आत्मनिर्भर बनना होगा।

मार्टिन लूथर किंग (जू०) ने एक समय कहा था, "मानवता को ऊपर उठाने वाले हर श्रम की गरिमा का और महत्व है। इसे श्रमसाध्य उत्कृष्टता के साथ किया जाना चाहिए।" भारत की नई श्रम संहिताएं इस आदर्श को जमीन पर उतारने की दिशा में एक कदम है। भारत का श्रम परिवेश वर्षों में पैबंदों वाली दरी के समान रहा है। देश के 29 श्रम कानून बेशक अच्छे इरादे में लाए गए हों लेकिन सब मिल कर अस्पष्टता पैदा करते रहे थे। सरकार ने इन कानूनों को वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा की चार संहिताओं में पिरो देने का फैसला किया। यह कदम सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं है। आधुनिकीकरण के इस अभियान में स्वीकार किया गया है कि संरक्षण और उत्पादकता को एक साथ मिलकर बढ़ना चाहिए। इम सुधार का संबंध दृश्यता से है। नियुक्तिपत्र, वेतन की पर्ची और डिजिटल रिकॉर्ड के बिना कामगार, सरकार और बाजार दोनों की ही नजरों से ओझल रहता है। औपचारीकरण इस स्थिति में बदलाव लाता है।

वेतन को ही लें। भारत में विभिन्न राज्यों और उद्योगों की अलग-अलग हजारों न्यूनतम मजदूरी दरें थीं। आस-पड़ोस के जिलों के कामगारों तक को एक ही काम के लिए काफी अलग-अलग रकम मिलती थी। वेतन संहिता में मजदूरियों की एक समान परिभाषा के साथ राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी स्थापित की गई। अब कंपनियां वेतन या लाभ की समानता से समझौता किए बिना नियुक्ति कर सकती हैं। कर्मचारियों के लिए लचीलेपन का मतलब अब असुरक्षा नहीं है। पुनर्कोशल निधि का निर्माण प्रतिक्रियात्मक कल्याण से सक्रिय रोजगार की ओर बदलाव का संकेत है। नौकरी छूटने का मतलब अब चट्टान से गिरना नहीं है, यह नया सीखने और पुनः प्रवेश करने का एक सेतु बन जाता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता वह मानती है कि भारत का कार्यबल अब फैक्टरियों तक ही सीमित नहीं है। ड्राइवर, डिलीवरी पार्टनर और फ्रीलांसर जैसे काम डिजिटल अर्थव्यवस्था के नए निर्माता हैं और अब सुरक्षा के दायरे में भी हैं। यह स्वीकार करते हुए कि काम की प्रकृति बदलती रहती है लेकिन सुरक्षा की जरूरत नहीं बदलती, नए प्लेटफॉर्म उनके कल्याण के लिए केंद्रीय कोष में योगदान देंगे। प्रवासी मजदूर, जिन्हें लंबे समय से अपने ही देश में बाहरी समझा जाता रहा है। जब जहां भी वे काम करते हैं, कल्याणकारी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह समावेशन का वास्तविक रूप कहा जा सकता है। सरलीकरण को शायद सबसे कम होने वाले लाभ के रूप में आंका गया है। अब 29 की बजाय एक पंजीकरण, एक लाइसेंस, एक रिटर्न भरना है।

निरीक्षक अब सुविधा प्रदाता हैं। अनुपालन की बातचीत दंड की बजाए साझेदारी की ओर बढ़ रही है। विश्वभर के देश प्रतिभाओं के लिए अपने अंदर की ओर देख रहे हैं। भारत को अपनी घरेलू श्रम प्रणाली को मज़बूत करना होगा जो पारदर्शी, सुवाह्म और निष्पक्ष हो। इन सुधारों का असली फायदा तब महसूस होगा जब भारत का विकास न केवल ज्यादा रोजगारों से, बल्कि बेहतर औपचारिक, उच्च-वेतन और सम्मानजनक रोज़गार में भी प्रेरित हो।

इन सुधारों का अगर सावधानी और निरंतरता के साथ क्रियान्वयन किया जाए, तो ये सुधार भारत की कार्यप्रणाली को नया रूप दे सकते हैं।

यह कैसा रील कल्चर है जो नैतिकता तोड़ रहा है

श्रीमती किरण चोपड़ा
डायरेक्टर- पंजाब केसरी दैनिक समाचार लि.
चेयरपर्सन- वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब
मुख्य संरक्षिका- चौपाल
सदस्या- राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल, एकल
संरक्षिका- भारतीय लोक विकास परिषद
/kiranchopra01
kiranchopra@punjabkesari.com
kiranchopradesk@gmail.com

यह सच है कि आज जमाना उस टैक्नोलॉजी का है जो सोशल मीडिया के रूप में देश और दुनिया पर हावी हो रहा है। कल तक लोग अखबारों में खबर छपने के बाद किसी घटना या इवेंट को लेकर जब चर्चा किया करते थे तो वह बड़ी सजीव और सकारात्मक हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से आज सोशल मीडिया चीजों को विशेष रूप से घटनाओं और इवेंट को प्रस्तुत कर रहा है उसका इम्पेक्ट एक होड़ को जन्म देता है। जो लोग सोशल मीडिया जैसे प्रोफेशन से जुड़े हैं वे आजकल रील बनाने का काम कर रहे हैं। रील बनाना हर किसी के जीवन में एक खास जगह बना रहा है। हालांकि रील बनाते समय आजकल नैतिकता की हदें भी पार की जा रही हैं, जो कि हमारे उस संस्कारों के खिलाफ है जिसे हम मान-मर्यादा और इज्जत के साथ जोड़ते हैं। केवल प्रसिद्धि पाने के लिए, केवल अपना लाभ कमाने के लिए और जहां कोई न पहुंचे वहां आप अपने आपको प्रदर्शित करने के लिए जब रील बनाते हैं तो आप लोग नैतिकता को दरकिनार कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि रील बनाने का कल्चर विशेष रूप से यूथ में सारी नैतिकताओं की हदें तोड़ चुका है और समाज पर इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं।

मैं जब कभी सोशल मीडिया के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम देखती हूं तो साधारण घरों की लड़कियां अनेक गानों की धुन पर डांस करती दिखाई देती हैं। डांस करने में कोई बुराई नहीं लेकिन जब आप अश्लीलता भरे डांस करेंगे तो यह मर्यादा का हनन है। किसी भी पुल के ऊपर से नदी में लड़के और लड़की का छलांग लगाना और अश्लील गानों पर थिरकते हुए रील बनाना यह सब मर्यादा का हनन है। दिल्ली की चलती मैट्रो में एक लड़की अश्लीलता भरा डांस कर रही है। इस रील के लिए लड़की अपनी शर्ट के बटन खोलकर लाइक्स किए जाने की अपील कर रही है।

इन्हीं रीलों में कमेंट करने की गुजारिश की जाती है जिनसे रील बनाने वालों के व्यूज बढ़ते हैं। इन्हें देख-देख कर कई और

लड़कियां ऐसी ही रीलें सोशल मीडिया पर डाल रही हैं। टीवी पर जब ऐसे डिबेट देखती हूं तो कितने ही दृश्यों को देखकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं कि ये हमारे समाज को क्या हो गया है। मेरा यह मानना है कि जब विज्ञान ने हमें टैक्नोलॉजी दी है और अनेक लोग रील बनाने के प्रोफेशन से जुड़े भी हैं लेकिन सामाजिक जीवन में रील बनाने को एक कल्चर के रूप में जिस तरह से यूथ ने स्थापित किया है वह एक सामाजिक बुराई के रूप में उभर रहा है और नैतिक सिद्धांतों का सम्मान भी किया जाना जरूरी है। रीलों की दुनिया में तेजी से वायरल होने की होड़ और किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना हमारे समाज के लिए घातक है। केवल व्यूज और लाइक के लिए अगर कोई लड़की अस्पताल में ग्लैमरस ढंग से नाचती है या मंदिर में लोगों की लाइनों के बीच में या किसी भी मॉल में या किसी भी सिनेमा के सामने अश्लील नृत्य करती है और उसे बदले में व्यूज और लाइक ही चाहिए तो ऐसी रील बनाने का क्या फायदा जो नैतिकता को अपने पांव तले रौंदती हो। इस संबंध में कड़े नियम लागू करने व सजा का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।

यही नहीं कई रीलें स्वास्थ्य को लेकर बनाई जाती हैं, उनको फॉलो करके भी कई लोग बीमार हुए, कई घर के वास्तु ठीक करने के लिए बनाई जाती हैं। वो बहुत लोगों को परेशान कर रही हैं। कई रीलें ज्योतिष के चक्र में बनती हैं, कई रीलें घर में पैसे की बरकत या घर में सुख-समृद्धि बढ़े, उसके लिए बनती हैं। सब रीलों ने आम व्यक्तियों को कई चक्करों में डाल रखा है। मेरे हिसाब से रीलें बनाने या सोशल मीडिया पर कुछ भी डालने के लिए नियम कानून बनने चाहिएं ताकि आम आदमी परेशान होने से बच सके।

इस मामले में मेरा माता-पिता से भी अनुरोध है कि बच्चों को मोबाइल के सद्उपयोग के लिए समझाएं और उन्हें बताएं कि कोई भी वीडियो बनाने से पहले उसमें कोई ऐसी रील न प्रस्तुत करें जिसमें गलत प्रभाव पड़ता हो। दूसरों का सम्मान करें, कानून का पालन करें और किसी के बारे में गलत कमेंट न करें। छात्रों के एक ग्रुप ने सहपाठी छात्राओं के फोटो खींच लिए और उनकी फिगर को लेकर कमेंट करने शुरू कर दिए और इसके लिए लाइक्स और व्यूज मांगे गए तो यह लाखों में थे, कुछ लड़कियों के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत की तो यह एक्शन हुआ और यह ग्रुप बंद कर दिया गया। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक घटना है। हमें एक-दूसरे पर विश्वास बनाने के लिए रील बनानी चाहिए। आज की तारीख में जिस तरह से अनेक छोटे-बड़े चैनल चाहे वह यूट्यूब से जुड़े हैं या खुद के व्हाट्सऐप हैं सनसनीखेज सामग्री डालने से बचना चाहिए। यह देश ऋषि-मुनियों, देवताओं और भगवान का देश है जहां से अच्छे संस्कारों की गंगोत्री बहती है। दुनिया भारत को एक संस्कारवान राष्ट्र मानती है लेकिन जागरूकता की कमी में रील बनाना वह गलत प्रभाव डाल सकता है और समाज पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर मेरी यही विनती है कि नैतिकता का सम्मान किया जाए और भारत की शान जो संस्कारों पर टिकी है उसका पालन किया जाना चाहिए। महज व्यूज और लाइक के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अपने आपको गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए रील मेकिंग कल्चर पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

https://t.me/AllNewsPapersPaid

पायनियर
नई दिल्ली, रविवार, 9 नवंबर 2025

बिहार में ख़ामोश बहुसंख्यकों का उदय

संजय मयूख

1990 के दशक के बिहार में, लालू के जंगलराज के बीच, शाम का मतलब कर्फ्यू था। महिलाएं अंधेरा होने से पहले ही घर चली जाती थीं, सड़कें खाली हो जाती थीं और हवा में डर भरा होता था। जबरन वसूली, अपहरण और राजनीतिक ताकत दिन का क्रम थी। युवाओं और महिलाओं के लिए अवसर एक दूर का सपना था, सुरक्षा स्वयं अनिश्चित थी।

बीस साल बाद, तस्वीर इससे अधिक भिन्न नहीं हो सकती थी। बिहार की महिलाएं आज घर के अंदर ही सीमित नहीं हैं, वे काम करने के लिए स्कूटर चला रही हैं, स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, और अक्सर पुरुषों से अधिक संख्या में मतदान कर रही हैं।

एक समय जंगल राज का पर्याय रहे राज्य ने अपनी महिलाओं और युवाओं को एक राजनीतिक और आर्थिक ताकत में बदल दिया है। विभाजनकारी जाति-आधारित राजनीति से लेकर तुष्टिकरण की राजनीति तक, परिवारवाद से प्रेरित कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जैसी पार्टियां अक्सर बिहार के युवाओं और महिलाओं के बजाय अपने बच्चों के विकास को प्राथमिकता देती हैं। उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं को दबाया और उन्हें ऐसा महसूस कराया कि यह उनकी वास्तविकता है।'

पिछले कुछ वर्षों में, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के नेतृत्व में, बिहार को बीमारू राज्य की छवि से विकसित और समृद्ध बिहार में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है।

नारी शक्ति और युवा शक्ति 2014 के बाद से पीएम मोदी के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं और उन्होंने बीजेपी-एनडीए सरकार पर अपना भरोसा जताया है। 2020 के बिहार चुनाव में, कुल 243 सीटों में से 119 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं थीं। उन 119 में से, एनडीए ने 72 सीटें (60.5 प्रतिशत) हासिल कीं, जबकि महागठबंधन (एमजीबी) ने सिर्फ 42 सीटें (35.3 प्रतिशत) जीतीं।

जैसा कि पीएम मोदी कहते हैं, ₹जब एक महिला विकसित होती है तो पूरा समाज विकसित होता है। और बिहार की महिलाओं के दो भाई हैं, नरेंद्र और नीतीश, जो उनके समग्र कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इसके विपरीत, महागठबंधन और तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक कौशल को कम करके बिहार के लोगों से झूठे और अव्यवहारिक वादे करने में व्यस्त हैं। हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और जीविका दीदियों को 30,000 मासिक देने का उनका वादा बिहार के मासिक बजट से अधिक है और इसे पूरा करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। ये महज उन महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें हैं जिन्होंने पिछले चुनावों में उनका समर्थन नहीं किया था. इस बीच, भाजपा-एनडीए सरकार जवाबदेही के साथ काम करती है और उसने अपने 2020 के घोषणापत्र के वादों को पूरा किया है और उन पर महत्वपूर्ण प्रगति की है।

जवाबदेही और वितरण :

बिहार के पुनरुत्थान की सबसे सशक्त कहानी यहां की महिलाओं की है। वे अब राज्य के हर कोने में बदलाव के एजेंट हैं। 50,000 करोड़ के माइक्रोफाइनेंस मिशन के तहत, 1.1 करोड़ महिलाओं को न

केवल वित्तीय सहायता मिली है, बल्कि सम्मान भी मिला है। प्रत्येक को 10,000 रुपये के सीधे नकद हस्तांतरण के माध्यम से, एनडीए सरकार ने उन्हें सिलाई और डेयरी फार्मिंग से लेकर स्थानीय व्यवसायों तक छोटे उद्यमों का प्रभार लेने में सक्षम बनाया है जो परिवारों और समुदायों का भरण-पोषण करते हैं।

लखपति दीदी योजना अब सिर्फ एक नीति नहीं है, यह 30 लाख महिलाओं का एक आंदोलन है जो आर्थिक बाधाओं को तोड़ रही है और दूसरों को भी इसका पालन करने के लिए प्रेरित कर रही है। 1 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन के साथ पीएम उज्ज्वला योजना ने चूल्हे के धुएं को सम्मान की एक नई सांस के साथ बदल दिया है, अर्थशास्त्र से परे, सशक्तिकरण का मतलब सुरक्षा और मान्यता है। अब हर जिले में एक महिला पुलिस स्टेशन है, और 35,000 महिला अधिकारी वर्दी में सेवा करती हैं - जो भारत में सबसे अधिक है। अनगिनत महिलाओं के लिए, यह शासन में विश्वास और सार्वजनिक जीवन में अपनेपन की भावना का प्रतीक है। राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की शुरूआत की गई है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें समाज का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। और घर पर, प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ने 41 लाख से अधिक परिवारों को 2020 के घोषणापत्र में किए गए वादे से 11 लाख अधिक एक पक्का घर दिया है, जिससे न केवल छतें बदल रही हैं, बल्कि जीवन भी बदल रहा है। स्वच्छ स्वच्छता, बिजली और एक महिला के नाम पर स्वामित्व ने गरिमा के साथ जीने के अर्थ को फिर से परिभाषित किया है।

युवा विकासः प्रवासन से प्रेरणा तक

बिहार के युवा, जो कभी अवसर की तलाश में पलायन करने को मजबूर थे, अब घर पर ही उद्देश्य तलाश रहे हैं। कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता आकांक्षा को उपलब्धि में बदल रहे हैं।

बिहार कौशल विकास मिशन के तहत 20 लाख से अधिक युवाओं ने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और जन नायक कपूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना सीखने को सीधे रोजगार से जोड़ने वाले इस बदलाव को संस्थागत बनाएगी। 2020 से 50 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई) के माध्यम से, एक अधिवास प्रावधान अब सुनिश्चित करता है कि स्थानीय युवाओं को पहली प्राथमिकता मिले, जिससे प्रतिभाओं को बिहार में जड़ें जमाने में मदद मिलेगी। साथ ही, बिहार शिक्षा में पहुंच को फिर से परिभाषित कर रहा है, एनआईटी पटना अब हिंदी में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जबकि हिंदी में एमबीबीएस पहल जल्द ही हजारों लोगों को उनकी अपनी भाषा में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराएगी।

ये सुधार एक ऐसी सरकार को दर्शाते हैं जो सुनती और समझती है कि अवसर तभी बढ़ते हैं जब शिक्षा और आकांक्षा एक ही भाषा बोलते हैं। यह बिहार नहीं है जो अपने बच्चों को दूर भेजता है, यह बिहार है जो उन्हें वापस बुलाता है।

एक समय प्रवासन द्वारा परिभाषित राज्य अब अवसर का गंतव्य बनने के लिए काम कर रहा है। बिहार के लिए एनडीए का संकल्प भाग 2025 अवसर का विस्तार करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने पर केंद्रित है। महिलाओं के लिए लक्ष्य वित्तीय और सामाजिक मजबूती है। माइक्रोफाइनेंस योजनाओं की सफलता और 1.21 करोड़ महिलाओं को 12,100 करोड़ रुपये के हस्तांतरण ने पहले ही ग्रामीण बिहार में उद्यमशीलता क्रांति ला दी है।

नया जीविका दीदी क्रेडिट कार्ड स्वयं सहायता समूहों को 15 लाख रुपये तक का ऋण आसानी से प्राप्त करने में मदद करेगा, जिससे महिलाओं को छोटे व्यवसाय बढ़ाने और अपने परिवार का समर्थन करने में मदद मिलेगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पिंक फोर्स इकाइयों के साथ-साथ लेफ्टिनेंट भारती आशा सहाय चौधरी और स्वतंत्रता सेनानी विजया मुशहरिन के नाम पर एक महिला पुलिस बटालियन की जल्द ही स्थापना की जाएगी। महिलाओं के स्वास्थ्य और रोकथाम के लिए मुफ्त एचपीवी टीकाकरण और नियमित कैंसर जांच जारी रहेगी। जैसे-जैसे बिहार औद्योगिक विकास के एक नए चरण में कदम रख रहा है, युवा और महत्वाकांक्षी ही इसे आगे बढ़ाएंगे। युवाओं के लिए नौकरियों और उद्यमिता पर फोकस है। सरकार की योजना खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में नए औद्योगिक पार्कों के माध्यम से 30 लाख नौकरियां पैदा करने की है। 10 लाख युवा उद्यमियों को प्रशिक्षित करने और सलाह देने, सह-कार्यस्थल और स्टार्टअप सहायता प्रदान करने के लिए जिला-स्तरीय सम्राट अशोक उद्यमिता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

पीएम मोदी के शब्दों में, ₹जब इतनी रोशनी है तो बिहार में लालटेन की जरूरत क्या है।₹ वह रोशनी विकास की रोशनी है, आत्मविश्वास की रोशनी है, आत्मनिर्भरता की रोशनी है, एनडीए सरकार बिहार में रोशनी लेकर आई है।

कांग्रेस और राजद ने बार-बार बिहार की प्रगति और यहां के लोगों के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है। आज बिहार अंधकार के उस युग में लौटने से इनकार कर रहा है. एनडीए सरकार को एक बार फिर लोगों का अटूट विश्वास और आशीर्वाद मिलेगा, खासकर बिहार की महिलाओं का, जो मानती हैं कि उनके भाई, नरेंद्र और नीतीश ही हैं जो बेहतर, शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। डॉ. संजय मयूख बिहार विधान परिषद में बीजेपी के मुख्य सचेतक और एनडीए के उप सचेतक हैं. वह भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। वह बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के मीडिया प्रबंधन की देखरेख कर रहे हैं। वह दो बार एमएलसी रह चुके हैं।

बतरस

ध्यान भटकाने की कला

राजेश विक्रांत

इन दिनों जम्बूद्वीप भरतखंड में एक कला काफी फल फूल रही है। ये है ध्यान भटकाने की कला। वैसे तो, ह्रदय की गहराइयों से या सच्चे मन से, मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए की गयी सुन्दर प्रस्तुति को ही कला कहते हैं लेकिन ध्यान भटकाने की कला में सच्चे मन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इसमें आपको एक्टिंग करना आना चाहिए। गिरगिट या मगरमच्छ के गुण होने चाहिए। रंग बदलने और आंसू बहाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। तब आप मुद्दों से लोगों का ध्यान बखूबी भटका सकेंगे।

ध्यान रहे कि भारतीय कलाओं का एक समृद्ध और जीवंत इतिहास है, जो 2,500 ईसा पूर्व के गुफा चित्रों से जुड़ा है। हमारे यहां कुछ समय पहले तक 64 कलाएं ही अस्तित्व में थी, ये ध्यान भटकाने की कला 65 वीं है जो सन 2014 में भारत में ही खोजी गई। और आज 2025 में अपने उच्चतम स्तर पर है। यानी कि हमारे देश का इस पर कॉपीराइट है। मुद्दों से ध्यान भटकाना, लटकाना, अटकाना आदि इसके उप प्रकार हैं। इस कला का मुख्य क्षेत्र राजनीति है और सही समय चुनाव का मौसम है।

महान जादूगर के लाल के अनुसार मंचीय जादू में केवल कल्पना का उपयोग करना होता है, इसके बाद सावधानीपूर्वक स्क्रिप्टिंग और अभ्यास करना होता है। लेकिन इसमें सबसे कठिन काम ध्यान भटकाने की कला सीखना है क्योंकि दर्शकों का ध्यान भटकाना एक ऐसा कौशल है जो हाथ की सहज सफाई और चतुर यांत्रिक भ्रमों के निर्माण से कहीं आगे है।

यह एक ऐसा कौशल है, ऐसी कला है जिसे वर्तमान राजनीतिक प्रतिष्ठान ने अच्छी तरह से सीख लिया है और वे देश में सर्वकालिक उच्च बेरोजगारी दर, कुपोषण, भुखमरी, महंगाई, 30 साल के उच्च थोक मूल्य सूचकांक- होलसेल प्राइस इंडेक्स, डीजल- पेट्रोल के आसमान छूते दाम आदि को ध्यान भटकाने की कला के सौजन्य से हल करते हैं।

जनता के मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं है। अब तो इस देश में यह लगने लगा है कि राजनीति की कला केवल ध्यान भटकाने की कला है। जिन मुद्दों को लेकर हमारे राजनेता और मीडिया सबसे अधिक उत्साहित होते हैं, वे उन वास्तविक मुद्दों पर लगभग कोई असर नहीं डालते हैं जिनका अधिकांश नागरिक सामना करते हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढाँचे का निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे जब कोई सामने लाने की कोशिश करता है जनता को अन्य मुद्दों का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। इस तरह भावनात्मक मुद्दों का उपयोग ध्यान भटकाने और अक्सर संवेदनहीन उन्माद को उत्प्रेरित करने के लिए किया जाता है। हमारे राजनेता इस कला में सबसे अधिक निपुण हैं।

मोटापे की नई दवाएं 'चमत्कारी इलाज' नहीं

(एलेग्जेंडर ड्यूपार्क, ओलिवियर लैरेज और फिलिप टेरेल - यूनिवर्सिटी ऑफ टौलौस तथा तानिया पैशेफ, यूनिवर्सिटी ऑफ पिकार्डी जूल्स वर्ने)

पेरिस। इक्कीसवीं सदी में मोटापा सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। यह एक दीर्घकालिक रोग है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कई जटिलताएं उत्पन्न करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, 1990 से 2022 के बीच मोटापे का वैश्विक प्रसार दोगुना हो गया और अब यह दुनिया भर में, 88 करोड़ वयस्क और 16 करोड़ बच्चों सहित एक अरब से अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा है। फ्रांस भी इससे अछूता नहीं है। एक अनुमान के अनुसार, देश में करीब 80 लाख लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। इसकी दर 1997 में 8.5 प्रतिशत से बढ़कर 2012 में 15 प्रतिशत और 2020 में 17 प्रतिशत हो गई।

हाल में विकसित नई दवाएं- ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1 (जीएलपी-1) एनालॉग्स- चिकित्सकों के लिए नई उम्मीदें लेकर आई हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि केवल इन दवाओं के भरोसे मोटापे पर काबू नहीं पाया जा सकता। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, अधिक वजन और मोटापा शरीर में असामान्य या अत्यधिक वसा संचय है जो स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण होता है। 25 से अधिक बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) को अधिक वजन और 30 से अधिक को मोटापा माना जाता है।

अब तक मोटापे के इलाज में जीवनशैली सुधार, संतुलित आहार, शारीरिक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक सहयोग और जटिलताओं की रोकथाम मुख्य उपाय रहे हैं। गंभीर मामलों में बेरिएट्रिक सर्जरी भी विकल्प रही है। मोटापे की पुरानी दवाओं जैसे डेक्सफेनफ्लुरामीन (आइसोमेराइड) और बेनफ्लुओरेक्स (मेडिएटर) को ह्रदय और फेफड़ों पर गंभीर दुष्प्रभावों के कारण बाजार से हटा लिया गया था।

अब चिकित्सकों के पास नई श्रेणी की दवाएं हैं- जीएलपी-1 एनालॉग्स- जो इंसुलिन स्राव को बढ़ाकर ब्लड शुगर नियंत्रण में मदद करती हैं, भूख कम करती हैं और पेट खाली होने की प्रक्रिया को धीमा करती हैं।इनमें लिराग्लूटाइड (ब्रांड नाम सैक्सेंडा, विक्टोज़ा), सेमाग्लूटाइड (वेगोवी, ओज़ेम्पिक) और टिरज़ेपाटाइड (माउंजारो) शामिल हैं। हफ्ते में एक बार इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाली ये दवाएं टाइप-2 डायबिटीज के इलाज में पहले से उपयोग की जाती हैं।

कई बड़े क्लीनिकल परीक्षणों में पाया गया कि जब इन दवाओं का उपयोग नियंत्रित आहार और शारीरिक गतिविधि के साथ किया गया, तो वजन में उल्लेखनीय कमी आई। साथ ही ह्रदय और चयापचय संबंधी कुछ मानकों में भी सुधार देखा गया।

फिलहाल इन्हें 30 से अधिक बीएमआई वाले या 27 से अधिक बीएमआई के साथ वजन-संबंधी रोगों से ग्रस्त वयस्कों के लिए मंजूरी मिली है। हालांकि, फ्रांस में इन्हें अभी बीमा प्रतिपूर्ति नहीं दी जाती। शोध से स्पष्ट है कि मोटापा केवल कैलोरी सेवन और खर्च के असंतुलन का परिणाम नहीं है। इसके पीछे आनुवंशिक, हार्मोनल, औषधीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारण भी होते हैं।

पर्यावरण में मौजूद कई रासायनिक पदार्थों को अब 'ओबेसोजेनिक' यानी मोटापा बढ़ाने वाला माना गया है, जो हार्मोन संतुलन बिगाड़ सकते हैं, आंतों के सूक्ष्मजीव तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं और जीन स्तर पर परिवर्तन ला सकते हैं। एक्सपोज़ोम की अवधारणा यानी जीवन भर के सभी पर्यावरणीय कारकों का योग अब इस संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई बार इन प्रभावों के परिणाम वर्षों बाद या अगली पीढ़ियों में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, डाइएथिलस्टिलबेस्ट्रोल (डिस्टिलबेन) दवा से मोटापा और कैंसर के बढ़ते जोखिम जैसे दीर्घकालिक प्रभाव देखे गए। अध्ययनों के अनुसार, जीएलपी-1 एनालॉग्स मोटापे को 'ठीक' नहीं कर सकते, वे केवल वजन घटाने में सहायक हैं। उदाहरण के लिए, एसटीईपी3 अध्ययन में सेमाग्लूटाइड लेने वाले प्रतिभागियों का वजन 68 सप्ताह में औसतन 15 प्रतिशत कम हुआ, जबकि प्लेसीबो समूह में यह केवल पांच प्रतिशत था। हालांकि यह सुधार महत्वपूर्ण है, फिर भी मरीज मोटापे की श्रेणी में ही बने रहते हैं। साथ ही, लंबे समय तक उपचार जारी रखना और इसके दुष्प्रभाव (जैसे मांसपेशियों में कमी या वजन वापस बढ़ना) प्रमुख चिंताएं हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक जीएलपी-1 दवाएं केवल रोग विकसित होने के बाद इस्तेमाल की जाती हैं। यानी यह उपचारात्मक दृष्टिकोण है, न कि निवारक।

मोटापा रोकने के प्रयासों में कई बाधाएं हैं – जैसे सस्ते और अत्यधिक प्रचारित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की आसान उपलब्धता, पौष्टिकता दर्शाने वाले उपकरणों (जैसे न्यूट्री-स्कोर) के उपयोग में बाधाएं, प्रदूषकों और हार्मोन प्रभावित करने वाले रसायनों का बढ़ता असर, शहरी नियोजन में सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा न देने वाली नीतियां और सामाजिक-आर्थिक असमानताएं आदि।

फ्रांस में निचले आय वर्ग के 17 प्रतिशत लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, जबकि उच्च आय वर्ग में यह दर 10 प्रतिशत है। बढ़ती असमानता और गरीबी इस प्रवृत्ति को और बढ़ा सकती है। जीएलपी-1 आधारित उपचार की अनुमानित लागत लगभग 300 यूरो प्रति माह है। यदि इसका खर्च स्वयं उठाना पड़े, तो यह केवल संपन्न वर्ग तक सीमित रहेगा। यदि स्वास्थ्य बीमा इसके लिए प्रतिपूर्ति करने लगे, तो सरकार पर वित्तीय बोझ अत्यधिक होगा।

विशेषज्ञों का मत है कि मोटापे से निपटने के लिए किसी एक दवा पर निर्भर रहना व्यावहारिक नहीं है। बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें चिकित्सा, मनोविज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नीति-निर्माण और सामुदायिक अनुभव सभी को शामिल किया जाए।

(द कन्वरसेशन)

मां भगवती की महिमा

मनौना बाबा खाटू श्याम का चमत्कार

शिरोज़ खान

चतुर्थ श्रेणी बरेली कॉलेज आवासीय परिसर में मसानी मठिया पर परिवार सहित रहने वाले निखिल महाराज बगैर पैसे बगैर चढ़ावा दूर-दूर से आए मरीजों का इलाज कर रहे हैं और चमत्कार तो तब है की नितिन महाराज के सानिध्य में आकर उन्हें फायदा भी प्राप्त हो रहा है। बगैर प्रसाद बगैर चढ़ावें के मरीज का इलाज कर रहे हैं। लौंग ,तेल ,फूल अगरबत्ती का खर्चा भी इधर-उधर से या महाराज द्वारा माता के आशीर्वाद से चल रहा है।

काफी समय से इलाज करा रहे सैकड़ो मरीज भी निखिल महाराज गुणगान कर जयकारा लगा रहे हैं। जब मसानी मठिया पहुंचकर स्वयं निखिल महाराज से इस संबंध में पूछा गया तो उनका साफ कहना मां भगवती की सिद्धि से हो रहा है चमत्कार माता द्वारा जरिया मुझे बनाया इसके लिए मेरी मां का धन्यवाद। बरेली कॉलेज आवासीय परिसर मे परिवार सहित रहने वाले निखिल नई उम्र के नवयुवक जो बरेली आसपास के क्षेत्र में निखिल महाराज के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं , स्वयं उनका कहना है,लगभग एक दशक पहले वह भयंकर बीमारी से ग्रसित हुए थे,डॉक्टरों की दवा काम छोड़ चुकी थी, डॉक्टरों द्वारा स्वयं भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया था। परिवार वालों ने अपने बेटे के लिए तरह-तरह के जतन किए मगर फायदा नहीं हुआ। तब प्रार्थना स्वरूप उनके ऊपर मां भगवती का चमत्कार हुआ मां की कृपा से उनका जीवन बचा था और मां भगवती ने स्वयं स्वप्न में भी आशीर्वाद स्वरुप उनके द्वारा चमत्कार का यह रास्ता बनाया है, जिसका उनके द्वारा लोगों को लाभ मिल रहा है। वह मां दुर्गा के उपासक हैं उन्हीं की सिद्धि से यह सब चमत्कार संभव हो रहे हैं।

जब से निखिल महाराज को मां भगवती का आशीर्वाद मिला है तब से निखिल महाराज हर वर्ष मां भगवती का विशाल जगराता कराते हैं, इसी क्रम में बीती रात निखिल महाराज द्वारा श्यामत गंज पुल के समीप साईं मंदिर के पीछे मसानी मठिया पर माता का जागरण कराया दूर-दूर से बाबा के भक्त और मरीज इस भव्य जागरण में शामिल हुए।

के समीप साईं मंदिर के पीछे मसानी मठिया पर माता का जागरण कराया दूर-दूर से बाबा के भक्त और मरीज इस भव्य जागरण में शामिल हुए। निखिल महाराज की बढ़ती ख्याति के तहत मुख्य अतिथि के रूप में कैंट विधायक , मेयर पुत्र पार्थ गौतम, मंत्री उमेश कठेरिया ने माता के जगराते में पहुंचकर हजारों की संख्या में भक्तों के साथ निखिल महाराज और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया।

नक्शा आपकी भूमि की डिजिटल पहचान का प्रतीक

विश्वसनीय भू-अभिलेखों और नागरिक सशक्तीकरण के लिए एक नई पहल

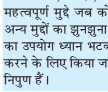

शिवराज सिंह चौहान

जब भारत एक समावेशी और विकसित भविष्य की कल्पना करता है, तो इसका सबसे मज़बूत आधार-स्तंभ भूमि है। चाहे घर हो, खेत हो, दुकान हो या स्मार्ट सिटी का सपना हो - विकास का प्रत्येक रूप भूमि पर अवस्थित होता है। हालाँकि, सच्चाई यह है कि वर्षों से हमारे भू-अभिलेख अधूरे, भ्रामक और अक्सर विवादों में उलझे रहे हैं। परिणामस्वरूप, आम नागरिकों को संपत्ति खरीदने, ज़मीन विरासत में प्राप्त करने, ऋण प्राप्त करने या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

इन दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग ने ₹नक्शा₹ (राष्ट्रीय शहरी निवास-स्थल भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण) कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह भारत में भूमि प्रबंधन, प्रशासन और भूमि-रिकॉर्ड रख-रखाव में बदलाव लाने की एक पहल है। यह कार्यक्रम एक पारदर्शी, डिजिटल और सत्यापित भू-अभिलेख प्रणाली का निर्माण कर रहा है, जो न केवल नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगी, बल्कि कस्बों और शहरों के विकास को भी गति प्रदान करेगी।

भारत में, भूमि पंजीकरण लंबे समय से एक जटिल व दस्तावेज-आधारित प्रक्रिया रही है। बिक्री विलेख, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, पटवारी सत्यापन और तहसील स्तर पर प्रस्तुतियाँ झ ये सभी नागरिकों के लिए पूरी प्रणाली को बोझिल बना देती थीं। पुराने रजिस्टर और फाइलों में न केवल त्रुटियां मौजूद थीं, बल्कि इनमें आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी, जो कई विवादों का मूल कारण होता है। अस्पष्ट संपत्ति अभिलेखों की वजह से बैंकों से ऋण प्राप्त करने की संभावना कम हो गयी थी। उत्तराधिकार या दाखिल-खारिज की प्रक्रिया अक्सर वर्षों तक अदालतों में अटकी रहती थी। गलत माप, अस्पष्ट सीमाएँ और स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप ने इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया। यही कारण है कि लाखों भारतीयों के लिए, सुरक्षा के स्रोत के रूप में भूमि का महत्त्व कम होता गया और यह जोखिम का प्रमुख स्रोत बन गई।

नक्शाः डिजिटल पारदर्शिता की ओर कदम

नक्शा कार्यक्रम, सटीक और डिजिटल भू-रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण, जीएनएसएस मानचित्रण और जीआईएस उपकरण जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाता है। इस पहल के तहत, नागरिकों को 'योरप्रो' (शहरी संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड) कार्ड मिलता है, जो स्वामित्व का एक डिजिटल प्रमाण है और संपत्ति के लेन-देन को आसान बनाता है। सरकार 'योरप्रो' कार्यक्रम को समर्थन दे रही है। नक्शा के साथ, लोगों को अब स्वामित्व की पुष्टि के लिए दस्तावेजों या बिचौलियों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। इससे ऋण प्राप्त करने, बिक्री पूरी करने, उत्तराधिकार प्राप्त करने और विवादों का निपटारा करने की प्रक्रिया तेज़ और अधिक पारदर्शी हो गयी है। अंततः, नक्शा केवल एक तकनीकी सुधार नहीं है - यह नागरिक सशक्तिकरण, समानता और भू-स्वामित्व में कानूनी आश्वासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नक्शा कार्यक्रम मुख्य रूप से उन नागरिकों को लाभान्वित करता है, जो लंबे समय से अधूरे या अप्रचलित भू-दस्तावेजों पर निर्भर रहे हैं। नगरपालिकाओं और स्थानीय परिषदों के पास

सच्चाई यह है कि वर्षों से हमारे भू-अभिलेख अधूरे, भ्रामक और अक्सर विवादों में उलझे रहे हैं। परिणामस्वरूप, आम नागरिकों को संपत्ति खरीदने, ज़मीन विरासत में प्राप्त करने, ऋण प्राप्त करने या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है

अब स्वच्छ, सटीक भू-स्थानिक डेटा तक पहुँच की सुविधा है, जिससे बेहतर निर्णय लेना और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। नागरिक आसानी से ऑनलाइन प्रारूप मानचित्र देख सकते हैं और आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। यह डिजिटल प्रणाली कराधान को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाती है, साथ ही शहरी नीति-निर्माण और अवसंरचना डिज़ाइन की सटीकता और गति में सुधार करती है। संक्षेप में, जो भू-रिकॉर्ड कभी धूल भरे रजिस्टरों में केवल हस्तलिखित प्रविष्टियों के रूप में मौजूद था, वह अब रंगीन, इंटरैक्टिव और पारदर्शी डिजिटल मानचित्रों में विकसित हो गया है। यह आधुनिक, डेटा-संचालित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नक्शा कार्यक्रम का प्रभाव व्यक्तिगत स्वामित्व और प्रशासनिक दक्षता से कहीं आगे तक फैला हुआ है और यह आपदा प्रबंधन और शहरी नीति-निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर रहा है।

अवस्थिति की ऊँचाई का विस्तृत डेटा प्रदान करके, यह लोगों को बाढ़-जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाता है, जबकि चक्रवात, भूकंप या आग की स्थिति में, यह बिना किसी देरी के बचाव और राहत कार्यों को शुरू करने की सुविधा देता है। सत्यापित डिजिटल स्वामित्व रिकॉर्ड यह भी सुनिश्चित करते हैं कि मुआवजा और सहायता सही लाभार्थियों तक शीघ्रता से पहुँचे। इससे आपदा के बाद, पूर्वस्थिति को बहाल करने की प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाती है। इसके अलावा, नक्शा संतुलित और सतत अवसंरचना विकास को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक शहरी सुदृढ़ता का समर्थन करता है। अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और दिव्यांगजनों जैसे कमजोर समूहों के लिए, नक्शा सुरक्षा और सुलभता प्रदान करता है—उन्हें संपत्ति के रिकॉर्ड ऑनलाइन देखने और सत्यापित करने की सुविधा देता है, किसी भी धोखाधड़ी और अतिक्रमण के जोखिम को कम करता है, और सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाए बिना आसान पहुँच सुनिश्चित करता है। संक्षेप में, नक्शा केवल एक तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि दुनिया भर के उन नागरिकों के लिए विश्वास और सशक्तिकरण का प्रतीक है, जिनकी भारत की भूमि और इसके भविष्य में हिस्सेदारी है।

विकसित भारत की आधारशिला

भारतीय इतिहास में, भूमि विवादों ने अक्सर असमानता, संघर्ष और विलंब को जन्म दिया है—लेकिन नक्शा कार्यक्रम भूमि प्रशासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित बनाकर इस विरासत को बदल रहा है। स्मार्ट शहर, पीएम गति शक्ति और पीएम स्वनिधि जैसे राष्ट्रीय मिशनों के साथ एकीकरण के जरिये, नक्शा भारत के विकास-केंद्रित भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। यह न केवल स्थानीय शासन को मज़बूत करता है, बल्कि नागरिक भागीदारी, सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है, जिससे अधिक निवेश और रोज़गार सृजन का मार्ग प्रशस्त होता है।

आख़िरकार, भूमि सिर्फ़ एक भौतिक संपत्ति नहीं है—यह प्रत्येक भारतीय नागरिक की पहचान और विरासत है। दशकों से, यह विरासत अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के आवरण से ढँकी हुई थी, लेकिन नक्शा विश्वास, पारदर्शिता और समानता का अमृत काल प्रस्तुत कर रहा है। सुरक्षित, सत्यापित डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के साथ, अब नागरिकों के पास सचमुच अपने सपनों की कुंजी है—जो भारत को एक अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और विकसित भविष्य की ओर ले जा रही है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

राष्ट्रीय सहारा
पटना। रविवार • 9 नवंबर • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

दीपक सोने का हो या मिट्टी का, मूल्य उसका नहीं होता, मूल्य होता है उसकी लौ का जिसे कोई अंधेरा, अंधेरे के तरकश का कोई तीर ऐसा नहीं जो बुझा सके।

-विष्णु प्रभाकर

बदलेंगे मनरेगा के नियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को नई दिशा देने की कवायद एक अच्छा कदम माना जाएगा। एक संसदीय स्थायी समिति ने मनरेगा से जुडी चुनौतियों को देखते हुए और योजना को नया रूप देने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण आयोजित करने का सुझाव दिया है, जिससे मनरेगा की प्रभावशीलता का आकलन हो सकेगा। हाल ही में बजट सत्र के समापन के अंतिम हफ्ते में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने योजना के तहत काम के दिनों की संख्या को वर्तमान 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की सिफारिश की है। वहीं, समिति का सुझाव है कि मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी को कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन तक बढ़ाया जाना चाहिए। दरअसल, मनरेगा के बजट आवंटन में पिछले

कुछ वर्षों में ठहराव आया है। यहां तक कि केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार सत्तासीन होने के बाद यह आरोप भी लगा कि मोदी सरकार मनरेगा की अवधारणा को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। दो महीने पहले पेश आम बजट में ग्रामीण रोजगार योजना के लिए आवंटन 86,000 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष के समान है। इस बात को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आक्रामक रुख अपनाया। बजट के बाद कांग्रेस ने बकायदा प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया था कि इस महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच की 'उपेक्षा' ग्रामीण आजीविका के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाती है। बहरहाल, देश के सांसद देर से ही सही मनरेगा मजदूरों की दुदर्शा सुधारने को लेकर अगर संवेदनशील दिख रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य की सफलता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वहां सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। समग्र विकास की इस पृष्ठभूमि में मनरेगा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चूंकि मौजूदा आर्थिक मंदी ने खासतौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित किया है और रोजगार के अवसरों को काफी कम कर दिया है, इस नाते संसदीय समिति का मनरेगा को लेकर उदार और सकरात्मक कदम उठाया जाना निश्चित तौर पर मजदूर तबके के लिए राहतकारी कदम होगा। अब श्रमिकों को कार्यक्रम से अन्यायपूर्ण तरीके से बाहर नहीं किया जा सकेगा। कुल मिलाकर मनरेगा मजदूरों की दशा और दिशा सुधरने की ओर यह कदम निःसंदेह बेहतरी लाएगा।

आस्था में शिष्टाचार

महाराष्ट्र के सभी मंदिरों में दिशा-निर्देश जारी कर भक्तों से शालीन कपड़े पहनने का आग्रह किया जा रहा है। मंदिरों के न्यासियों का मानना है, धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाये रखने के लिए ड्रेस कोड यानी वस्त्र संहिता जरूरी है। पुणे के मोरगांव और थेउर, अहिल्यानगर में सिद्धटेक और पिंपरी चिंचवाड़ मोरया गोसावी और रायगढ में खार नारंगी आदि के प्रबंधकों ने श्रद्धालुओं से उचित पोशाक पहनने का अनुरोध किया है। यह स्पष्ट किया गया है कि यह अनिवार्य नहीं है, मगर शिष्टाचार बनाये रखने के लिए सम्मानजनक अपील भर है। इसी साल के शुरुआत में मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धविनायक मंदिर में भी ड्रेस कोड की घोषणा की थी। कुछ अन्य मंदिरों ने जींस, स्कर्ट, शार्ट्स, देह दर्शाना पोशाक पर सख्त पाबंदी लगाई है। यह प्रतिबंध समूचे महाराष्ट्र में लागू करने के प्रयास हैं। शनि शिगणापुर व अहिल्यानगर जिले के शिरडी में भी यह ड्रेस कोड लागू करने की अपील की गई है। कुछ साल पहले नागपुरके चार मंदिरों में ड्रेस कोड जारी किया था, जिसमें गोपालकृष्ण मंदिर, संकटमोचन पंचमुखी हनुमान, बृहस्पति मंदिर व दुर्गामाता मंदिर शामिल हैं। देशभर के विभिन्न बड़े मंदिरों में तेजी से ड्रेसकोड लागू होते जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण यह भी है कि युवाओं में छोटे या बदन उघाड़ू कपड़े पहनने का फैशन चल पड़ा है। वास्तव में अन्य धार्मिक स्थलों मसलन गुरुद्वारों, चर्च व मजारों में इस तरह के ड्रेस कोड हमेशा से चले आ रहे हैं। कुछ धार्मिक स्थलों में सिर ढककर ही प्रवेश की आज्ञा होती है। हालांकि हिन्दू धर्म इन सब को लेकर बेहद सहिष्णु रहा है। तार्किक तौर पर तो बड़े मंदिरों में गर्भगृह में देवताओं की पूजा-अर्चना करने वाले महंत/पुरोहित/पुजारी हमेशा से केवल कमर के नीचे का भाग ढकते हैं। उनकी छाती हमेशा खुली होती है। मंदिर प्रांगण में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा में खलल न हो, न ही उनकी आस्था पर प्रहार हो; यह ख्याल रखना मंदिर प्रबंधन का जिम्मा है। जिन धर्मस्थलों में वस्त्र-संहिता नहीं लागू है, वहां भी पहनावे के प्रति श्रद्धालुओं को सतर्क रहना सीखना चाहिए। आस्थावान होने का तात्पर्य है, भक्तों का प्रयास हो कि उनके कृत्य से किसी अन्य की भावनाएं न आहत हों। न ही वे खुद अपमानित होने वाले कदम उठाएं।

मतदाताओं का उत्साह रचेगा इतिहास

बिहार चुनाव

आलोक पाण्डेय

बिहार विधानसभा के पहले चरण के 18 जिलों की 121 सीटों पर उतरे 1314 उम्मीदवारों की किस्मत वोटिंग मशीनमें कैद हो गई है। प्रथम चरण में मतदाताओं ने अत्यधिक उत्साह दिखाया है तथा 121 सीटों में 64.69 प्रतिशत मत दे करके लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था प्रकट की है। बिहार के चुनावी इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी मात्रा में लोग वोट देने के लिए घरों से निकले। 2020 की तुलना में लगभग 8.5ऽ ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। 1951 से लेकर के वर्तमान अर्थात 2025 तक बिहार में लोकसभा एवं विधानसभा के किसी भी चुनाव में इतना अधिक मत प्रतिशत नहीं हुआ है। जहां 1951 में लोकसभा चुनाव में 40.35 प्रतिशत मत पड़े थे तो इसी वर्ष विधानसभा चुनाव में 42.6ऽ मतदान हुआ था। 1998 के लोकसभा चुनाव में यह मत प्रतिशत 64.6ऽ तक पहुंच गया था। 1998 से भी ज्यादा 2025 के विधानसभा चनाव में यह मतदान 64.69ऽ पहुंचा। बिहार में इस चुनावी रण में जनता की इस प्रकार की भागीदारी बिहार में एक नया और स्वच्छ जनादेश लेकर अवश्य आएगी। यह जनादेश किसके पक्ष में होगा यह कह पाना तो अभी अत्यंत दुरूह कार्य है लेकिन फिर भी जनता जब भी चुनाव में भागीदारी करती है वह एक संदेश अवश्य देती है।

बिहार चुनाव में यह मतदान क्या संकेत करता है यह तो 14 नवंबर 2025 को पता चल जाएगा लेकिन इस बढ़े मतदान ने राजनीतिक पंडितों को दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि बढ़ा मतदान सत्ता रूढ़ दल को चिंता में अवश्य डाल देता है। हालांकि यह कई बार गलत सिद्ध भी हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में बढ़े मत प्रतिशत में भी बीजेपी ने वापसी की थी। प्रथम चरण के 121 सीटों पर हुआ मतदान जिसमें मख्य मुकाबला महागठबंधन व राष्ट्रीय गठबंधन में दिखाई देता है। हालांकि बिहार के इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपने जन सुराज के माध्यम से एक तीसरा विकल्प भी दिया है लेकिन ऐसा माना जा रहा है की मख्य मुकाबला इन दोनों गठबंधनों के मध्य ही रहेगा। बिहार में बड़ी मात्रा में बागी भी चुनाव लड़ रहे है यह बागी किसी न किसी का मत आवश्य काटेंगे। इसलिए बिहार के चुनाव में कोई निष्कर्ष या विवेचना में कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। बिहार के लिए वैसे भी कहा जाता है कि बिहार की जनता किसके पक्ष में जाएगी यह भविष्यवाणी करके आप अपने ज्ञान पर प्रश्न अवश्य लगा सकते है। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से इतनी जागरूक है कि वह आमतौर पर लोगों को इस बात का पता नहीं चलने देती कि वह किस मत दे रही है। चुनाव में अलग-अलग तरह के गठबंधन बने हुए है जो 2020 में या तो किसी गठबंधन से अलग-अलग रहे थे या अब उसे गठबंधन के साथ है। एक उदाहरण से समझ जा सकता है कि चिराग पासवान पिछले चुनाव में अलग चुनाव लड़ रहे थे तथा इस बार वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है। प्रशांत किशोर चुनावी भूमिका में ही नहीं थे। मुकेश सैनी इस बार महा गठबंधन के साथ है। इस चुनाव में कोई ना कोई गठबंधन तो अवश्य सफल होगा लेकिन कौन सा यह 14 नवंबर को पता चल जाएगा। बिहार में बढ़ा हुआ मतदान भी यह अनुमान लगाने से रोकता है की प्रथम चरण का विजेता कौन है। प्रत्येक पक्ष इसे अपने पक्ष में जीत के रूप में बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर वह अपने जीत के रूप में हवा नहीं बनाएगा तो इसका नुकसान उसे द्वितीय चरण में उठाना पड़ेगा।

बिहार के प्रथम चरण के चुनाव में बढ़े मतदान के कारणों में जाननेका यदि प्रयास किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक जागरूकता, चुनाव आयोग की सक्रियता, एवं विशेष मतदाता पुनरीक्षण के दौरान वोटो की कम हुई संख्या, यह तीन प्रमुख कारक माने जा सकते है। बिहार में विकास की भूख इस चुनाव में अलग से दिखाई दे रही है दोनों गठबंधन बिहार को आर्थिक तौर पर आगे बढ़ाने के लिए अपने-अपने तरह से वादा कर चुके है। बिहार की जनता को लगने लगा है कि कोई भी सत्ता में आए उसे अब विकास से अछूता नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए बिहार के लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक जनप्रिय सरकार बनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने लगातार अपने कार्यक्रमों द्वारा लोगों को जागरूक करके, अर्धसैनिक बलों की समय पर और सही जगह पर तैनाती करके और दो चरण में चुनाव करके यह सिद्ध किया है कि बिहार में अब कानून व्यवस्था बेहतर है। इलेक्शन कमीशन ने निश्चय ही इन कार्यो द्वारा लोगों को वोट देने के लिए घर से निकलने के लिए प्रेरित किया। विशेष मतदाता परीक्षा पुनरीक्षण को भी इस बार के भारी मतदान का श्रेय दिया जा सकता है क्योंकि 2020 के चुनाव में कल वोटो की संख्या 7.89 करोड़ थी तथा उसी वर्ष विधानसभा चुनाव में 57.29% वोट पड़े थे, लेकिन विशेष मतदाता पनरीक्षण के बाद मृत अनुपस्थित एवं दो जगह के नाम वाले मतदाताओं की छटनी के बाद कुल 7.42 करोड़ मतदाता ही मतदाता सूची में रह गए। इसके बाद बिहार के प्रथम चरण चुनाव में 64.69 प्रतिशत लोगों ने मत दिया।

> **बढ़े मतदान ने राजनीतिक पंडितों को दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि बढ़ा मतदान सत्तारूढ़ दल को चिंता में अवश्य डाल देता है। हालांकि यह कई बार गलत सिद्ध भी हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में बढ़े मत प्रतिशत में भी बीजेपी ने वापसी की थी। प्रथम चरण के 121 सीटों पर हुआ मतदान जिसमें मुख्य मुकाबला महागठबंधन व राष्ट्रीय गठबंधन में दिखाई देता है।**

इस विधानसभा चुनाव में प्रवासी बिहारी भी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए आए है। सौभाग्य से बिहार का चुनाव उसे समय हुआ जब बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ उसके कुछ दिन पूर्व ही मनाया गया था। इस त्यौहार को मनाने के लिए देश-विदेश से बिहार में रहने वाले लोग अपने घरों की ओर लौटते है। प्रवासी मतदाता बिहार में आने के बाद छठ मनाकर वापस अपने काम पर न लौटकर बिहार में वोट करने के लिए रुक गया है। प्रवासी मतदाताओं को रोकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व तेजस्वी यादव ने भी अपनी भूमिका अदा की है। दोनों ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने-अपने घोषणा पत्र में बिहार के विकास के लिए अनेक अनेक वादे किए है। दोनों ने कहा है कि बिहार में वह कई करोड़ नौकरियां देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने तो प्रत्येक जिले में उद्योग लगाने का भी वादा किया है इससे प्रवासी बिहारियों के मन में यह बात बैठ गई है कि वह अगर सही सरकार चुनते है तो निश्चय ही बिहार में उन्हें रोजगार प्राप्त होगा। उन्हें रोजगार के लिए और किसी राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए प्रवासी मतदाताओं को लगता है कि उन्हें मत देकर सरकार निर्माण में भूमिका अवश्य निभानी चाहिए। प्रवासियों ने वोट किसे दिया यह कह पाना तो संभव नहीं है लेकिन यह वोट बिहार के बेहतरी के लिए किया गया है। जो भी दल जीते, या हारे बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत लोकतंत्र की विजय पताका को फहरा रहा है। जहां एनडीए अपने पूर्व में किए गए कार्यो के आधार पर मत मांग रहा है वही महागठबंधन व जन सुराज बदलाव के लिए वोट मांग रहा है। तेजस्वी यादव कहते है कि अब बदलाव जरूरी है। लालू यादव तो कह रहे है की रोटी को एक तरफ ही कितना सकते रहोगे, जरूरत से ज्यादा सेकने पर रोटी जल जाएगी।

बिहार चुनाव में महिला वोटर ही यह तय करेंगे कि कौन सा गठबंधन चुनाव जीतेगा या हारेगा। प्रथम चरण के मतदान में महिला वोटरों की लंबी कतारों ने भी यह बात बताई है। जहां एनडीए सत्ताधारी दल है ने चुनाव की घोषणा से पहले ही महिलाओं की खातों में 10000 की वित्तीय राशि भेज कर बड़ा खेल खेला है वहीं विपक्षी महा गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने इसका तीन गुना यानी ?30000 प्रतिवर्ष देने का वादा किया है उन्होंने कहा है कि माई बहन योजना के तहत यह राशि प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को महिलाओं के बैंक खातों में डाली जाएगी। इससे यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि बिहार चुनाव में पुरुष तो अपना मन बना चुके है कि किस गठबंधन को अपना वोट देना है, अब महिलाओं को सभी दल अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रहे है।

बिहार विधानसभा के प्रथम चरण में ऐतिहासिक मतदान लोकतंत्र के प्रति बढ़ती आस्था को व्यक्त कर रहा है। बिहार की जनता ने यह संदेश दिया है कि बिहार वोट देने की परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने लगा है। राजनीतिक दलों की जीत या हार तो 14 नवंबर को पता चलेगी लेकिन लोकतंत्र की जीत की पटकथा तो प्रथम चरण के चुनाव से ही लिख दी गई है। द्वितीय चरण संभवत इससे भी आगे जाकर अपना योगदान लोकतंत्र को स्थापित करने में देगा। क्योंकि प्राय यह माना जाता है कि प्रथम चरण से ज्यादा मतदान द्वितीय चरण में सामान्य तौर पर होता है। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव में एक इतिहास लिखें जाने की संभावना है कि बिहार में अब तक के चुनाव में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत में और प्रभावी रूप से वोट दिया है। लेकिन इस ज्यादा वोट ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को यह सोचने के लिए विवश कर दिया है कि बढ़ा हुआ यह मत किसे प्राप्त होगा। दोनों ही पक्ष इसे अपनी जीत के लिए पड़े मतदान की ओर संकेत मान रहे है लेकिन यह 14 नवंबर 2025 को ही पता चल पाएगा कि जनता किसे विजयश्री दिलाने का मन बनाया है।

(मीडिया इनपुट्स)

टेस्ला की आमद पर बताशे बांटनेवाले न भूलें कि कभी इंग्लैंड के Charter Act 1833 से अधिकृत ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड के Wellesley, Hastings आदि गवर्नर जनरलों ने भी भारत में कूटनीति से कंपनी बहादुर का राज फैला कर 1856 में हिमालय से बर्मा तक को 2 सदी तक खुली लूट का अड्डा बना लिया था।

मृणाल पांडे, पत्रकार
@MrinalPande1

पिछले जन्मों का करम

ओशो

एक व्यर्थ की धारणा हमें सिखा दी गई है कि तुम्हें दुःखी होना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्मों का कर्म तुम्हें भोगना है। यह धारणा अगर मन में बैठ गई कि मैं पिछले जन्मों के कर्मों को भोग रहा हूं, तो सुख का

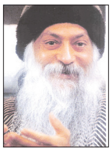

उपाय कहां है? इतने-इतने जन्म! कितने-कितने जन्म! चौरासी कोटि योनियां! इनमें कितने पाप किए होंगे, थोड़ा हिसाब तो लगाओ! इन सारे पापों का फल भोगना है। सुख हो कैसे सकता है! दुख स्वाभाविक मालूम होने लगेगा। ये आदमी को दुःखी रखने की ईजाद हैं। मैं तुमसे कहता हूं: कोई पाप नहीं किए हैं, कोई कर्म का फल नहीं भोगना है। तुम अभी जागे ही नहीं, तुम अभी हो ही नहीं, पाप क्या खाक करोगे! पाप बुद्ध कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध पाप करते नहीं। अकबर की सवारी निकलती थी और एक आदमी अपने मकान की मुंडेर पर चढ़ गया और गालियां बकने लगा। सम्राट को गालियां! तत्क्षण पकड़ लिया गया। दूसरे दिन दरबार में मौजूद किया गया। अकबर ने पूछाः तू पागल है! क्या कह रहा था? क्यों कह रहा था? उसने कहा मुझे क्षमा करें, मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैंने शराब पी ली थी। मैं बेहोश था। मैं था ही नहीं! अगर आप मुझे दंड देंगे, तो ठीक नहीं होगा, अन्याय हो जाएगा। मैं शराब पीए था। अकबर ने सोचा और उसने कहाः यह बात ठीक है; दोष शराब का था, दोष तेरा नहीं था। तू जा सकता है। मगर अब शराब मत पीना। शराब पीने का दोष तेरा था। शराब पीने के बाद जो कुछ तेरे मुंह से निकला, उसमें तेरा हाथ नहीं, यह बात सच है। आज भी अदालत पागल आदमी को छोड़ देती है, अगर पागल सिद्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि पागल आदमी का क्या दायित्व? किसी पागल ने किसी को गोली मार दी। अदालत क्षमा कर देती है, अगर सिद्ध हो जाए कि पागल है। क्योंकि पागल आदमी को क्या दोष देना, उसे होश ही नहीं है! तुम होश में रहे हो? ये जो चौरासी कोटि योनियां जिनके संबंध में तुम शास्त्रों में पढ़ते हो, तुम होश में थे? तुम्हें एकाध की भी याद है? अगर तुम होश में थे, तो याद कहां है? तुम्हें एक बार भी तो याद नहीं आती कि तुम कभी वृक्ष थे, कि तुम कभी एक पक्षी थे, कि तुम कभी जंगल के सिंह थे। तुम्हें याद आती है कुछ? शास्त्र कहते हैं; तुम्हें याद नहीं। और तुम गुजरे हो चौरासी कोटि योनियों से। तुम बेहोश थे, तुम मूर्च्छित थे। मूर्च्छा में जो भी किया गया, उसका क्या मूल्य है? परमात्मा अन्याय नहीं कर सकता।

रीडर्स मेल

निजता का अधिकार जरूरी

हर नागरिक को निजता का अधिकार है, इसलिए आम लोगों का डाटा संरक्षण करना सरकार का कर्तव्य है। आज के दौर में डाटा सुरक्षा एक अनिवार्य मुद्दा बन गया है। हमारे दैनिक दिनचर्या में साइबर स्पेस का दायरा बढ़ता जा रहा है। एक ओर साइबर पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर डाटा संरक्षण के अभाव में साइबर अपराध का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सरकार को स्वदेशी डिजिटल मंच विकसित करना चाहिए। कई बार बच्चों की लापरवाही से डाटा की चोरी हो जाती है। देश में बच्चों द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। सरकार को डाटा संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए।

हिमांशु शेखर, गया

रायशुमारी से बनेगी बात

'ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी' इटली में एक राष्ट्रीय-रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी लोकलुभावन राजनीतिक पार्टी है, जो वर्तमान में देश की सत्तारूढ़ पार्टी है। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी कर रही हैं। बीते रविवार को इटली में रायशुमारी का पहला दौर कराया गया, जिसमें लोगों को आप्रवासन को लेकर कुछ बदलाव पर अपनी सहमति देनी है। पहला प्रस्ताव गैर-ईयू निवासियों के लिए नागरिकता के लिए आवेदन करने की प्रतीक्षा अवधि को 10 वर्ष से घटाकर केवल पांच वर्ष करने का है, जिससे इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के बराबर हो जाएगा। अभियानकर्ताओं का तर्क है कि इस बदलाव से लगभग 2.5 मिलियन लोगों को लाभ हो सकता है और केंद्र-वाम डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। लाखों अप्रवासियों का भाग्य दांव पर है क्योंकि इटली के लोग दो दिवसीय जनमत संग्रह में मतदान में भाग ले रहे हैं, जिसमें कानूनी रूप से देश में प्रवेश करने वाले विदेशियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव है। जनमत संग्रह में बेहतर नौकरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम सुधारों को वापस लेने की भी मांग की गई है। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव भारत में आता तो इसे सरकार मेज थपथपा के लागू करवा देती।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

विकास की बयार सभी तक

प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे पुल का उद्घाटन कर दिया है। कह सकते हैं कि अब कश्मीर की वादियों से निकल कर ताजगी भरा सेब, चेरी, कैंसर और अन्य ड्राई फ्रूट्स कुछ ही घंटे में दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में पहुंच जाएगा। सबसे ज्यादा तो कश्मीरी सेब की मिठास को रफ्तार मिल सकेगी। क्योंकि पहले देश के बड़े शहरों में कई दिनों में पहुंचता था अब वह कुछ घंटों में पहुंच जाएगा। अतः इसे हम एक प्रसन्नता की कह सकते हैं कि विश्व के इस सबसे ऊंचे पुल के जरिए जो चिनाब नदी पर बना है के दम पर रेल के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश जुड़ जाएगा। हमेशा से एक दर्द सालता रहता था कि कश्मीर में रेलवे लाइन न होने से पर्यटकों को काफी परेशानियां आती थी। बस से यात्रा करने में ज्यादा समय लगता था, पर अब यहां रेलवे लाइन आ जाने से इधर का आवागमन अवश्य सुगम एवं सरल बना जाएगा एवं पर्यटन को भी बल मिल सकेगा।

मनमोहन राजावत 'राज', शाजापुर, मप्र

letter.editorsahara@gmail.com

नोटबंदी की वर्षगांठ

देश की अर्थव्यवस्था को मिली नई दिशा

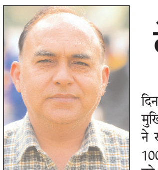

प्रशांत दीक्षित

देश के इतिहास में 8 नवम्बर 2016 एक ऐतिहासिक तिथि के रूप में दर्ज है। इसी दिन एनडीए सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रात आठ बजे 500 और 1000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों को बंद करने का निर्णय लिया था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा से जनता भौचक्की रह गयी थी। विपक्ष ने भी नोटबंदी (डिमोनेटाइजेशन) की प्रक्रिया को लेकर केन्द्र सरकार की जमकर आलोचना की। इस सबके बावजूद देशहित में उठाया गया प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित हुआ। नौ वर्ष पूर्व उठाये गये इस कदम ने भारत को आर्थिक ईमानदारी, पारदर्शिता और डिजिटल प्रगति की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। कुछ कठिनाइयों के बावजूद, यह कदम राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ। नोटबंदी (डिमोनेटाइजेशन) का मुख्य उद्देश्य था काले धन, भ्रष्टाचार, नकली नोटों और आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाना। भले ही यह कदम अचानक लिया गया था, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम राष्ट्र के हित में रहे। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई, आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण हुआ और देश की वित्तीय प्रणाली अधिक सुदृढ़ हुई।

नोटबंदी का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि काले धन पर नकेल कसी गई। बहुत से लोगों ने अपने छिपे हुए धन को बैंकों में जमा करवाया, जिससे सरकार को वास्तविक आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा मिला। इससे टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी और आयकर दाताओं की संख्या में वृद्धि हुई। इसके अलावा नोटबंदी ने नकली नोटों के व्यापार पर कड़ा प्रहार किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए बड़े पैमाने पर नेपाल के जरिये जाली मुद्रा भारतीय बाजार में खपा रही थी और इससे अर्जित राशि का इस्तेमाल आतंकवाद और अपराधों को बढ़ावा देने में होता था। पुराने नोटों के बंद होने से यह अवैध गतिविधियाँ काफी हद तक रुक गई।

इसी के साथ देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिला। लोग नकद की जगह ऑनलाइन भुगतान, यूपीआई, कार्ड, और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने लगे। इससे न केवल लेनदेन में सुविधा बढ़ी बल्कि पारदर्शिता भी आई। डिजिटल अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जैसी समस्याओं में कमी आई।

हालाँकि कुछ समय तक आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ी। पुराने नोट बदलने के लिए बैंक में लगी लंबी कतारें, नकदी की कमी से व्यापार पर भी कुछ समय के लिए प्रभाव पड़ा लेकिन दूरगामी परिणाम देश हित में रहे। ऐसा नहीं था कि नोटबंदी पहली बार हुई हो। 1946 से 2023 तक देश में कुल पांच बार विमुद्रीकरण हुआ। जनवरी 1946 में, 1000 और 10,000 रुपए के नोटों को वापस ले लिया गया था और 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नए नोट 1954 में पुनः शुरू किए गए थे। 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने फिर से 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया था ताकि जालसाजी और काले धन पर अंकुश लगाया जा सके। 1946 में 10,000 रुपये के नोटों को बंद करने से लेकर 2023 में 2,000 के नोटों को बंद करने तक, हर कदम का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और बैंकिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण करना था।

नोटबंदी (विमुद्रीकरण) के चलते आम जनता को कुछ समय के लिए नकदी की समस्या से दो-चार होना पड़ा। लेकिन इन अस्थायी कठिनाइयों की तुलना में इसके दीर्घकालिक लाभ कहीं अधिक रहे। नोटबंदी ने देश को एक नई दिशा दी। जनता को कैशलेस और पारदर्शी व्यवस्था मिली। नकदी में लेनदेन सीमित होने से सरकार को नकदी प्रबंधन से लेकर राजस्व संग्रह समेत अन्य कई फायदे हुए। जबकि जनता को बैंक में पैसा जमा करना हो या किसी अपने को किसी भी शहर में भेजना अत्यंत आसान हो गया। अधिकांश नागरिकों ने इस कठिन निर्णय का समर्थन किया क्योंकि वे समझते थे कि यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए आवश्यक था। नोटबंदी एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय था जिसने भारत को एक स्वच्छ और आधुनिक आर्थिक व्यवस्था की ओर अग्रसर किया। यह कदम निश्चित रूप से राष्ट्र के हित में था, क्योंकि इसने भ्रष्टाचार, काले धन और आतंकवाद पर प्रबल प्रहार किया।

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 20, अंक 6826
आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

संस्कृति दुनिया को विस्तार से परिभाषित करके उसे समझने का एक तरीका है।
- मैलकॉम ब्रैडबरी

जुबीन, ऋषभ और स्वामी प्रेमानंद मौलिकता के विनम्र विद्रोह हैं, जिन्होंने रील्स के पीछे भागते युवाओं को सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया। मशीन वही है, एल्गोरिदम भी वही है, लेकिन इन तीनों ने मशीन को इतना सच्चा, मौलिक और जीवंत डाटा खिला दिया कि खुद सिस्टम को ही प्रामाणिकता प्रिय लगने लगी।

तीसरी परंपरा की खोज

ये तीनों कल्चरल जैमिंग के नायक हैं, जिनकी वजह से मौलिक संस्कृति ने मशीन के कोड को भले कुछ ही समय के लिए, लेकिन हैक कर लिया। यह कुछ ऐसा है, जैसे किसी विज्ञापन के बीच में एक सच्चा संदेश आ जाए, जो उपभोक्ता को ग्राहक नहीं, बल्कि सचेत नागरिक में बदल दे।

अंशुमान तिवारी
वरिष्ठ पत्रकार

दीपावली के बाद भी मुंबई की एक नम रात। मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर हरकत हुई, रील यानी फिरकी उभरी। जुबीन गर्ग के स्वरों ने भीतर समा लिया। आंखें स्वतः मुंद गईं। लेकिन कुछ मिनटों के सांगीतिक ध्यानलोक को तोड़ दिया एक दूसरी रील ने, दहाड़ते हुए ऋषभ शेट्टी। दैवीय आस्थाओं के आभिजात्य से दूर *कांतारा* एक दूसरे ही लोक में खींच ले गया। तीन मिनट की *कांतारा* यात्रा के बाद उभरी तीसरी रील! रोते, खिलखिलाते, सहज भक्ति में भीगते-भिगोते, डांटते-पुचकारते, ललकारते स्वामी प्रेमानंद गोविंदशरण। नौ मिनट खत्म होते ही लगा कि मैट्रिक्स (मूवी) टूट रहा है, दरक रहा है वह मायालोक, जो डिजिटल कंट्रोल के साथ कल्चरल कंट्रोल पर भी बुना है। ऐसा कृत्रिम जगत लोगों को एक जैसे वीडियो दिखाता है, एक जैसे गाने सुनाता है, एक जैसे सपने बेचता है, एक जैसे ट्रेंड पर नचाता है... और धीरे-धीरे हम कल्चरल एल्गोरिदम के स्लेव बन जाते हैं। फिर आता है मॉर्फियस, मगर लाल-नीली गोली लेकर नहीं। वह इसी एल्गोरिदम पर बिठाकर तीन अजनबी लोगों को भेज देता है। ये तीनों मैट्रिक्स से लड़ते नहीं, बल्कि इसके भीतर बैठ जाते हैं। वे सोशल-मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपने गीतों को बांटने के लिए, वे बॉक्स-ऑफिस की सफलता का प्रयोग करते हैं लोककथाओं को स्वीकार्य ठहराने के लिए, वे इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम पर बिठाकर विशुद्ध भक्ति को लाखों आंखों-कानों तक बांट देते हैं। वे नियो की तरह मैट्रिक्स को नष्ट नहीं करते, बल्कि उसमें शुद्ध, सच्चा, जमीन से जुड़ा इतना अधिक संवाद उतार देते हैं कि धीरे-धीरे, मशीन मूल्यों को पहचानने लगती है, और प्रामाणिकता एल्गोरिदम का नया धर्म बनने लगता है।

टाइम मशीन — अतीत से सुनें वर्तमान की धड़कन ▪ हर पखवाड़े

जुबीन, ऋषभ और स्वामी प्रेमानंद मौलिकता के विनम्र विद्रोह हैं, जहां पॉपुलर कल्चर, प्रामाणिक संस्कृति के सामने झुक जाती है। यह कुछ ऐसी शक्ति है, जहां सच्ची, देशज और आत्मीय अभिव्यक्तियां लोकप्रिय मंचों पर फैलकर एक सांस्कृतिक प्रतिरोध बन जाती हैं। यह तीसरी परंपरा की खोज है। तीनों ही कल्चरल जैमिंग या रचनात्मक सांस्कृतिक अवरोध के नायक हैं। संगीत, मीडिया और आध्यात्मिक असहमति को मिलाकर, उनका रचना संसार अद्वितीयता के मारक, एल्गोरिदमिक प्रभुत्व को चुनौती देता है। यह ऐसी कल्चरल जैमिंग है, जो संदेशों को अपना कर उन्हें उनके ही माध्यम से उलट देती है, जैसे किसी विज्ञापन के बीच में एक सच्चा संदेश आ जाए, जो उपभोक्ता को ग्राहक नहीं, बल्कि सचेतन नागरिक में बदल दे।

मौलिकता का पूर्वोत्तर

इस मैट्रिक्स में विचरते हुए अनुभव होता है कि जुबीन गर्ग की धुनों में छिपा है संस्कृति के मूल स्वरों का कोड, जो सोई हुई सांस्कृतिक स्मृतियों को जगाता है। हर गीत के साथ लोगों के भीतर छिपी 'अपनी मिट्टी' की खुशबू लौट आती है। 2006 में अपार लोकप्रियता पाने के बाद जुबीन मुंबई छोड़कर अपनी जड़ों की ओर लौट गए। जब उसका देहावसान हुआ, पूरा असम थम गया। वह संसार की चौथी सबसे बड़ी अंतिम यात्रा थी। लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, मानो उनकी आत्मा का कोई हिस्सा जा रहा हो। वह लोगों के आंसू, कंटेंट के अंधाधुंध शोर के बीच मौलिकता की शक्ति का अभिषेक थे। कला जब अपनी मिट्टी की खुशबू नहीं खोती, तो वह लोक की धरोहर बन जाती है।

अरण्य का सिनेमा

इसी मैट्रिक्स में शहरों से दूर किसी घने वन में अपनी आधुनिक लैब के भीतर ऋषभ शेट्टी सिनेमा के लिए नया लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं। वह कैमरे को शंख की तरह फूंकते हैं। उनका सिनेमाई संसार किसी विराट कथा यज्ञ की तरह चलता है, जहां हर फ्रेम में छिपा है एक रचनात्मक विद्रोह। ऋषभ ने पहले लोक को महसूस किया, फिर उससे कथा निकाली। इसलिए, *कांतारा* का जन्म शहर के स्टूडियो में नहीं, बल्कि तटीय कर्नाटक के जंगलों और मंदिरों में हुआ। जैसे प्राचीन यूनान के रंगमंच में सोफोक्लीज और एस्किलस ने देवताओं की कथाओं के भीतर छिपाकर राजसत्ता पर प्रश्न उठाए, वैसे ही ऋषभ शेट्टी ने भूतकोला के अनुष्ठानों के माध्यम से समाज की आत्मा को झिंझोड़ा। *कांतारा* सांस्कृतिक प्रामाणिकता का इनोवेशन है। सिनेमा का नवाचार है।

प्रामाणिक आस्था का विद्रोह

यह निर्मल भक्ति का नया क्वांटम यूनिवर्स है। स्वामी प्रेमानंद गोविंदशरण लोगों को याद दिलाते हैं कि ईश्वर को डाउनलोड नहीं किया जा सकता। उसे अनुष्ठानों से नहीं उतारा जा सकता, उसे केवल जपा जा सकता है, जिया जा सकता है। प्रेमानंद चमत्कार नहीं करते। मौलिक भक्ति की प्राचीन सोई स्मृति जगाते हैं। वह किसी नए धर्म के प्रवर्तक नहीं हैं। वह केवल यह याद दिलाते हैं कि प्रामाणिक आध्यात्मिकता भीतर की लौ है, जिसे किसी मंदिर, मठ या पंथ में कैद नहीं किया जा सकता। कॉरपोरेट अध्यात्म और गहरी भक्ति के संघर्ष पुराने हैं। *ब्रदर्स कारमाजोव* में दोस्तोयेव्स्की के पात्र अल्योशा और इवान सच्ची आस्था बनाम संस्थागत धर्म से जूझते हैं। अन्ना कारेनिना से लेकर रेसरेक्शन तक टॉल्स्टॉय के नायक उसी प्रामाणिक नैतिकता की खोज में हैं, जो समाज की पाखंडी परंपराओं से परे है। कबीर, तुलसी, नामदेव और सूर बता गए हैं कि संस्थागत धर्म उस साधक से हमेशा डरता है, जो आत्मा की स्वतंत्रता की पुकार लगाता है। बार-बार अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा की घोषणा करते, गुरुओं के समक्ष फूट-फूट कर रोते प्रेमानंद, भक्ति आंदोलन का 2.0 हैं, जहां आरती लाइवस्ट्रीम नहीं, अंतर्यात्रा है। जहां गुरु नहीं सिखाता, बस स्मरण कराता है।

आभा का पुनर्जन्म

वॉल्टर बेंजामिन ने अपने प्रसिद्ध निबंध *द वर्क ऑफ इन द ऐज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन* (1935) में 'आभा' (औरा) की विवेचना की है। आभा अर्थात वह अदृश्य प्रतिष्ठा, वह आत्मिक उपस्थिति, जो किसी कलाकृति की मौलिकता और समय-सापेक्ष अस्तित्व से जन्म लेती है। बेंजामिन ने चेताया था कि यांत्रिक रिप्रोडक्शन की सहायता से कोई मौलिक रचना असंख्य प्रतियों में फैल जाती है, तो जो नष्ट होता है, वह कला की आभा है, क्योंकि कला अपनी अद्वितीयता खो देती है। परंतु मौलिकता के विनम्र विद्रोह की इस तीसरी परंपरा ने बेंजामिन के सिद्धांत को उलट दिया है-जुबीन, ऋषभ, स्वामी प्रेमानंद ने मशीनों की मदद से संस्कृति की मौलिक आभा वापस जगाई है। यह वही क्षण है, जहां उपसंस्कृति मुख्यधारा बन जाती है। जब कलाकार, संत और साहसी कथाकार लोकप्रियता के औजारों को इतनी निपुणता से साध लेते हैं कि जनमानस सतहीपन की जगह गंभीरता को, ट्रेंड की जगह परंपरा को और एल्गोरिदम के पुश की जगह मौलिकता को वरीयता देने लगता है। और तब वह प्रणाली, जो सबको एक जैसा सोचने और देखने पर मजबूर कर रही थी, भीतर से हिलने लगती है।

हमारे युग के इन तीन स्वरों ने मशीन को इतना सच्चा, इतना मौलिक और इतना जीवंत डाटा खिला दिया कि स्वयं सिस्टम को ही प्रामाणिकता प्रिय लगने लगी। मौलिक संस्कृति ने कोड को हैक कर लिया है, भले ही कुछ समय के लिए सही, मगर मैट्रिक्स टूटा तो है।

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

ऋषभ के पुत्र का नाम भरत था, जिनके वंश में राजा शतशृंग का जन्म हुआ। शतशृंग के आठ पुत्र और कुमारी नामक एक कन्या थी। उसका मुख बकरी जैसा था। देवर्षि नारद ने अर्जुन को कुमारी की पूर्वजन्म की कथा सुनाई।

बकरी के मुख वाली कुमारी ने पाया मोक्ष

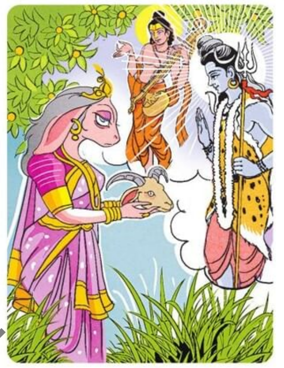

एक समय महीसागर के तट पर स्थित स्तंभतीर्थ के समीप घनी लताओं से घिरे वन में एक बकरी अपने झुंड से बिछड़ गई। वह वन से बाहर निकलना चाहती थी, पर लताओं में उलझकर मर गई। उसके शरीर का निचला भाग उसके सिर से अलग होकर महीसागर संगम में गिर गया, जो पापों का नाश करने वाला क्षेत्र था। संयोग से उस दिन शनैश्चर और अमावस्या का योग भी था। बकरी का सिर लताओं के बीच अटका रह गया। संगम के जल के पवित्र प्रभाव से बकरी का पुनर्जन्म सिंहल देश के राजा शतशृंग की कन्या (कुमारी) के रूप में हुआ, पर उसका मुख अब भी बकरी जैसा ही था। समय बीता, कुमारी युवा हो गई। एक दिन उसने दर्पण में अपना मुख देखा, तो बकरी का चेहरा देखकर उसे अपने पूर्वजन्म की स्मृति लौट आई। फिर उसने उसने माता-पिता से सारी बात बताई और उनसे अनुमति लेकर स्तंभतीर्थ की ओर रवाना हो गई। स्तंभतीर्थ पहुंचकर कुमारी ने दान दिया, तप किया और लताओं में से अपना पिछले जन्म वाला बकरी का सिर खोज निकाला।

धूप आने दो

● **फिर उसने उस सिर का संगम के निकट दाह-संस्कार किया और अस्थियां महीसागर में ही विसर्जित कर दीं। महीसागर के पुण्य प्रताप और तीर्थ की शक्ति से कुमारी के बकरी वाले मुख के स्थान पर चंद्रमा की तरह सुंदर और तेजस्वी मुख हो गया।**

कुमारी का अप्रतिम रूप देखकर देवता, दानव और मनुष्य तक मोहित हो उठे, परंतु वह किसी को पति नहीं बनाना चाहती थी। वह तपस्या में लीन हो गई। एक वर्ष की कठोर साधना के बाद महादेव शिव ने कहा, 'कुमारी, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं।' कुमारी ने हाथ जोड़कर शिव से कहा, 'प्रभो! यदि आप प्रसन्न हैं, तो इसी तीर्थ में निवास करें।' महादेव मुस्कराकर बोले, 'एवमस्तु!' फिर वहीं शिवलिंग की स्थापना हुई, जिसे 'वर्करेश्वर' कहा गया। यह समाचार नागराज स्वस्तिक तक पहुंचा। वह उसे देखने के लिए धरती पर आया और जहां से उसका सिर निकला, वहां एक कूप बन गया, जिसे आज भी 'स्वस्तिक कूप' कहा जाता है। गंगा जी ने उस कूप को जल से भर दिया, जिससे वह तीर्थों के समान पुण्यदायी हो गया। तब शिव ने प्रसन्न होकर कुमारी को वरदान दिया, 'जो इस स्थान पर शव का दाह करेगा और जिसकी अस्थियां महीसागर संगम में प्रवाहित की जाएंगी, वह स्वर्ग में निवास करने के बाद पृथ्वी पर प्रतापी राजा के रूप में जन्म लेगा। जो इस संगम में स्नान कर भक्तिभाव से वर्करेश्वर की पूजा करेगा, उसका हर मनोरथ पूर्ण होगा।'

बाद में राजा शतशृंग ने भारतवर्ष को नौ भागों में बांटा। आठ पुत्रों को आठ खंड दिए और नौवां भाग प्रिय पुत्री कुमारी को अर्पित किया। आगे चलकर आठों भाइयों से नौ-नौ पुत्र हुए, जो कुल मिलाकर बहत्तर हुए। एक दिन वे सब कुमारी के पास आए और बोले, 'आप हमारी कुलदेवी हैं, इन आठ खंडों को बहत्तर भागों में बांट दीजिए, ताकि कोई कलह न हो।' कुमारी ने भारतवर्ष के बहत्तर भाग कर अपने भतीजों में बांट दिए। उसने अपना हिस्सा भी उन्हें दे दिया। इसीलिए वह क्षेत्र 'कुमारीखंड' कहलाया और सबसे पवित्र माना गया। इसके बाद कुमारी, महीसागर के समीप भगवान की उपासना करने लगीं। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव फिर प्रकट हुए और बोले, 'आज से लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारीश्वर, दोनों नामों से जानेंगे। तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से मैं अत्यंत संतुष्ट हूं। अब तुम्हारा अंत समय निकट है, परंतु जिस स्त्री ने विवाह नहीं किया, उसे मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए, तुम इस तीर्थ में सिद्धि प्राप्त महाकाल को पति रूप में स्वीकार करो।' इस प्रकार उस बकरीमुखी कुमारी कन्या का जीवन दिव्य अनुग्रह से पूर्ण हुआ। उसने जिस स्थान पर भक्ति की, वही स्थान आज कुमारी और शिव के संगम का प्रतीक बनकर पवित्र तीर्थ माना जाता है।

मानसं शमयेत्
तस्माज्ज्ञानेनाग्निमिवाम्बुना।
प्रशान्ते मानसे ह्यस्य
शारीरमुपशाम्यति।।

अर्थात् जल से अग्नि को शांत करने की भांति ज्ञान द्वारा मानसिक दुख को शांत करना चाहिए। मन का दुख मिट जाने पर मनुष्य के शरीर का दुख भी दूर हो जाता है।

वनपर्व 2/26

(वनवास के प्रारंभ में शोकाकुल युधिष्ठिर से महर्षि शौनक ने कहा)

प्रस्तुति : **विवेक चौरसिया**

जब सामने वाला रुकने का नाम न ले रहा हो

जॉन्सी डान

जब सामने वाला इतना बातूनी हो कि आप आकंठ ऊब चुके हों, लेकिन मुंह खोलने का मौका तक न मिल पा रहा हो, तो थोड़ा सामान्य शिष्टाचार आपका सहारा बन सकता है।

हाल ही में, एक पार्टी में मेरी मुलाकात एक बेहद मिलनसार आदमी से हुई, जो अपने बेसमेंट के पुनर्निर्माण के बारे में करीब घंटे भर से बोले जा रहा था। जब वह सांस लेने के लिए रुका, तो मैं ड्रिंक लेने के बहाने उसके चंगुल से छूटी। हममें से ज्यादातर लोग उस बेचैनी और ऊब को जानते हैं, जो हमें एकतरफा बातचीत में फंसे होने पर होती है। ऐसा सामाजिक परिवेश और कार्यस्थलों पर भी होता है। ऐसी स्थिति में शालीनता से बातचीत को अपने नियंत्रण में लेने के तरीके कुछ विशेषज्ञों ने सुझाए।

द नेक्स्ट कन्वर्सेशन के लेखक जेफरसन फिशर कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम लेना उसका ध्यान आकृष्ट करने का सबसे आसान तरीका है। ज्यादातर लोग अपना नाम सुनते ही रुक जाते हैं और आपको बोलने का मौका मिल जाता है। अगर एक बार में काम न बने, दो दूसरी बार शांति से प्रयास करें, लेकिन हाथ उठाकर 'टॉक टू द हैंड' की तरह नहीं, जो धमकी की तरह लगे। बीच में टोकते हुए आप कहें, 'माफ कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूं।' ऐसे में वह आप पर बीच में टोकने का इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि आपने इसकी स्वीकृति ली है। मगर आपका अंदाज गर्मजोशी भरा, दृढ़ व शांत होना चाहिए।'

एमोरी यूनिवर्सिटी के गोइजुएटा बिजनेस स्कूल में प्रबंधन संचार की एसोसिएट प्रोफेसर निक्की ग्रेव्स ने कहा, ऐसे एकतरफा बोलने वाले व्यक्ति के सामने आप शांत, स्थिर और तटस्थ लहजे में तब तक बोलते रहें, जब तक वह खुद पीछे न हट जाए। फिशर कहते हैं कि ऐसे लोगों का ध्यान खींचने के लिए 'मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं' जैसे वाक्यांश से शुरुआत करना असरदार होता है। मसलन, आप कह सकते हैं-'मुझे यह स्पष्ट करना है।' 'मुझे इसमें कुछ और जोड़ना है।' 'मुझे आपको यहीं रोकना पड़ेगा।' इस तरह आप बिना टकराव के बातचीत पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर कोई सहकर्मी मीटिंग में अकेले बोल रहा हो, तो फिशर के अनुसार, आप उसकी बातों को संक्षेप में दोहराकर आगे की चर्चा के लिए किसी दूसरे को आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे, 'मैं इस विषय पर अपने दूसरे साथी के विचार भी जानना चाहूंगा।'

थेरेपिस्ट टॉड बरात्ज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा हो और लगातार अपनी ही सुना रहा हो, तो बातचीत खत्म करना ही ठीक है। इसके लिए सिर्फ 'मुझे जाना होगा' कहना पर्याप्त है, अथवा कोई बहाना बना दें।

©The New York Times 2025

अध्ययन कक्ष

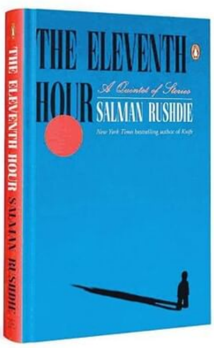

द इलेवंथ ऑवर

लेखक : सलमान रुश्दी

प्रकाशक : पेंगुइन रैंडम हाउस
मूल्य : 899 रुपये (हार्डकवर)

शब्द हमें निराश कर रहे हैं

सलमान रुश्दी का नया कहानी संग्रह जीवन के अंतिम क्षणों में ध्यान में आने वाली चीजों की मंत्रमुग्ध करने वाली खोज है। उनकी एक कहानी कहती है कि शब्द हमें निराश कर रहे हैं, पर रुश्दी के पास अब भी कहने के लिए बहुत कुछ है।

कई पीढ़ियों के बीच लोकप्रिय कथाकार सलमान रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा जारी किया गया। वर्ष 2022 में वह चाकू से किए गए हमले से बच गए। लेकिन रुश्दी की कलम ने तलवार पर विजय पाई, क्योंकि उस हमले के बाद से उनका कहानी संग्रह *द इलेवंथ ऑवर* प्रकाशित हुआ है। इसमें उनकी विशिष्ट बुद्धि और जादुई यथार्थवाद का शानदार संयोग मिलता है। इसमें मृत्यु बार-बार लौटने वाला विषय है। इसमें लेखक की मृत्यु से साक्षात्कार की प्रतिध्वनि है। *द इलेवंथ ऑवर* उनके कॅरिअर का एक तरह से उपसंहार प्रतीत होता है। इनमें दो कहानियां भारत से संबंधित हैं, जो आस्था और संदेह की उलझी हुई स्थितियों पर विचार करती हैं। अंतिम दो कहानियां अमेरिका से संबंधित हैं, जो प्रामाणिकता, सेंसरशिप और धोखाधड़ी जैसे गंभीर सवालों को संबोधित करने के लिए शैलीगत नवीनता का प्रयोग करती हैं।

एक कहानी का नाम 'लेट' है, जो एक परलोक-कथा है, जिसमें कैंब्रिज का एक छात्र, जिसका कॅरिअर ईएम फोर्स्टर (भारत पर एक महान उपन्यास लिखने वाले) और एलन ट्यूरिंग (एनिग्मा कोड को तोड़ने में मदद करने वाले), दोनों से मिलता-जुलता है, मर जाता है और मरने के बाद रोजा नाम की एक युवा भारतीय छात्रा को परेशान करता है; इन दोनों को जोड़ने वाली चीज साम्राज्य के दबे हुए अपराध हो सकते हैं।

'इन द साउथ' में झगड़ालू बुजुर्गों की एक जोड़ी-जूनियर और सीनियर-और राष्ट्रीय आपदा के एक क्षण में उनकी निजी त्रासदी का परिचय दिया गया है। 'ओक्लाहोमा' एक युवा लेखक को धोखे और झूठ के जाल में फंसा देता है, क्योंकि वह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके गुरु ने खुद को मार डाला या उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया।

'द म्यूजिशियन ऑफ कहानी' में युवा नायिका में जादुई प्रतिभाएं हैं, जो उसका इस्तेमाल उस धनी परिवार पर कहर ढाने के लिए करती है, जिससे उसकी शादी होती है।

'द ओल्ड मैन इन द पियाजा' हमारे समय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में एक सशक्त दृष्टांत है। इसका अंतिम वाक्य है-'हमारे शब्द हमें निराश कर रहे हैं।' यहां भाषा, जिसे एक मानव स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, को लुभाया जाता है, हड़पा जाता है, अनदेखा किया जाता है। अंततः वह चीखती है और गायब हो जाती है, जिस समय पियाजा की सभी इमारतें टूट जाती हैं-'पियाजा टूट गया है, और शायद हम भी।' यह वाक्य दर्शाता है कि *द इलेवंथ ऑवर* सिर्फ व्यक्तिगत मृत्यु के बारे में नहीं है, बल्कि यह सभ्यता के बारे में भी है। लेकिन सलमान रुश्दी के लिए शब्द अब भी विफल नहीं हुए हैं।

द इलेवंथ ऑवर जीवन और मृत्यु, विरासत व पहचान पर उस गहन अंतर्दृष्टि तथा असीम कल्पना के साथ विचार करता है, जिसकी बदौलत ही सलमान रुश्दी हमारे समय के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक बने हुए हैं।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

अभियान

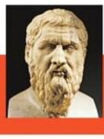

राजनीति में भाग न लेने का दंड यह है कि आपको अपने से निम्न लोगों द्वारा शासित होना पड़ता है। -प्लेटो

amarujala.com
अमर उजाला

Hindi@mithelesh
■ मिथिलेश बारिया

गोल चबूतरा

मां का बुना पुराना स्वेटर पहनने में शर्म आती है,
क्या-क्या छीन लिया, इस शहर ने तुमसे...

हवा मुंह फुलाकर बैठ गई है खिड़कियों से,
शहरों के झगड़े भी कुछ अजीब होते हैं...

तेरी हवा चली, मैं बुझने को हूं...

एक दीवार गिरी थी कभी

1989 में आज के ही दिन 'बर्लिन की दीवार' गिरा दी गई थी। यह दीवार 1961 में बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य पूर्वी जर्मनी के लोगों को पश्चिमी जर्मनी भागने से रोकना था। विश्व इतिहास में इसे एक 'ऐतिहासिक मोड़' के रूप में जाना जाता है। दीवार ने 'बर्लिन शहर' को दो भागों में बांट दिया था- पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। यह दीवार केवल एक भौतिक अवरोध नहीं थी, बल्कि यह 'शीत युद्ध' के दौरान 'पूंजीवादी और साम्यवादी' विचारधाराओं के बीच विभाजन का प्रतीक बन गई थी।

झरोखा
9 नवंबर

1980 के दशक के अंत में सोवियत संघ की कमजोरी और पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र की बढ़ती मांगों ने बदलाव की लहर पैदा की। पूर्वी जर्मनी में जनता ने स्वतंत्रता की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू किए। अंततः 9 नवंबर 1989 को सरकार ने सीमा खोलने की घोषणा की। हजारों नागरिक दीवार की ओर उमड़ पड़े और हथौड़े, औजारों से दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया।

बर्लिन की दीवार का गिरना जर्मनी के एकीकरण की दिशा में पहला कदम था। यह घटना न केवल जर्मनी के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र की विजय का प्रतीक बन गई।

■ राजन दास, लुधियाना

ब्रिटिश हुकूमत ने जब 'गॉड सेव द क्वीन' को गाना अनिवार्य किया, तब इससे खफा होकर महर्षि बंकिम ने वंदेमातरम गीत की रचना की थी। आगे चलकर यह देश की स्वतंत्रता संग्राम का गीत बन गया। उस वक्त इसे सभी धर्मों के लोग एक सुर में गाते थे, तो फिर आज इसे अपनाने में असहजता क्यों महसूस होती है?

अखंड वंदेमातरम में हर्ज क्या है

उदात्त भाव से स्वीकार करें राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रगीत की रचना को 150 साल पूरे हो रहे हैं। इस गीत की यात्रा 7 नवंबर, 1875 से आरंभ होकर कई पड़ावों से गुजरी है। इस यात्रा में गीत से अनन्य राष्ट्रभक्ति के ज्वार का देशव्यापी प्रसार शामिल है। गीत को अंग्रेजों के प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था, वहीं भारत विभाजन की विचारधारा के नाम पर इसे खंडित किया गया। आखिर हम क्यों न उस गीत को समग्र रूप में स्वीकार करें, जिसने क्रांति का संबल दिया। आखिर उसे खंडित करके भी क्या हम विभाजन रोक पाए?

चिट्ठी 1

इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 07 नवंबर, 1875 को उस समय की थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता अपने हाथ में लेने पर ब्रिटिश सरकार ने 'गॉड सेव द क्वीन' को गाना अनिवार्य किया था। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने यह गीत भारत माता की स्तुति और उसकी शक्तियों को प्रतिबिंबित करते हुए लिखा था।

1896 में कांग्रेस के कोलकाता (तब कलकत्ता) अधिवेशन में गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर ने इसका गायन किया, लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो काकीनाडा अधिवेशन (1923) में उन्होंने वंदेमातरम का विरोध कर दिया। इसके पहले के सभी अधिवेशनों में उद्घाटन के समय संपूर्ण वंदेमातरम का गायन होता रहा था। यहां भी परंपरागत रूप से वंदेमातरम के गायन का कार्यक्रम निर्धारित था। गायन के लिए प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को बुलाया गया था। गायन आरंभ होते अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर खड़े हो गए और उन्होंने इसे बंद करने को कहा, लेकिन पं. पुलस्कर ने इसका गायन जारी रखा। अध्यक्षता कर रहे मौलाना जौहर मंच छोड़कर चले गए, लेकिन बाद में इस विरोध के परिणामस्वरूप कांग्रेस ने एक कमेटी बनाकर इसके कई अंशों को काट दिया। इस कमेटी की रिपोर्ट को 1937 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर केवल पहले दो छंद ही स्वीकार किए गए। साथ ही इसके अनिवार्य गायन से कुछ लोगों को मुक्ति दे दी गई।

प्रश्न यह है कि क्या वंदेमातरम को खंडित करने से भारत विभाजन की विभीषिका रुक सकी? संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 को खंडित छंदों को राष्ट्रगीत की मान्यता प्रदान की, किंतु फिर भी एक वर्ग द्वारा इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। इसी खंडित वंदेमातरम को गाने से कुछ लोगों द्वारा संसद में इन्कार किया गया। अभी 29 अक्तूबर को जब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक नवंबर से सात नवंबर तक सभी स्कूलों में वंदेमातरम के सामूहिक गायन का आदेश दिया तो एक पक्ष ने विरोध किया।

वंदेमातरम का विभाजन इस आधार पर कर दिया गया कि इसमें दुर्गा, सरस्वती की स्तुति है। जब हम भारत माता को ही दुर्गा और सरस्वती के रूप में देख रहे हैं तो विरोध औचित्यहीन है। इसे उदात्त भाव से सभी को स्वीकार करना चाहिए।

■ सर्वेश कुमार सिंह, लखनऊ

इस जीत ने आगे का रास्ता दिखाया है

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर 'वूमेन इन ब्लू' ने वर्षों का लंबा इंतजार खत्म किया। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों, संघर्षों और उम्मीदों की ऐतिहासिक परिणति है। इस जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जैसे वैश्विक हस्तियों ने भी भारतीय टीम को बधाई देते हुए इसे 'ऐतिहासिक और प्रेरणादायी क्षण' बताया।

चिट्ठी 2

यह जीत केवल एक खेल की जीत नहीं, बल्कि नारी शक्ति, परिश्रम और आत्मविश्वास की विजय है। इसने यह साबित कर दिया कि जब अवसर और प्रोत्साहन समान हों, तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में इतिहास रच सकती हैं। आने वाले समय में यह सफलता भारतीय युवाओं विशेष रूप से लड़कियों को प्रेरित करेगी कि वे भी बड़े सपने देखें और उन्हें साकार करने के लिए निर्भीक होकर आगे बढ़ें। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की यह जीत देश की नई दिशा का प्रतीक है, जहां प्रतिभा का सम्मान लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि प्रदर्शन और जुनून से तय होता है।

■ विभूति बुपक्या, दिल्ली

इनकी **चिट्ठियां** भी सराहनीय रहीं

मेरठ से डॉ. नरेन्द्र टोंक, रायबरेली से नरेन्द्र नाथ, मेरठ से मनुदेव वैदिक, फिरोजाबाद से शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, गढ़वाल से लक्ष्मण पुंडीर, रुड़की से ललित शंकर, बरेली से सीमा गुप्ता, रुड़की से डॉ. श्रीगोपाल नारसन, इंदौर से अमृतलाल मारू, बड़वानी से नरेंद्र तिवारी, बड़वानी से प्रो. आरके जैन, उज्जैन से हेमा हरि उपाध्याय, झाबुआ से अरविन्द रावल, पटना से मुकेश कुमार मनन।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

कुछ चीजें सिर्फ यहीं पाई जाती हैं

दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, जो अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। सोकोत्रा आइलैंड पर कुछ चीजें ऐसी हैं, जो सिर्फ वहीं पाई जाती हैं।

यमन में एक आइलैंड है, जिसे दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जगह कहा जाता है। इस जगह का नाम है सोकोत्रा आइलैंड। यह जगह विचित्र इसलिए है क्योंकि यहां पर कई ऐसे जीव-जन्तु हैं, जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। इस आइलैंड पर जाने के बाद आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं, जहां एलियन्स का राज चलता है। यहां मौजूद हर एक चीज एलियन प्रजाति की लगती है।

इस जगह से जुड़ी सबसे खास बात ये है कि यहां पाए जाने वाले 825 पौधों की प्रजाति में से 37 फीसदी प्रजातियां, रेप्टाइल प्रजाति में से 90 फीसदी प्रजातियां और घोंघे की 95 फीसदी प्रजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ इसी आइलैंड पर पाई जाती हैं। दुनिया में और कहीं नहीं मिलतीं. यहां कई तरह के जमीनी पक्षी और समुद्री पक्षी भी पाए जाते हैं. यहां के सबसे अनोखे पेड़ माने जाते हैं ड्रैगन्स ब्लड पेड़. सभी पेड़ों की पत्तियां, डाल, ग्रैविटी की वजह से नीचे की तरफ लटकते हैं पर इस पेड़ की बात अनोखी हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ घूमा रहता है. इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये उल्टे किए गए छाते हैं. इस जगह पर अजीबोगीरब बॉटल ट्री भी मिलते हैं. इसका निचला हिस्सा मोटा, मगर ऊपरी हिस्सा बेहद पतला होता है. ऐसा माना जाता है कि ये बॉटल ट्री इस आइलैंड के पूरी तरह अस्तित्व में आने से पहले यहां पर थे। ये सिर्फ इसी जगह पर पाए जाते हैं। यह आइलैंड दुनिया के सबसे दुर्लभ रेप्टाइल्स का भी घर है. वर्म स्नेक, स्किंक (बभनी), गेको छिपकली, मोनार्क गिरगिट आदि जैसे मिलते हैं। सोकोत्रा आइलैंड की पारिस्थितिकी तंत्र में असामान्य संतुलन है, जो इसे एक अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। यह आइलैंड जिज्ञासा और शोधकर्ताओं के लिए अनूठी जैविक विविधता के अध्ययन का विषय है।

■ रेखा गोयल, रोहतक

जाने कहां चले गए तुम

अभिनेत्री जरीन खान और उनके अभिनेता-पति संजय खान की एक यादगार तस्वीर। जरीन खान का 7 नवंबर को मुंबई में देहांत हो गया।
■ गोपाल कश्यप, लाहौल स्पीती

छायानट

जब दिलीप ने सुने सुलक्षणा के सुर

कोलकाता के एक समारोह में नौ साल की बालिका गाना गा रही थी। सामने अभिनेता दिलीप कुमार बैठे थे। वह बालिका के गाने से इतने प्रभावित हुए कि बोले- इसे तो मुंबई आना चाहिए। इसका भविष्य वहां है। इस तरह सुलक्षणा पंडित का मुंबई का सफर शुरू हुआ। यह सफर इतना आसान भी नहीं रहा। उस समय पंडित परिवार कठिन दौर से गुजर रहा था। मुंबई में रहने के लिए न तो कोई जगह थी और न ही पैसे। सुलक्षणा के पिता उन्हें और उनके भाई को लेकर दिलीप साहब के घर चले गए। दिलीप साहब बहुत दयालु थे। उन्होंने परिवार को अपने एक घर में रखा और सुलक्षणा को पैर जमाने में मदद भी की। दिलीप कुमार शूटिंग पर सुलक्षणा को साथ ले जाते और निर्माताओं, निर्देशकों के सामने उनसे गाने को कहते। इस तरह धीरे-धीरे उन्हें शो मिलने लगे। उन्होंने लता मंगेशकर के साथ लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल के एक गाने 'सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से' में कुछ पंक्तियां गाई थीं। किशोर कुमार ने फिल्म 'दूर का राही' में अपने संगीत निर्देशन में सुलक्षणा को पार्श्व गायन का पहला मौका दिया। गाना था 'बेकरार दिल तू गाए जा'। इसमें किशोर कुमार ने भी एक अंतरा गाया। यह गाना सफल रहा।

■ ब्रह्मानंद शुक्ला, हरिद्वार

विदेश नीति पर विचार की जरूरत

ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात ने भारत की चिंता बढ़ा दी है, साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के समीकरण भी बिगड़े हैं। पश्चिम एशिया के देश भारत के बिना इस्राइल से संबंध बढ़ा रहे हैं। अब विनम्रता दिखाकर नीति पर पुनर्विचार करने का समय है।

पी चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय मंत्री

डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दुनिया के प्रभावशाली नेता हैं। दूसरे कद्दावर नेताओं में व्लादिमीर पुतिन और बेंजामिन नेतन्याहू भी आते हैं। ये वे नेता हैं, जिनके शब्द और फैसलों का अच्छा और बुरा असर सिर्फ इनके देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया में पसर जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन प्रभावशाली नेताओं की सूची में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि भाजपा इस बात का दावा करती है कि वह उक्त नेताओं की सूची में शामिल हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है।

आर्थिक तस्वीर

भारतीय अर्थव्यवस्था आकार के नजरिये से अमेरिका और चीन से बहुत छोटी है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखा जाए तो रूस और इस्राइल के नागरिकों से हम पीछे हैं। आंकड़े देखिए -

देश	जीडीपी का आकार	प्रति व्यक्ति आय
अमेरिका	30.51 ट्रिलियन	89,000
चीन	19.23 ट्रिलियन	13,800
रूस	2.54 ट्रिलियन	17,500
इस्राइल	0.6 ट्रिलियन	54,000
भारत	4.19 ट्रिलियन	2,900

(2025 के अनुमानित आंकड़े अमेरिकी डॉलर में हैं।)

अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में सात गुना और चीन की तुलना में साढ़े चार गुना बड़ी है। भारत सबसे बड़ी और तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो सकती है, लेकिन अभी जीडीपी को दोगुना करने में 10 साल लग जाएंगे। इस बीच भले ही अमेरिका और चीन की जीडीपी धीमी गति से बढ़े, लेकिन उसका आधार बड़ा होने के कारण वह और बड़ी हो जाएगी। संभव है कि भारत, अमेरिका और चीन की जीडीपी का अंतर पहले के मुकाबले और बढ़ जाए। गौरतलब है कि रूस और इस्राइल की जीडीपी आकार में छोटी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय भारत से क्रमशः छह गुना और 18 गुना अधिक है। दुनिया में यह गणित भारत के शासकों को छोड़कर सब नेता जानते हैं।

जी-2 के संकेत

भारत की विश्व में पहचान उसके लोकतंत्र, इतिहास, प्राचीन संस्कृति, शांति स्थापित करने में प्रयासों की भूमिका, जनसंख्या, बड़ा बाजार और संभावनाओं की वजह से है, न कि इसलिए कि भारत एक महाशक्ति है। दूसरे देशों का हित इस बात में है कि भारत तथा पाकिस्तान, दोनों के साथ शांतिपूर्वक व्यापारिक रिश्ते रखें। भारत के मित्र होने का अर्थ यह नहीं होता कि वे पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे। वे दोनों देशों से संबंध रखना चाहेंगे।

इसके अलावा दुनिया तेजी से बदल रही है। 2023 में भारत ने जोर देकर कहा कि उसने जी-20 सम्मेलन की मेजबानी की, लेकिन जी-20 बैठक और नेताओं का शिखर सम्मेलन एक वार्षिक आयोजन है और इसकी मेजबानी रोटेशन के आधार पर तय होती है। ब्राजील 2024 में मेजबान था, दक्षिण अफ्रीका 2025 के नवंबर में मेजबानी करेगा और अमेरिका को 2026 में यह करने का मौका मिलेगा। जी-20 की मेजबानी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दूसरा देश इस पर इतना शोर नहीं करता।

जी-8 और जी-7, जी-20 से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमारे पास अब जी-2 के रूप में एक नया मुद्दा है। इसमें बैठक से पहले और बाद में ट्रंप ने शी जिनपिंग को बराबरी का दर्जा दिया। ऐसा वह नरेंद्र मोदी के लिए कभी नहीं करेंगे। इस मौके पर ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति की खूब तारीफ की, जबकि शी जिनपिंग अपने स्वभाव के अनुसार रहस्यमयी बने रहे। बहुध्रुवीय दुनिया की चाहे कितनी बातें की जाएं, असल में दुनिया में केवल दो महाशक्तिया हैं और रूस उनके करीब है। अमेरिका कल तक अपनी सुरक्षा को लेकर जो खतरा बता रहा था, अचानक वह गायब हो गया है। इन हालात में क्वाड का महत्व कम हो जाएगा।

व्यापार का उतार-चढ़ाव

- अमेरिका ने चीन के साथ व्यापारिक प्रगति करते हुए दुर्लभ धातुओं और सोयाबीन के व्यापार को लेकर एक छोटा समझौता कर लिया है। जल्द ही दोनों देश टिकटॉक के मामले का भी हल निकाल सकते हैं। भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने के लिए काफी दिनों से बात चल रही है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है।
- अमेरिका-चीन के बीच भी टैरिफ को लेकर टकराव हुआ था, लेकिन बुसान में दोनों नेताओं के मिलने के बाद तकनीक हस्तांतरण, निर्यात नियंत्रण, पोर्ट शुल्क पर सहमति बन गई। दोनों देश टैरिफ धीरे-धीरे कम करने को राजी हैं। भारत पर लगाए सख्त टैरिफ को लेकर अमेरिका ने नरम रुख नहीं अपनाया है।
- चीन की कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध अमेरिका ने अभी हटाए नहीं हैं। भारतीय कंपनियां रूसी तेल खरीदती हैं तो उन पर भी प्रतिबंध जारी रहेंगे।
- अमेरिका ने अपने बाजार में चीन के उत्पादों को मिलने वाली विशेष पहुंच कम कर दी है। इसी तरह ऐसा लगता है, 2019 में भारत के उत्पादों को मिला विशेष लाभ बंद हो सकता है।

भारत की चिंता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप से आखिरी मुलाकात 14 फरवरी, 2025 को हुई थी। हाल में तीन मौके ऐसे थे, जब मोदी-ट्रंप मिल सकते थे। पहला मौका कनाडा में हुए जी-7 शिखर सम्मेलन में आया। तब ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को वाशिंगटन में 'स्टॉप ओवर' के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वह नहीं गए। मेरे विचार से यह निर्णय सही था। दूसरा मौका तब आया, जब गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें मिस्र जाना था, लेकिन वह नहीं गए। तीसरा मौका हाल में कुआलालंपुर में हुआ आसियान शिखर सम्मेलन रहा। इसमें प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। मुझे लगता है, यह निर्णय सही नहीं था। यह माना जा रहा है कि मोदी ट्रंप से द्विपक्षीय संवाद करने से बचना चाहते हैं।

ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाया था। दोनों देशों को व्यापार नहीं करने की धमकी दी और चौथे दिन युद्ध रुक गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप के इस दावे का खंडन सार्वजनिक रूप से या संसद में नहीं किया। यही नहीं, शी जिनपिंग को कभी उनके सैनिकों द्वारा की गई घुसपैठ और अवैध कब्जे को लेकर कुछ नहीं कहा।

ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात ने भारत की चिंता बढ़ा दी है, साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के समीकरण भी बिगड़े हैं। देखा जाए तो भारत दक्षिण एशिया में अकेला पड़ गया है। पश्चिम एशिया के देश भारत के बिना इस्राइल से संबंध बढ़ा रहे हैं। अब विनम्रता दिखाकर नीति पर पुनर्विचार करने का समय है।

Licensed by The Indian Express Limited

संस्कृत से जन्मा राष्ट्रगीत 'वंदेमातरम'

शास्त्री कोसलेन्द्रदास

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक युग में जिस गीत ने समूचे राष्ट्र के जनमानस को एक सूत्र में बांधा, वह था बंकिमचंद्र चटर्जी का 'वंदेमातरम'। यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ (1882 ई.) में अंतर्निहित है, किंतु इसकी आत्मा और स्वर संस्कृत भाषा में गूंजते हैं। बंकिमचंद्र ने भली प्रकार समझा था कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का मूल स्रोत संस्कृत है। संस्कृत ही वही भाषा है, जो सहस्राब्दियों से भारतभूमि के ज्ञान, धर्म, दर्शन और राष्ट्रभाव की वाहक रही है। अतः उन्होंने जब मातृभूमि के गौरव का गीत रचा, तो उसकी आरंभ और समापन संस्कृत में किया है - 'वंदे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम। शस्यश्यामलां मातरम।'

खुला आकाश

बंकिमचंद्र की दूरदृष्टि अद्भुत थी। उन्होंने संस्कृत को राष्ट्र की आत्मा और बांग्ला को उसकी वाणी बनाया। इस प्रकार यह गीत केवल साहित्यिक रचना नहीं, बल्कि भारतीय भाषिक-सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया।

इनमें निहित सौंदर्य और भावनात्मक शक्ति केवल काव्य नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का घोष है। इस गीत का मध्यांश बांग्ला भाषा में है, जिससे यह जनभाषा से जुड़ा रहा, पर इसकी संरचना और प्रभाव का मूल संस्कृत में ही स्थित है। बंकिमचंद्र की यह दूरदृष्टि अद्भुत थी कि उन्होंने संस्कृत को राष्ट्र की आत्मा और बांग्ला को उसकी वाणी बनाया। इस प्रकार यह गीत केवल साहित्यिक रचना नहीं, बल्कि भारतीय भाषिक-सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया। भाषाशास्त्री बांग्ला को संस्कृत के एकदम नजदीक बताते हैं, जिसमें सैंकड़ों शब्द संस्कृत से यथावत उतर आए हैं।

'वंदे मातरम' ने भारतीयों के हृदय में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, गौरव और त्याग का भाव उत्पन्न किया। यह गीत स्वतंत्रता-आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय मंत्र बन गया। इसके संस्कृत शब्दों ने भारतीयों को यह अनुभूति कराई कि स्वातंत्र्य की प्रेरणा पश्चिम से नहीं, हमारी अपनी परंपरा और भाषा से ही उत्पन्न होती है।

बंकिमचंद्र चटर्जी ने अपने इस गीत के माध्यम से यह सिद्ध किया कि संस्कृत कोई प्राचीन या जड़ भाषा नहीं, बल्कि भारत की जीवित आत्मा है। उसके शब्दों में जो दिव्यता और ओज है, वही राष्ट्र को एकता और स्वाभिमान का संबल प्रदान कर सकता है। इसीलिए 'वंदे मातरम' आज भी भारत के स्वतंत्रता-संगीत का अमर स्वर है, जिसमें संस्कृत भाषा की पवित्रता और भारतमाता की महिमा एकाकार होकर गूंजती है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid

काम के बोझ से दरकते रिश्ते

क्यों होता है 'बर्नआउट सिंड्रोम?' यह एक ऐसी परिस्थिति है, जो अक्सर अत्यधिक काम के दबाव से उपजती है। वे लोग, जिनके निजी जीवन में पेशेगत अनिवार्यताएं दखल देने लगती हैं, वे अवसाद अथवा हिंसक मनोवृत्ति की चपेट में आ जाते हैं। भीमेश बाबू इसी का शिकार बने। उम्मीद थी कि कोविड के बाद यह सिलसिला खत्म हो जाएगा, पर इसमें बढ़ोतरी होती गई।

आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

शशि शेखर

आजकल

क्या भीमेश बाबू को जानते हैं आप? इस महीने की शुरुआत में अपनी त्रासद मौत की वजह से वह समूचे देश में चर्चा का विषय बन गए थे। कैसे हुआ उनका देहांत? उनकी मृत्यु से पेशेवरों के बीच प्रचलित एक पुरानी बहस क्यों पुरगर्म हो उठी है?

पहले इस झकझोर देने वाले घटनाक्रम पर गौर करते हैं। रात एक बजे जब अंग्रेजी कैलेंडर 2 नवंबर की आमद की मुनादी कर चुके थे, तब भीमेश बेंगलुरु के एक डाटा डिजिटल बैंक में रोजमर्रा के काम निपटाकर घर जाने की तैयारी में थे। किसी वजह से तेज रोशनी उनकी आंखों में चुभती थी और वह अक्सर साथियों से अनावश्यक लाइट बुझाने को कहा करते थे। उस रात भी उन्होंने एक कनिष्ठ सहयोगी से बत्तियां बुझाने को कहा, लेकिन वह भड़क उठा। उसने भीमेश पर हमला बोल दिया, जो इतना घातक था कि बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

इस शर्मनाक घटना ने एक बार फिर 'वर्कलाइफ बैलेंस' की पुरानी बहस को जिंदा कर दिया है।

भारत में कार्यस्थल पर बढ़ते काम के बोझ और दरकते रिश्तों ने लोगों को मनोविकारों की ओर धकेलना शुरू कर दिया है। तमाम सर्वेक्षणों के अनुसार आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर तेज कदम बढ़ा रहा भारत 'बर्नआउट एपिडेमिक' के जबड़े में भी समाता जा रहा है। इस नए कारोबारी मुहावरे का अर्थ है- काम के अत्यधिक बोझ से टूटन।

कई भरोसेमंद सर्वेक्षण बताते हैं कि हमारा देश लगातार उन देशों के शीर्ष पर बना हुआ है, जहां काम का समय स्थापित मानक से कहीं ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, पूरी दुनिया में छह कार्यदिवसों के सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करने का रिवाज है। इसके उलट भारत कार्य की समय-सीमा के मामले में संसार के उन 13 देशों में शामिल है, जहां काम के घंटे सर्वाधिक हैं। इसका दुष्परिणाम सामने है। एक शोध के दौरान देश में 60 फीसदी से अधिक पेशेवरों में 'बर्नआउट' के लक्षण पाए गए हैं। हमारे यहां हालात पहले भी अच्छे नहीं थे, पर कोरोना के दौरान गजब की गिरावट देखी गई। उन दिनों लोग घरों से काम करते थे और उन्हें लगातार खुद को 'लॉग इन' रखना होता था।

क्यों होता है 'बर्नआउट सिंड्रोम?'

यह एक ऐसी परिस्थिति है, जो अक्सर अत्यधिक काम के दबाव से उपजती है। वे लोग, जिनके निजी जीवन में पेशेगत अनिवार्यताएं दखल देने लगती हैं, वे अवसाद अथवा हिंसक मनोवृत्ति की चपेट में आ जाते हैं। भीमेश बाबू इसी का शिकार बने। उम्मीद थी कि कोविड के बाद यह सिलसिला खत्म हो जाएगा, पर इसमें बढ़ोतरी होती गई। अब नए डिजिटल उपकरणों के जरिये घर या दफ्तर से काम करने वाले लोगों की सतत निगरानी की जाती है। यही नहीं, 'फील्ड' में काम करने वाले पेशेवरों को भी अपनी 'जीपीएस लोकेशन' शेयर करनी पड़ती है।

शुरुआत में तो इस तरह की निगरानी उत्पादकता बढ़ाने वाली साबित हुई, लेकिन अब यह प्रक्रिया तमाम विरोधाभास जन रही है।

कई शोध बताते हैं कि काम की लंबी पारियां अच्छे नतीजे देने के बजाय कंपनियों का दोतरफा नुकसान कर रही हैं। आमतौर पर ऐसा पाया गया है कि 20 प्रतिशत से अधिक पेशेवर आठ से नौ घंटे की पारी में सिर्फ ढाई से तीन घंटे सर्वोत्तम परिणाम दे पाते हैं। धीमे-धीमे उनमें सुस्ती और ऊब के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। यहां भी लैंगिक असमानता भारतीयों का पीछा नहीं छोड़ती। मानव संसाधन की विशेषज्ञ एक संस्था ने पाया कि कार्यस्थल पर अत्यधिक दबाव और उससे उपजे पारिवारिक तनाव की वजह से नौकरी छोड़ने वालों में महिलाओं की तादाद काफी अधिक है।

आईटी और तकनीकी सेक्टर इस मामले में ज्यादा निर्मम साबित हो रहे हैं। उनके ज्यादातर ग्राहक धरती के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए इन क्षेत्रों में काम करने वालों को उनके समय के हिसाब से खुद को ढालना होता है। इसके अलावा भाषा, व्यवहार और तकनीकी दिक्कतें भी उन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। यही नहीं, उन्हें कभी-कभी 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। सप्ताह में पचास से अधिक घंटों की ड्यूटी इन क्षेत्रों में आम है।

कई क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां कर्मचारियों से हरदम उपलब्धता की उम्मीद की जाती है। उन्हें ई-मेल, वाट्सएप अथवा कंपनी के निजी संदेश सिस्टम पर उपलब्ध रहना होता है। जो दिन-रात की परवाह किए बिना तत्काल जवाब दे देते हैं, उन्हें समर्पित और सक्षम के जुबानी तमगों से नवाजा जाता है। जिनसे थोड़ी-बहुत देर हो जाती है, वे 'कामचोर' करार दे दिए जाते हैं। इससे काम लेने वालों और काम करने वालों के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। कभी-कभी यह जानलेवा भी साबित होती है।

भीमेश बाबू से पहले अन्ना सेबेस्टियन पेरिल का मामला खबरों में सुर्ख हुआ था। एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी शुरू करते वक्त 25 वर्षीय अन्ना का दिल बल्लियों उछल रहा था, लेकिन 14 महीने के भीतर वह हृदयाघात से चल बसीं। अन्ना की असामयिक मौत के बाद उनकी मां ने उस कंपनी के आला अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न और निरंतर 14 घंटे तक काम लेने के आरोप लगाए थे। ऐसे दर्जनों मामले लोगों का ध्यान खींचते रहे हैं।

दुर्भाग्य से यह सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इससे सिर्फ कामगारों का ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े कॉरपोरेट घरानों को हानि उठानी पड़ रही है। इसका दोषी कौन है? व्यावसायिक संस्थान या उनके मानव संसाधन विभाग? कतई नहीं। अगर यह राष्ट्रीय आपदा बन रही है, तो इसके लिए राष्ट्रीय नीति की भी दरकार है। कुछ देशों ने इस मुद्दे पर बेहतरीन काम किया है।

मसलन, फ्रांस में शाम सात बजे से सुबह आठ बजे के बीच आधिकारिक ई-मेल या वाट्सएप संदेश भेजने पर पाबंदी है। कई पश्चिमी देशों में पेशेवरों को सलाह दी जाती है कि वे सुबह उठते ही अपने मोबाइल फोन चेक न करें और कुछ समय खुद को भी दें। इसके अलावा कुछ देशों में 'लॉग इन' अथवा 'डेस्क टाइम' की जगह उत्पादकता मापने के मानक गढ़े जा रहे हैं। वहां 'डिजिटल बाउंड्रीज' तय करने के साथ सवैतनिक छुट्टियों पर जाने की अनिवार्यता भी गढ़ी जा रही है।

तमाम भारतीय कॉरपोरेट इस दिशा में बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसी राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, जो कॉरपोरेट और कामगारों का साझा विकास तय कर सके, क्योंकि इंसान और उत्पादकता का आदिम रिश्ता है। आज जब मानवीय बल और बुद्धि पर तकनीक हावी हो चली है, तब नए मानकों का निर्धारण जरूरी हो गया है।

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

जीना इसी का नाम है

मित्तल पटेल
समाजसेविका

खानाबदोशों के लिए वह किसी मसीहा से कम नहीं

आज सिर्फ उनकी बदौलत गुजरात के साढ़े सात लाख खानाबदोशों के पास वैध पहचान-पत्र है, हजारों को घर और तमाम सरकारी सुविधाएं हासिल हैं। लगभग पांच हजार नौजवान नौकरी कर रहे हैं और हजारों स्कूल जा रहे हैं। अब ऐसी नारी शक्ति को देश कैसे न सलाम करेगा?

जिंदगी की खूबसूरती उसकी अनिश्चितता में ही है। हम बनना कुछ और चाहते हैं, बन कुछ और जाते हैं। इसीलिए सयाने लोग कहते हैं, जीवन के हरेक क्षण को भरपूर जीने वाले लोग ही अपने देश-समाज और इंसानियत को कुछ ऐसा देकर जाते हैं, जिसके लिए आने वाली नस्लें उनको याद करती हैं। मित्तल पटेल ऐसे ही खास लोगों में से एक हैं।

करीब 44 साल पहले मेहसाणा (गुजरात) के शंखलपुर गांव में मित्तल पैदा हुईं। माता-पिता, दोनों खेती-किसानी से जुड़े थे। उन्होंने बेटी को बड़े लाड से पाला। मित्तल एक ऐसे माहौल में बड़ी हुईं, जहां लड़की होने के कारण उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। इसीलिए उनके गांव में जब कोई बहुरूपिया किसी देवता का रूप धरकर आता या सांप के खेल व रस्सियों पर अपनी कलाबाजी दिखाता या फिर चाकू-छुरी पर सान चढ़ाने की आवाजें लगाता, मित्तल इन हुनरमंदों को सराहने वाली भीड़ की पहली कतार में होतीं। तब उन्हें कहां पता था कि गांव की जरूरतें पूरी करने वाले और सबका मनोरंजन करने वाले ये लोग खानाबदोश जनजाति के हैं।

पढ़ने-लिखने में तेज मित्तल पटेल का हर परीक्षा-परिणाम माता-पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर देता और ऐसे में उन्होंने तय किया कि बेटी जो कुछ भी पढ़ना चाहेगी, वे पढ़ाएंगे। बारहवीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने के बाद मित्तल अहमदाबाद आ गई थीं। दरअसल, स्कूल के दिनों से ही वह आईएएस बनने के सपने देखा करती थीं और इसकी तैयारी के लिए तब अहमदाबाद में पढ़ना उन्हें मुनासिब लगा था। वहां पहुंचकर मित्तल ने सोचा कि अगर पत्रकारिता में स्नातक किया जाए, तो यूपीएससी की तैयारी में भी मदद मिल जाएगी और एक पेशेवर डिग्री हाथों में होगी। लिहाजा, उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता पाठ्यक्रम में दाखिला ले लिया।

मित्तल पूरी गंभीरता से अपनी पढ़ाई में जुट गईं। साल 2004 की बात है। उन्हें पता चला कि 'चरखा' नाम का एक स्थानीय संगठन पत्रकारिता के बच्चों को विभिन्न विषयों पर शोध के लिए फेलोशिप देता है। मित्तल ने भी आवेदन किया और वह इस फेलोशिप के लिए चुन ली गईं। दक्षिण गुजरात के गन्ना मजदूरों के हालात को उन्होंने अपने अध्ययन का विषय बनाया। मित्तल यह तो जानती थीं कि ये मजदूर टेंट में रहते हैं, मगर वह बिल्कुल नहीं जानती थीं कि इनके टेंट और फौजी टेंटों में जमीन-आसमान का फर्क होता होगा।

नवंबर का पहला हफ्ता था। मित्तल इन मजदूरों से मिलने एक गांव पहुंची। मगर उनका 'पड़ाव' गांव से काफी दूर था। वहां पहुंचकर उन्होंने जो हालात देखे, तो उनके जैसे होश उड़ गए। वे प्लास्टिक से ढकी छोटी-छोटी झोंपड़ियां थीं। मित्तल यह सोचकर वहां गई थीं कि वे सब उनके गांव के आम मजदूरों की तरह होंगे। उनसे बात करके उनकी समस्याएं समझेंगी और

लौटकर अपना प्रोजेक्ट लिख लेंगी। मगर वहां के हालात झटके देने वाले थे। मित्तल ने एक ठेकेदार से संपर्क साधा, जो आदिवासी इलाकों से मजदूरों को उस पड़ाव में ले आते थे। मगर ठेकेदार ने यह कहते हुए उनको टाल दिया कि इनके बारे में लिखने लायक कुछ भी नहीं है। आप यहां से जाएं।

मित्तल जो देख रही थीं और ठेकदार जो बोल रहा था, वे दोनों नदी के दो किनारे की तरह थे। वह सोचने लगीं कि अब क्या किया जाए, शाम होने लगी थी। वहां रुकने की कोई व्यवस्था न थी। न उनके पास सर्दी से बचने के कपड़े थे। तभी एक नौजवान सात-आठ महीने के बच्चे को गोद में उठाए वहां आया। वे दोनों जख्मी थे। युवक के मुंह से खून बहता जा रहा था। उसने बताया कि वे खेतों में काम करके आ रहे थे। दो मोटरसाइकिल सवार उसकी पत्नी को जबरन उठा ले गए। विरोध करने पर जालिमों ने मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शा।

मित्तल ने सोचा कि अभी पुलिस आएगी। महिला को बरामद कर लाएगी। मगर आधे घंटे के बाद उन्होंने देखा कि सब कुछ सामान्य हो गया और सब अपनी-अपनी झोंपड़ी में जाकर खाना बनाने लगे। जब मित्तल ने पूछा कि आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, तो जवाब मिला- ठेकेदार नाराज हो जाएगा और उन्हें काम नहीं देगा। यह बेहद पीड़ादायक स्थिति थी। एक मासूम अपनी मां से बिछड़ गया था, पति-पत्नी अलग हो गए थे, पूरा परिवार बिखर गया था, मगर पेट भरने की मजबूरी ने सबकी जुबान पर ताले जड़ दिए थे।

मित्तल तब महज 23 साल की थीं। रात हो चुकी थी। एक अकेली महिला की झोंपड़ी में वह रात उन्होंने किसी तरह काटी। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने इन सबको इनके हाल पर छोड़ दिया, तो अफसर क्या खाक बनेंगी? अगले डेढ़ महीने तक वह उन आदिवासियों के बीच रहीं। उनकी परेशानियों को खुद जीकर देखा। मित्तल आदिवासियों की समस्याओं के निदान के लिए अधिकारियों व नेताओं से भी मिलीं, उन्हें मिलने वाली कम मजदूरी का मुद्दा उठाया, पर सबने बस यही कहकर टालने की कोशिश की कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं।

मित्तल ने उसी समय आईएएस बनने का सपना त्याग दिया। जब अधिकारियों के हाथों में कुछ है ही नहीं, तो फिर अफसर क्या बनना? पत्रकारिता में गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी उन्होंने मुख्यधारा के मीडिया में शामिल होने के बजाय हाशिये के लोगों की खिदमत का रास्ता चुना। एक अन्य फेलोशिप के तहत उन्होंने गुजरात के खानाबदोश लोगों को पहचान दिलाने की

मित्तल ने सोचा कि अभी पुलिस आएगी, महिला को बरामद कर लाएगी। मगर आधे घंटे के बाद उन्होंने देखा, सब अपनी-अपनी झोंपड़ी में जाकर खाना बनाने लगे। जब उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, तो जवाब मिला- ठेकेदार नाराज हो जाएगा और उन्हें आगे काम नहीं देगा।

पहल शुरू की। कोई सरकारी दस्तावेज न होने के कारण पुलिस अक्सर खानाबदोशों को ही अपराधी ठहरा देती थी।

मित्तल ने साल 2010 में 'विचरता समुदाय समर्थन मंच' की नींव रखी और आज सिर्फ उनकी बदौलत गुजरात के साढ़े सात लाख खानाबदोशों के पास वैध पहचान-पत्र है, हजारों को घर और तमाम सरकारी सुविधाएं हासिल हैं। लगभग पांच हजार नौजवान नौकरी कर रहे हैं और हजारों स्कूल जा रहे हैं। अब ऐसी नारी शक्ति को देश कैसे न सलाम करेगा?

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा

चोई होंग ही
ताइक्वांडो के पितामह

बिगड़ैल पहलवान ने जब धमकाया

खैर, किसी तरह से बात संभली, लेकिन पहलवान ने इस कमजोर युवक का गिरेबां पकड़कर, आंखों से क्रोध बरसाते हुए धमकाया कि जा रहे, तो जाओ, जाने दे रहा हूं, पर याद रखना, अब अगर कोरिया लौटकर आए, तो तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से बोटी-बोटी कर दूंगा।

वह किशोर इतना कमजोर था कि जरा-सा जोर शरीर पर पड़ते ही बिस्तर खोजने लगता था। उसकी इस कमजोरी से माता-पिता भी बहुत परेशान रहते थे। नाना उपाय किए गए, पर कमजोरी दूर न हुई। इसी कमजोरी का नतीजा था कि मन में हमेशा भय बैठा रहता था। वैसे तो पूरे कोरिया में भय का वास था, जापान ने ताकत से सबको दबा रखा था। एक बार तो ऐसी स्थिति बनी कि उस किशोर को स्कूल से निकाल दिया गया। पढ़ाई थम गई। वहां ऐसे बहुत लड़के थे, जिनकी पढ़ाई छूटी थी। हर तरफ बुरी संगत का साया था। ऐसे माहौल में ही उम्र जवानी की दहलीज पर चढ़ गई थी। कोरिया में गुजारा मुश्किल था, तो पिता ने युवा बेटे को जापान भेजने का फैसला किया, ताकि वहां जाकर बेटा कोई कला ही सीख ले, ताकि अपनी जिंदगी ठीक से बसर कर सके। उन्होंने जापान के क्योटो में अपने बेटे के लिए सुलेख विद्या सीखने का इंतजाम कर लिया। सफर की तैयारियां भी शुरू हो गईं।

उन्हीं दिनों एक निर्णायक घटना हुई। इस युवक का एक स्थानीय बिगड़ैल पहलवान से झगड़ा हो गया। मारपीट की नौबत आ गई, तभी किसी ने पहलवान को समझाया कि छोड़ दो इस लड़के को, यह तो वैसे भी अब क्योटो जा रहा है? इससे लड़कर क्या फायदा? पर कद-काठी से बहुत तगड़ा पहलवान तो हाथ चलाने पर उतारू था। खैर, किसी तरह से बात संभली, लेकिन पहलवान ने इस कमजोर युवक का गिरेबां पकड़कर, आंखों से क्रोध बरसाते हुए धमकाया कि जा रहे, तो जाओ, जाने दे रहा हूं, पर याद रखना, अब अगर कोरिया लौटकर आए, तो तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से बोटी-बोटी कर दूंगा।

तब कमजोरी का शिकार वह युवा थरथर कांप रहा था, भय से कंठ सूख रहा था, दिल बहुत तेज धड़क रहा था, एक भी शब्द मुंह से बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसने किसी तरह आंखों ही आंखों से और थोड़ा सिर हिलाते हुए पहलवान का आश्वस्त किया कि ठीक है, अब कोरिया नहीं लौटूंगा।

इस धमकी ने युवक का मनोबल तोड़कर रख दिया। वह सोच में पड़ गया कि ऐसे तगड़े पहलवान से लड़ना और बचना मुश्किल है, यह कभी न कभी पकड़कर अपनी बदमाशी को अंजाम देगा। इसकी फौलादी जकड़ में आने का परिणाम जीवन का अंत ही है। वह कई दिनों तक डरा-सहमा सोचता रहा। बहरहाल, क्योटो पहुंचकर सुलेख सीखने की शुरुआत हुई, पर सुलेख से आत्म-सुरक्षा संभव न थी। पहलवान सुलेख देखकर पसीजने वाला नहीं था। सोचते-सोचते ही समाधान निकला कि क्यों न खुद को लड़ने योग्य बनाया जाए। कोई ऐसी समर कला सीखी जाए कि कोई दुश्मन छू न सके। फिर क्या था, कद से छोटे और कमजोर उस युवा ने कराटे सीखने की शुरुआत की। कराटे सीखने को उसने जीवन-मरण का प्रश्न बना लिया, तो महज दो वर्ष में कराटे मास्टर बन गया, पर महज कराटे से मन न माना। उसे लगा कि हो सकता है, जब वह घर लौटे, तो पहलवान भी कराटे सीख चुका हो। ऐसे में, किसी ऐसी समर कला में पारंगत होना जरूरी है कि पहलवान की पकड़ से बचा जा सके। तब उस युवा का ध्यान प्राचीन कोरियाई मार्शल आर्ट ताइक्योन की ओर गया। पैरों के बल से ही लड़ने की यह कला पहलवान को पास आने से रोक सकती है, ऐसा मानकर इस युवक ने अभ्यास की शुरुआत की। तब भय यह भी सताया कि क्या पता, वह पहलवान भी ताइक्योन सीख गया हो, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि लड़ने की कोई अलग ही नई कला चाहिए। तब अनेक मार्शल आर्ट शैलियों से कुछ न कुछ लेकर उस युवक ने अपनी एक समर शैली बनाई, जिसे उसने ताइक्वां-डो नाम दिया।

बहरहाल, उसकी अस्थियों में बसा पहलवान का भय यहीं समाप्त नहीं हुआ, तो वह सेना में शामिल हो गया। लगभग पांच वर्ष बाद ही वह युवक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ जापानी सैन्य जवान चोई होंग ही के रूप में अपने घर कोरिया लौटा। तब उसकी ख्याति अपने इलाके में ऐसी हो गई थी कि उसे कमजोर जानकर धमकाने वाला पहलवान न जाने किस बिल में जा छिपा था।

अपनी विरल योग्यता से चोई होंग ही (1918-2002) सेना में पदोन्नत होते चले गए और एक दिन मेजर जनरल बने। उसके अगले साल 1955 में उन्होंने दुनिया को ताइक्वांडो के बारे में बताया। यह शानदार समर कला देखते-देखते दुनिया में लोकप्रिय हो गई। खुद कोरिया में इतनी लोकप्रिय हुई कि इसे राष्ट्रीय मार्शल आर्ट घोषित किया गया। 9 नवंबर को जन्मे चोई होंग ही ने ताइक्वांडो पर बेहतरीन पुस्तकों की रचना की, जो दुनिया भर में हाथों-हाथ बिकीं। वह ताइक्वांडो के पितामह कहलाते हैं और वह अपने अंतिम दिनों में उस बिगड़ैल पहलवान को याद करते हुए कहते थे कि उसकी धमकी ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

तुलसी के हुए तो वाम से गए

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

हिंदी के एक आचार्य ने कहा कि तुलसी पर बात करने को तरस गया। आचार्य जीवित होते, तो पूछता कि सर जी! इतने दिनों तक हिंदी के सर्वेसर्वा रहकर भी तुलसी पर बात करने को कैसे तरस गए? क्या किसी ने सेंसर लगाया? आप तो जब चाहते, तुलसी पर बात कर सकते थे।

आप बनारस के, तुलसी बनारस के, पचास साल तक हिंदी की सल्तनत आपके पास रही। ऐसे में, यह आत्म-स्वीकार कैसा, जिसमें आत्म-परिताप नहीं? यह तो अपने आपको माफीनामा देने जैसा है? भला आपको किसका डर था? तुलसी के राम से डर था या 'एंटी राम लॉबी' के साथ थे आप?

तुलसी का यही जादू है, जो ऐसे बहुतों को डराता है। तुलसी 440 बोल्ट के खुले तार हैं। छुआ, तो गए; न छुआ, तो उससे बचते-बचते रहे। तुलसी का यही काव्यात्मक तिलिस्म है कि तुलसी के हुए तो फिर और किसी काम के न रहे। तुलसी की एक चौपाई भी ऐसा कहती है : *सोइ जानइ जेहि देहु जनाई!/ जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई!!* राम ने जनाया, तो राम को जाने। जाने, तो राम के हुए और राम के हुए, तो वाम से गए। वाम से गए, तो क्रांति से गए, सेकुलर इतिहास से गए, साहित्य से गए। साहित्य से गए, तो साहित्य के करियर से गए।

तुलसी किसी के लिए सुविधा हैं, तो किसी के लिए दुविधा। वह ऐसी उक्ति हैं, जो एक ही वक्त में मुक्ति भी हैं और भुक्ति भी। तुलसी को पढ़े, तो वर्णवादी, मनुवादी, हिंदुत्ववादी, ब्राह्मणवादी, संघी, फासिस्ट हुए और यह सब हुए, तो आप साहित्य से गए। एक लेखक ने कभी 'जय जानकी जीवन' किया, तो प्रतिक्रियावादी कहलाया, सीआईए का एजेंट कहलाया। ऐसे ही, एक अन्य लेखक कुंभ-कुंभ करने लगा, तो धिक्कार को प्राप्त हुआ। स्व. आचार्य के मन में शायद ऐसे ही 'सेंसर' रहे होंगे, जो उनके चाहने से भी तुलसी पर बात न करने देते होंगे। इसी मानी में तुलसी हिंदी साहित्य की एक बड़ी आफत हैं।

तुलसी का यही जादू है कि वह एक ही समय में महाकवि भी हैं और उच्च कोटि के भक्त भी। *मानस* पढ़ते हुए हम साहित्य का आनंद तो लेते ही हैं, कुछ-कुछ भक्त भी बनते जाते हैं। तुलसी की यही ताकत अपनी ओर खींचती है, लेकिन डराती भी है। हिंदी के ज्यादातर आलोचक तुलसी के प्रति बेईमान रहे हैं। तुलसी को क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन *मानस* के धार्मिक भाव व राम के लीला भाव को निकालकर पढ़ाएंगे और इस तरह, तुलसी को 'सेकुलर कपड़े' पहनाना चाहेंगे और जब 'सेकुलर कपडे' तुलसी के राम जी को छोटे पड़ जाएंगे, तो फिर तुलसी को सामंती-वर्णवादी- प्रगति विरोधी कहकर, उनके भक्तों तक को पोंगापंथी आदि कहकर आम रामभक्त को भी दुश्मन बना लेंगे और जब अकेले पड़ जाएंगे, तो कहेंगे कि क्या करें, तुलसी के बारे में बात न कर पाए!

सच! जब कोई 'टेक्स्ट' बहुसंख्यक जनता की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, तो दरअसल वह सामान्य आलोचना से परे एक 'महाटेक्स्ट' बन जाती है, जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, जिसका विरोध करते-करते हम एक अपराध-बोध से भर जाते हैं। तुलसी हमें ऐसे ही अपराध-बोध से भरते हैं, जिसे हम सब हिंदी वाले महसूस करते हैं।

मैं जब भी *मानस* पढ़ता हूं, मुझे रोना आने लगता है। क्या यह अब तक, अपने जातीय कवि तुलसी और अपने राम से दूर चले आने का अफसोस है या स्वयं के राममय हो जाने का डर, जिसके होते ही मेरी कल्पित प्रगतिशीलता और सेकुलरिज्म की दुकान बंद हो सकती है? या ऊपर से थोपी गई आधुनिकता व प्रगतिशीलता के चक्कर में अपनी जातीय परंपरा को भूलते जाने और उस परंपरा से घृणा करते जाने की आदत को छोड़ अचानक परंपरा में समा जाने और इस तरह अब तक एक व्यर्थ का जीवन गुजारने का अफसोस होता है, जो मुझे रुलाता है? क्या आपको भी रुलाता है?

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 9 नवंबर, 2025

दैनिक जागरण

जब इच्छाएं सीमित होती हैं तब संतोष जन्म लेता है

नियमों की अनदेखी

यह अच्छा है कि सरकार बिना बीमा वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए इंश्योरेंस इन्फार्मेशन ब्यूरो बनाया जा रहा है, जहां सभी वाहनों का डाटा होगा। इस ब्यूरो के जरिये जिन वाहनों का बीमा नहीं पाया जाएगा, उनके मालिकों को चेतावनी संदेश भेजा जाएगा और उस पर ध्यान न देने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा किया ही जाना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रहे कि बात तब बनेगी, जब बीमा रहित वाहन चलाने वालों के खिलाफ सचमुच कठोर कार्रवाई की जाएगी। चूंकि अभी ऐसा नहीं किया जाता, इसलिए बड़ी संख्या में लोग बीमा खत्म होने के बाद भी उसके बगैर वाहन चलाते रहते हैं। यह स्थिति यही बताती है कि अपने देश में आवश्यक नियम-कानूनों का पालन न करने की प्रवृत्ति कायम है। यह प्रवृत्ति सब चलता है वाले रवैए को ही बयान करती है। यह प्रवृत्ति वाहन मालिकों के साथ-साथ सरकारी तंत्र की ढिलाई का भी नतीजा है। यह ढिलाई किस बड़े पैमाने पर बरती जा रही है, इसका पता इससे चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक आंकड़े के अनुसार देश में 50 प्रतिशत से अधिक वाहन बिना बीमा के चलाए जाते हैं। जब कभी बिना बीमा वाले वाहन दुर्घटना से दो-चार होते हैं, तब वाहन स्वामी के साथ हादसे के शिकार व्यक्ति को भी अतिरिक्त मुसीबत का सामना करना पड़ता है।

अपने देश में मार्ग दुर्घटनाओं और उनमें मरने एवं घायल होने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। बिना बीमा वाहन चलाने वाले दुर्घटना की स्थिति में अपने साथ-साथ दूसरों को संकट में ही नहीं डालते, मुकदमेबाजी का कारण भी बनते हैं। ऐसे लोग इससे बेपरवाह रहते हैं कि उनके वाहन का बीमा न पाए जाने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस बेपरवाही के मूल में है जुर्माने की राशि अधिक न होना और पकड़े जाने पर कुछ ले-देकर या रौब जमाकर छूट जाने का भरोसा होना। नियम-कानूनों की अनदेखी तभी होती है, जब उनके पालन का तंत्र निष्प्रभावी या नाकाम होता है। अपने देश में ऐसा हर क्षेत्र में होता है। इसी कारण सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में पड़ती रहती है और बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही है। आवश्यक केवल यह नहीं कि बिना बीमा वाहन न चलने दिए जाएं, बल्कि यह भी है कि अकुशल चालकों, खटारा वाहनों, खराब सड़कों के साथ-साथ यातायात नियमों की अवेहलना के चलते होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। इसके लिए केवल नियम-कानूनों को कठोर ही नहीं करना होगा, उन पर सही तरह अमल भी सुनिश्चित करना होगा। आम तौर पर ऐसा करने की घोषणा कर दी जाती है और कभी-कभी तो नियम-कानूनों में संशोधन भी कर दिया जाता है, लेकिन उनके पालन के अभाव में नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही रहता है।

हरित संकल्प

हरियाणा ने पराली प्रबंधन के क्षेत्र में एक नई चेतना का सूत्रपात किया है। आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में 77 प्रतिशत की कमी आई है। यह केवल सरकारी पहल की सफलता नहीं, बल्कि किसानों की चेतना, वैज्ञानिक दृष्टि और समाजिक उत्तरदायित्व के संगम का परिणाम है। हरियाणा सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में दो वर्षों में शून्य पराली जलाने वाला राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। यह लक्ष्य एक प्रशासनिक घोषणा मात्र नहीं, बल्कि हरियाणा की पर्यावरणीय पुनर्जागरण यात्रा का प्रतीक बन चुका है। करनाल और कुरुक्षेत्र जैसे जिलों में हुई प्रगति इस परिवर्तन की पूरी राह, संकल्प और संघर्ष को स्पष्ट करती है। त्रि-आयामी रणनीति, इन-सीटू, एक्स-सीटू और पशु चारे के रूप में पराली का उपयोग इस दिशा में ठोस नवाचार का उदाहरण है। जहां कभी धुएं ने आकाश को ढक लिया था, वहीं अब वही पराली ऊर्जा, चारे और उद्योग का संसाधन बन रही है। यह सोच कृषि को केवल उत्पादन नहीं, संरक्षण और पुनर्चक्रण की दिशा में ले जा रहा है। सरकार ने भी प्रोत्साहन योजनाओं में उदारता दिखाई है। किसानों को आर्थिक सहायता, तकनीकी सहयोग व वैज्ञानिक उपकरणों की उपलब्धता ने मुहिम को गति दी। अधिक नोडल अधिकारी एवं सतत उपग्रह निगरानी इस प्रतिबद्धता की गंभीरता को रेखांकित करते हैं।

> जब किसान ने उत्पादन से आगे बढ़कर संरक्षण चुना, हरियाणा की धरा ने एक बार फिर अपना संकल्प दोहराया है। प्रकृति को राहत दी है

वंदे मातरम् पर व्यर्थ का विवाद

संजय गुप्त

जब कभी वंदे मातरम् को मान-सम्मान देने या फिर उसका स्मरण करने की पहल होती है, उसके खिलाफ कुछ बेतुके स्वर उभर ही आते हैं

अवधेश राजपूत

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने को एक उत्सव के रूप में वर्ष भर मनाने का फैसला कर यही रेखांकित किया कि उनकी सरकार राष्ट्रीयता के प्रति विशेष अनुराग रखती है और वह प्रत्येक अनुकूल अवसर को राष्ट्रबोध जगाने के लिए उपयोग करती है। यह उनकी गहरी दृष्टि और दूरगामी सोच को प्रकट करता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ओर से रचित कालजयी गीत वंदे मातरम् से संबंधित उत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने जिस तरह स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने के साथ एक विशेष वेबसाइट लांच की, उससे यही पता चलता है कि वे इस अवसर को कितना महत्व दे रहे हैं। इस मौके पर दिए गए भाषण में उन्होंने वंदे मातरम् को एक मंत्र, एक संकल्प, एक साधना, आराधना आदि बताते हुए उसे वर्तमान से भी जोड़ा और कहा कि यह विकसित भारत के सपने को पूरा करने की प्रेरणा देने वाला है। निःसंदेह यदि देशवासी भारत को उन्नत बनाने के लिए समर्पण की उसी भावना से लैस हो जाएं, जिसका परिचय उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय वंदे मातरम् के उद्घोष के सहारे दिया था तो विकसित भारत के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। उस समय यह गीत पहले बंगाल और फिर पूरे देश के लिए स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, त्याग, देशभक्ति और देशसेवा के प्रति संकल्प का पर्याय बन गया था। इसने लाखों लोगों को स्वतंत्रता के लिए त्याग और संघर्ष करने को प्रेरित किया।

विश्व इतिहास में ऐसे किसी गीत का उल्लेख कठिनाई से ही मिलता है, जिसने करोड़ों लोगों को आंदोलित करने के साथ उन्हें आत्मबल प्रदान किया हो। ऐसा तब हुआ, जब वंदे मातरम् बांग्ला मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखा गया। 1882 में बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम् का प्रकाशन होते ही वह लोगों के आत्मा में रच-बस गया। इस गीत की खूबी यह रही कि इसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सभ्यतागत गौरव के साथ जोड़ने का काम किया। इसका प्रभाव इतना अधिक बढ़ा कि वह स्वतंत्रता संघर्ष के उद्घोष वाक्य में बदल गया। इससे घबराकर अंग्रेजी सत्ता ने उसे प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन इससे उसकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ी। इसी के साथ बढ़ा जनमानस की चेतना पर उसका प्रभाव। इस गीत की सराहना रवींद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरबिंदो आदि ने की। इसे कांग्रेस के अधिवेशनों में राष्ट्र गीत के रूप में गाया जाने लगा।

स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में कई पत्र-पत्रिकाओं ने वंदे मातरम् नाम से अपना प्रकाशन शुरू किया। इनमें से कुछ तो उर्दू भाषा के थे। इसके अतिरिक्त यह कई क्रांतिकारियों के बीच अभिवादन का विकल्प बन गया। एक तरह से यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रबल स्वर बना। वंदे मातरम् की महत्ता इससे भी समझी जा सकती है कि उसे राष्ट्रीय ध्वज के प्रारंभिक स्वरूप में भी स्थान मिला। जब यह गीत स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था, तब संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उसका बेतुका विरोध भी हुआ। मुस्लिम लीग ने उसे इसलिए सांप्रदायिक बताना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें भारत को एक माता के रूप में चित्रित किया गया था और उसकी आराधना पर बल दिया गया था। चूंकि कांग्रेस मुस्लिम लीग को संतुष्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने वंदे मातरम् को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता तो दी, पर उसके छह में से प्रथम दो छंदों को ही। शेष चार छंदों में ऐसा कुछ नहीं था, जिसे सांप्रदायिक कहा जा सकता। यदि ऐसा होता तो गांधी जी यह न कहते कि वंदे मातरम् बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शक्तिशाली युद्धघोष और साम्राज्यवाद विरोधी नारा था। नेहरू जी ने भी कहा था कि यह गीत भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। इसके बाद भी कांग्रेस की ओर से उसके दो छंद ही राष्ट्र गीत के रूप में स्वीकृत किए गए। गत दिवस प्रधानमंत्री ने इसका ही उल्लेख करते हुए कहा कि यहीं से विभाजनकारी राजनीति के बीज बोए गए। वंदे मातरम् से जुड़े इस विवाद के बाद भी संविधान सभा ने उसे राष्ट्रीय गीत और जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दी। इससे समझा जा सकता है कि इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में कितनी महती भूमिका निभाई।

अतीत में जन गण मन को लेकर भी ऐसी टिप्पणियां करके विवाद उठाए गए हैं कि उसकी रचना ब्रिटिश शासक के गुणगान के लिए की गई थी। अभी हाल में कर्नाटक के एक भाजपा सांसद ने फिर से ऐसा कहा। इस तरह की बातों से बचा जाना चाहिए। राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान को बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए। यह सभी को सुनिश्चित करना चाहिए कि न राष्ट्रीय गीत की अवहेलना हो और न ही राष्ट्र गान की। दुर्भाग्य से ऐसा रह-रहकर होता रहता है। कई बार संसद में कुछ सांसद वंदे मातरम् के गायन में शामिल नहीं होते। यह ठीक नहीं कि वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री की ओर से वर्ष भर चलने वाले आयोजन का शुभारंभ किए जाते ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने वंदे मातरम् को कभी सम्मान नहीं दिया। आखिर जब दोनों दल वंदे मातरम् की महत्ता से सहमत हैं और उसे राष्ट्र की चेतना को जगाने वाला गीत मानते हैं तो आरोप-प्रत्यारोप क्यों?

महाराष्ट्र में सपा नेता अबू आजमी ने वंदे मातरम् को धार्मिक गीत बताते हुए जिस तरह उसे गाने से इन्कार कर दिया, उससे पता चलता है कि कुछ लोग किस तरह राष्ट्रीय महत्व के प्रतीकों के सहारे विभाजनकारी राजनीति करने के आदी हो गए हैं। अबू आजमी ने वंदे मातरम् को नमाज के समतुल्य बताया। यह खेद की बात है कि जब भी कभी वंदे मातरम् को मान-सम्मान देने या फिर उसका स्मरण करने की पहल होती है, उसके खिलाफ कुछ बेतुके स्वर उभर ही आते हैं। महाराष्ट्र के अलावा ऐसे स्वर जम्मू-कश्मीर में भी सुनाई दिए हैं। ऐसे अवांछित-अनावश्यक स्वरों से वंदे मातरम् की महत्ता-लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यह अवश्य हो सकता है कि भाजपा ऐसे स्वरों को अपने पक्ष में भुनाने के लिए सक्रिय हो।

response@jagran.com

शेरू, मोती और झबरा के भी दिन बहुरे

हास्य-व्यंग्य

अरुणेंद्र नाथ वर्मा

सड़कों से हटाए जा रहे कुत्तों को इससे संतोष करना चाहिए कि वे सुरक्षा बलों में सेवाएं देने के काबिल समझे जा रहे

बारह बरस में घूरे के भी दिन फिर जाते हैं। कुत्तों की पूंछ इसका अपवाद है। वह बारह बरस तक नली में डाल कर रखी जाने पर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही बनी रहती है, लेकिन एक नई खबर बताती है कि अब देसी कुत्तों के दिन फिर रहे हैं। खबर यह है कि सशस्त्र बलों के श्वान दस्तों में भारतीय नस्लों के कुत्ते भी भर्ती किए जाएंगे। लगता है देसी कुत्तों की पूंछ को छोड़कर उनका पूरा व्यक्तित्व बदल जाने वाला है।

अंग्रेजों के राज में अच्छे होटलों तक में कुत्तों और हिंदुस्तानियों का प्रवेश वर्जित होता था। इसी नियम के बूते पर दक्षिण अफ्रीका में एक गोरे मुसाफिर ने मोहनदास करमचंद गांधी को रेल की उच्च श्रेणी के डिब्बे से नीचे उतरने के लिए बाध्य किया था। बैरिस्टर गांधी ने इस भेदभाव के खिलाफ असहयोग की सफलता से उत्साहित होकर भारत वापस आकर भी यही राह अपनाई और महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हो गए।

काश गांधी जी ने देसी कुत्तों के साथ भेदभाव पर भी आपत्ति की होती। उन्हें तो केवल अपने तीन बंदरों और बकरी से प्यार था। उन्हें अपने प्यारे तीन बंदरों को साथ लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें अपने देश में आंख-कान बंद किए लोग हर जगह मिले। हां, गांधी जी की राह अपनाने के बाद भारतीयों ने अपना मुंह जरूर खोल लिया। अब तो यह स्थिति है कि करीब हर आदमी मुंह खोलकर दूसरों को गालियां देते हुए ही मिलता है।

इसके विपरीत अंग्रेजों को कुत्तों से बहुत लगाव था, लेकिन अपनी फौज में उन्होंने सिर्फ विदेशी कुत्तों को प्रवेश दिया और देसी कुत्तों को दूर रखा। अंग्रेज चले गए तो आजादी के 70 वर्षों बाद हाल में ही हमारे देसी कुत्तों का भाग्य खुल गया। सेना के साथ-साथ सीमा सुरक्षा दल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल जैसे अर्धसैन्य बलों में अब तक देसी नस्ल के कुत्तों का प्रवेश निषेध था। अब उनमें देसी कुत्तों की भर्ती का मार्ग खुल गया है। इन सैन्य बलों के दस्तों में अब तक जर्मन शेफर्ड, अल्सेशियन आदि बहादुरी, स्वामिभक्ति, आदेश पूर्ति और सूंघने की शक्ति जैसे गुणों से लबरेज नस्लों के कुत्ते भर्ती किए जाते थे। उन्हें अनाधिकृत प्रवेश रोकने और प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों की प्राण रक्षा, मादक पदार्थों और अपराधियों का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता था।

अभी तक माना जाता था कि देसी कुत्ते केवल दुम हिलाने में होशियार होते हैं, पर अंग्रेज जानते थे कि यह गुण तो अनगिनत भारतीयों के पास भी है। फिर देसी कुत्ते क्यों पाले जाएं? पर स्वतंत्र भारत में ऐसा क्यों किया गया?

कई देसी नस्ल के कुत्ते जैसे मुधोल हाउंड और रामपुरी कुत्ते भी बहादुरी, शक्तिसंपन्नता, आज्ञा पालन और सूंघने की अच्छी शक्ति जैसे गुणों में विदेशी कुत्तों से पीछे नहीं। अब फौजी कुत्तों के नाम भी विदेशी टामी, चार्ली, बडी की जगह देसी चलन के रखे जाएंगे। यह इस आशा से किया जा रहा है कि शायद शेरू, मोती और झबरा नाम वाले देसी कुत्ते विदेशी कुत्तों के आगे मेड इन इंडिया ब्रांड वाली हीनभावना से ग्रस्त नहीं होंगे, पर एक शंका अभी भी बचती है। देसी इंसान जिस तरह उत्तर भारतीय बनाम दक्षिण और मराठी बनाम भैया के झमेलों में फंसते जा रहे हैं, क्या देसी कुत्तों के दस्तों में भी देसी-विदेशी कुत्तों में युद्ध छिड़ सकता है। या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि औसत भारतीय नागरिक की तरह देसी कुत्ते अंग्रेजी में भौंकने वालों के सामने पड़ते ही दुम हिलाना शुरू कर देंगे? वैसे उन्हें इस पर संतोष होगा कि वे सार्वजनिक स्थलों से हटाए जा रहे तो सुरक्षा बलों में सेवाएं देने के काबिल समझे जा रहे।

response@jagran.com

कालचक्र

सत्संग विमुख मानव भौतिकवादी संस्कृति की भूल-भुलैया में अपने यथार्थ मार्ग को ढूंढ पाने में भटक रहा है। एक कपोलकल्पित सांसारिक समुपलब्धि को प्राप्त करने में दिशाविहीन होकर अनवरत दौड़ में लगा हुआ है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई मान, कोई सुख की तलाश में, किंतु इस दौड़ का अंत कहां है? हमारे मनीषियों ने एक अद्भुत रूपक के माध्यम से इस सत्य को प्रकाशित किया है- एक मेंढक कीटादि को आहार बनाने के लिए दौड़ रहा है, उसे खाने के लिए उसके पीछे सर्प दौड़ रहा है, सर्प के पीछे मयूर, मयूर के पीछे सिंह और सिंह के पीछे शिकारी। वस्तुतः इन सबके पीछे काल ही सबको निगल रहा है। यह सिर्फ दृश्य मात्र जीव-जगत् की क्रिया नहीं, अपितु मानव जीवन का गूढ़ प्रतीक है। मेंढक भोग में लिप्त साधारण मनुष्य का प्रतीक है, सर्प उसकी वासना है, मयूर अहंकार है, सिंह क्रोध एवं शक्ति की लालसा है और शिकारी नियति या काल का प्रतीक है। हर जीव किसी का पीछा कर रहा है, कोई किसी से बचना चाहता है, किंतु सब एक ही दिशा में अग्रसर हैं, काल के आलिंगन की ओर। इससे यह स्पष्ट होता है कि संसार का प्रत्येक प्राणी क्षणभंगुरता की परिधि में बंधा है। जीवन का हर क्षण घट रहा है, किंतु मनुष्य इसे अनंत मानकर मोह में डूबा है।

सत्य यह है कि शरीर, संपत्ति और प्रतिष्ठा-सब नश्वर हैं, केवल आत्मा ही शाश्वत है। विचारणीय यह है कि मनुष्य इस आपाधापी में थोड़ा विवेक से अपने भीतर झांके तो उसे यथार्थ का बोध हो जाएगा। आत्मचिंतन ही वह शक्ति है, जो काल के भय को समाप्त कर देती है। जो व्यक्ति मृत्यु की स्मृति रखते हुए भी धर्म, सत्य और आत्मबोध में स्थिर रहता है, वही जीवन को सार्थक बनाता है। जो काल को पहचान लेता है, वही अमरत्व और जो जीवन की क्षणभंगुरता को समझ लेता है, वही अखंड और परम शांति को समुपलब्ध होता है।

आचार्य नारायण दास

तथ्य-कथ्य **केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)**

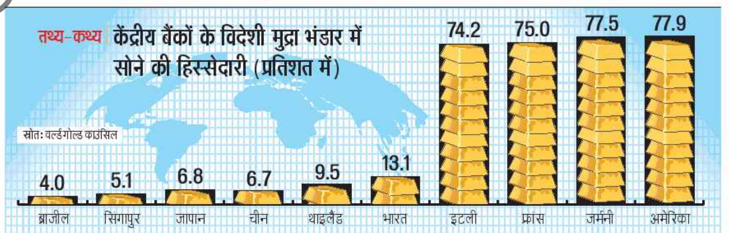

ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन जल भंडार

मुकुल व्यास

> यह जल स्रोत एक क्वेजार में पाया गया है, जो एक सक्रिय आकाशगंगा का अत्यंत चमकीला केंद्रीय भाग है

नासा के खगोलविदों ने ब्रह्मांड में अब तक देखे गए पानी के सबसे विशाल और सबसे दूरस्थ भंडार की खोज की है। यह जल स्रोत 'एपीएम 08279+5255' नामक एक क्वेजार में पाया गया है, जो एक सक्रिय आकाशगंगा का अत्यंत चमकीला केंद्रीय भाग है। इसके केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैकहोल आसपास की गैस और धूल को आकर्षित करता है, जिससे उत्पन्न ऊर्जा क्वेजार को असाधारण बना देती है। यह ब्लैकहोल आकार में अत्यंत विशाल है-हमारे सूर्य से लगभग 20 अरब गुना बड़ा। इसके आस-पास गैस और धूल का घना क्षेत्र है, जो अत्यधिक गर्म होकर अणुओं से भरी परत बनाता है। इन्हीं अणुओं में जलवाष्प भी शामिल है। जलवाष्प की उपस्थिति बताती है कि यह क्वेजार बड़ी मात्रा में विकिरण उत्सर्जित कर रहा है और आसपास की गैस को अपेक्षाकृत गर्म रखता है। विज्ञानियों ने पता लगाया है कि जलवाष्प कई सौ प्रकाश-वर्ष के विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। एक प्रकाश-वर्ष लगभग 94 लाख करोड़ किलोमीटर का होता है, इसलिए इस पैमाने का जल भंडार ब्रह्मांडीय दृष्टि से अद्वितीय है।

यह क्वेजार पृथ्वी से 12 अरब प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूर स्थित है। इसका अर्थ है कि हम इसे जैसा देख रहे हैं, वह आज नहीं, बल्कि दस अरब साल से भी पुरानी स्थिति है- उस समय जब ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और आकाशगंगाएं तथा ब्लैकहोल तेजी से विकसित हो रहे थे। खगोलविदों का अनुमान है कि इस क्वेजार में मौजूद पानी की मात्रा पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना में लगभग 140 लाख करोड़ गुना अधिक है, जो इसे अब तक ज्ञात सबसे बड़ा जल भंडार बनाती है।

खगोलशास्त्री ब्रह्मांड में दूरियों का अनुमान लगाने के लिए रेडशिफ्ट का उपयोग करते हैं। इस क्वेजार का रेडशिफ्ट लगभग 3.9 है, जो इसे प्रारंभिक ब्रह्मांड के अत्यंत पुराने चरण में रखता है। रेडशिफ्ट बताता है कि जैसे-जैसे ब्रह्मांड फैलता है, वस्तुओं से आने वाला प्रकाश भी फैलता है और उसका रंग लाल की ओर खिसकता है। यह सिद्धांत विज्ञानियों को अरबों वर्ष पुरानी घटनाएं समझने में मदद करता है। दूरस्थ होते हुए भी यह क्वेजार दृश्य प्रकाश और सुदूर अवरक्त प्रकाश दोनों में अत्यधिक चमकीला दिखता है। यह संकेत है कि वहां ऐसी भौतिक प्रक्रियाएं सक्रिय हैं जो उत्सर्जित प्रकाश को और अधिक उज्ज्वल बना रही हैं। विज्ञानियों के अनुसार, इस विशाल जल भंडार की खोज महत्वपूर्ण इसलिए भी है, क्योंकि पानी जीवन का मूलभूत तत्व है। इतनी प्राचीन अवस्था में पानी की उपस्थिति यह भी प्रमाणित करती है कि ब्रह्मांड में जीवन के संभावित घटक आरंभिक समय से ही मौजूद थे।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

भरोसा नहीं

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता यही दावा कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि पिछले एक साल से ऐसा दावा इतनी बार किया जा चुका है कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है। भाजपा मुख्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच इस पर कोई खास चर्चा भी नहीं हो रही है। इस संबंध में नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं को कुरेदने पर उनका दर्द छलक जाता है। ऐसे ही एक नेता ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। उसके बाद संक्रांति शुरू हो जाएगी और संक्रांति खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल समेत छह राज्यों के विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। यानी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, जो पहले से ही काफी लंबा हो गया है।

वक्त के साथ बदला रंग

राजनीति में रिश्ते, विचार और रंग भी मौसम की तरह बदलते रहते हैं। कभी हरे रंग की सौगंध खाने वाले तेज प्रताप यादव अब पूरी तरह से पीले रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। पुरानी पारिवारिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही परिवार से भी बेदखल होने के बाद उन्होंने नई पार्टी बनाई और पहचान का रंग भी तय कर लिया। अपनी नई पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' की पहचान के रूप में उन्होंने पीला गमछा अनिवार्य कर दिया है। अब तो उनके मंचों पर हरे की जगह पीले का ही जलवा है। जिस हरे गमछे को उन्होंने वफादारी की निशानी बताया था, अब वही रंग उन्हें बेवफाई का प्रतीक लगता है। नई पार्टी में जो साथी पीला गमछा नहीं रखता है, उसे वे 'जयचंद की पार्टी' वाला बताकर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जयचंद की पार्टी का मतलब उनके पिता लालू प्रसाद की पार्टी, जो अभी उनके भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रही है। यही तेज प्रताप हैं, जो जब राजद में थे तो हरे गमछे के बिना किसी को मंच पर चढ़ने नहीं देते थे। तब हरा उनकी पहचान थी, अब वही रंग उन्हें नागवार गुजरता है। वक्त बदला तो रंग भी बदल गया।

शुक्रिया से पहले सुन तो लो...

संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीश मामले में फैसला कुछ भी सुनाएं, लेकिन फैसले के बाद वकील हमेशा अदालत को धन्यवाद देते हैं। कई बार तो हक में फैसला आने पर वकील कोर्ट को धन्यवाद देते नहीं थकते। हालांकि कुछ उत्साही वकील अदालत के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की खासी जल्दबाजी भी कर देते हैं। पिछले दिनों ऐसा ही एक वाकया दिखा। एक मामले में कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाना शुरू किया और कहा कि मांग स्वीकार की जाती है, तत्काल एक उत्साही युवा वकील ने कोर्ट का धन्यवाद अदा करना शुरू कर दिया। जब कई बार हो गया तो न्यायाधीश ने कहा कि बहुत उत्साहित न हों, फैसले में और भी बहुत कुछ है। वकील साहब तुरंत चुप्पी साध गए।

पत्रकारों की शरण में अधिकारी

इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के पोस्ट की समीक्षा के दौर में कई मंत्रालयों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया। उनके वरिष्ठ अधिकारियों को कहा गया है कि वे वीडियो बनाकर, अच्छी हेडिंग लगाकर या कंटेंट को नया बनाकर विभिन्न तरीकों से मंत्रालय की सूचनाओं को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट करें। एक मंत्रालय से कहा गया कि उनके मंत्रालय से रोजाना 100 पोस्ट करने की गुंजाइश है, लेकिन सिर्फ दस किए जा रहे हैं। अब इस टास्क पर खुद को सक्षम साबित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी पत्रकारों से कंटेंट को इंटरनेट मीडिया पर चर्चित बनाने की कला पूछ रहे हैं। वीडियो बनाने के दौरान किसी सामग्री को किस रूप में पेश किया जाए कि अधिक से अधिक लोग उसे देखें, इस प्रकार की बातें अधिकारी पत्रकारों से पूछते नजर आ रहे हैं।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

जब इच्छाएं सीमित होती हैं तब संतोष जन्म लेता है

नियमों की अनदेखी

यह अच्छा है कि सरकार बिना बीमा वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए इंश्योरेंस इन्फार्मेशन ब्यूरो बनाया जा रहा है, जहां सभी वाहनों का डाटा होगा। इस ब्यूरो के जरिये जिन वाहनों का बीमा नहीं पाया जाएगा, उनके मालिकों को चेतावनी संदेश भेजा जाएगा और उस पर ध्यान न देने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा किया ही जाना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रहे कि बात तब बनेगी, जब बीमा रहित वाहन चलाने वालों के खिलाफ सचमुच कठोर कार्रवाई की जाएगी। चूंकि अभी ऐसा नहीं किया जाता, इसलिए बड़ी संख्या में लोग बीमा खत्म होने के बाद भी उसके बगैर वाहन चलाते रहते हैं। यह स्थिति यही बताती है कि अपने देश में आवश्यक नियम-कानूनों का पालन न करने की प्रवृत्ति कायम है। यह प्रवृत्ति सब चलता है वाले रवैए को ही बयान करती है। यह प्रवृत्ति वाहन मालिकों के साथ-साथ सरकारी तंत्र की ढिलाई का भी नतीजा है। यह ढिलाई किस बड़े पैमाने पर बरती जा रही है, इसका पता इससे चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक आंकड़े के अनुसार देश में 50 प्रतिशत से अधिक वाहन बिना बीमा के चलाए जाते हैं। जब कभी बिना बीमा वाले वाहन दुर्घटना से दो-चार होते हैं, तब वाहन स्वामी के साथ हादसे के शिकार व्यक्ति को भी अतिरिक्त मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अपने देश में मार्ग दुर्घटनाओं और उनमें मरने एवं घायल होने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। बिना बीमा वाहन चलाने वाले दुर्घटना की स्थिति में अपने साथ-साथ दूसरों को संकट में ही नहीं डालते, मुकदमेबाजी का कारण भी बनते हैं। ऐसे लोग इससे बेपरवाह रहते हैं कि उनके वाहन का बीमा न पाए जाने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस बेपरवाही के मूल में है जुर्माने की राशि अधिक न होना और पकड़े जाने पर कुछ ले-देकर या रौब जमाकर छूट जाने का भरोसा होना। नियम-कानूनों की अनदेखी तभी होती है, जब उनके पालन का तंत्र निष्प्रभावी या नाकाम होता है। अपने देश में ऐसा हर क्षेत्र में होता है। इसी कारण सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में पड़ती रहती है और बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही है। आवश्यक केवल यह नहीं कि बिना बीमा वाहन न चलने दिए जाएं, बल्कि यह भी है कि अकुशल चालकों, खटारा वाहनों, खराब सड़कों के साथ-साथ यातायात नियमों की अवेहलना के चलते होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। इसके लिए केवल नियम-कानूनों को कठोर ही नहीं करना होगा, उन पर सही तरह अमल भी सुनिश्चित करना होगा। आम तौर पर ऐसा करने की घोषणा कर दी जाती है और कभी-कभी तो नियम-कानूनों में संशोधन भी कर दिया जाता है, लेकिन उनके पालन के अभाव में नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही रहता है।

मतदान के प्रति जागरूकता

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 121 सीटों के अब तक जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक मतदान मुजफ्फरपुर के मीनापुर में किया गया। यहां 77.54 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि सबसे कम मतदान पटना जिले के कुम्हरार क्षेत्र में हुआ। यहां केवल 40.17 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि यह राजधानी पटना का क्षेत्र है। ये आंकड़े बता रहे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान के प्रति जागरूकता शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक दिखी, जबकि यह माना जाता है कि शहरों में शिक्षा और जागरूकता अधिक है। मतदान के आंकड़े बता रहे कि ग्रामीण क्षेत्र इस मामले में कहीं अधिक सक्रिय और जागरूक रहे हैं, जहां लोकतंत्र में मतदान के महत्व को समझते हुए लोग घरों से निकले और मतदान केंद्रों तक पहुंचे। शहरी क्षेत्रों में कम मतदान होना चिंता की बात है। अभी दूसरे चरण का मतदान होना शेष है। यह 11 नवंबर को होगा। राज्य के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने को आगे आएं, यह जरूरी है। आमजन की अपेक्षा को पूर्ण करने की जवाबदेही होती है, ऐसे में मतदान के प्रति उदासीनता उचित नहीं है। योग्य प्रतिनिधि के चुनाव में मत का प्रयोग करते हुए अपनी राय व्यक्त करना एक मतदाता का अधिकार है और इसका सदुपयोग निश्चित रूप से किया जाना चाहिए।

> आम मतदाताओं के मतों से चुनी गई लोकप्रिय सरकार पर ही विकास का दायित्व होता है। योग्य प्रतिनिधि का चुनाव अवश्य करें।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जमीन पर असर दिखेगा?

आज का सवाल

क्या राष्ट्र गीत वंदे मातरम् के कुछ हिस्से को हटाने का तत्कालीन कांग्रेस नेताओं का फैसला सही था?

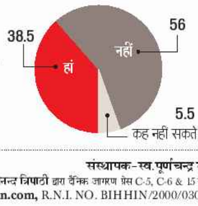

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

वंदे मातरम् पर व्यर्थ का विवाद

संजय गुप्त

जब कभी वंदे मातरम् को मान-सम्मान देने या फिर उसका स्मरण करने की पहल होती है, उसके खिलाफ कुछ बेतुके स्वर उभर ही आते हैं

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने को एक उत्सव के रूप में वर्ष भर मनाने का फैसला कर यही रेखांकित किया कि उनकी सरकार राष्ट्रीयता के प्रति विशेष अनुराग रखती है और वह प्रत्येक अनुकूल अवसर को राष्ट्रबोध जगाने के लिए उपयोग करती है। यह उनकी गहरी दृष्टि और दूरगामी सोच को प्रकट करता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ओर से रचित कालजयी गीत वंदे मातरम् से संबंधित उत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने जिस तरह स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने के साथ एक विशेष वेबसाइट लांच की, उससे यही पता चलता है कि वे इस अवसर को कितना महत्व दे रहे हैं। इस मौके पर दिए गए भाषण में उन्होंने वंदे मातरम् को एक मंत्र, एक संकल्प, एक साधना, अराधना आदि बताते हुए उसे वर्तमान से भी जोड़ा और कहा कि यह विकसित भारत के सपने को पूरा करने की प्रेरणा देने वाला है। निःसंदेह यदि देशवासी भारत को उन्नत बनाने के लिए समर्पण की उसी भावना से लैस हो जाएं, जिसका परिचय उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय वंदे मातरम् के उद्घोष के सहारे दिया था तो विकसित भारत के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। उस समय यह गीत पहले बंगाल और फिर पूरे देश के लिए स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, त्याग, देशभक्ति और देशसेवा के प्रति संकल्प का पर्याय बन गया था। इसने लाखों लोगों को स्वतंत्रता के लिए त्याग और संघर्ष करने को प्रेरित किया।

विश्व इतिहास में ऐसे किसी गीत का उल्लेख कठिनाई से ही मिलता है, जिसने करोड़ों लोगों को आंदोलित करने के साथ उन्हें आत्मबल प्रदान किया हो। ऐसा तब हुआ, जब वंदे मातरम् बांग्ला मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखा गया। 1882 में बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम् का प्रकाशन होते ही वह लोगों के आत्मा में रच-बस गया। इस गीत की खूबी यह रही कि इसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सभ्यतागत गौरव के साथ जोड़ने का काम किया। इसी कारण देश के साथ विदेश में भी वह स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसका प्रभाव इतना अधिक बढ़ा कि वह स्वतंत्रता संघर्ष के उद्घोष वाक्य में बदल गया। इससे घबराकर अंग्रेजी सत्ता ने उसे प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन इससे उसकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ी। इसी के साथ बढ़ा जनमानस की चेतना पर उसका प्रभाव। इस गीत की सराहना रवींद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरबिंदो आदि ने की। इसे कांग्रेस के अधिवेशनों में राष्ट्र गीत के रूप में गाया जाने लगा।

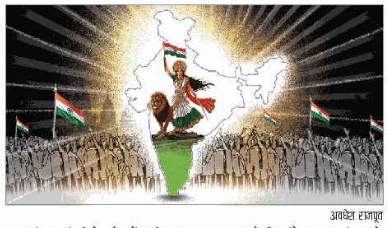

अवधेश राजपूत

स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में कई पत्र-पत्रिकाओं ने वंदे मातरम् नाम से अपना प्रकाशन शुरू किया। इनमें से कुछ तो उर्दू भाषा के थे। इसके अतिरिक्त यह कई क्रांतिकारियों के बीच अभिवादन का विकल्प बन गया। एक तरह से यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रबल स्वर बना। वंदे मातरम् की महत्ता इससे भी समझी जा सकती है कि उसे राष्ट्रीय ध्वज के प्रारंभिक स्वरूप में भी स्थान मिला। जब यह गीत स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था, तब संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उसका बेतुका विरोध भी हुआ। मुस्लिम लीग ने उसे इसलिए सांप्रदायिक बताना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें भारत को एक माता के रूप में चित्रित किया गया था और उसकी आराधना पर बल दिया गया था। चूंकि कांग्रेस मुस्लिम लीग को संतुष्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने वंदे मातरम् को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता तो दी, लेकिन उसके छह में से प्रथम दो छंदों को ही। शेष चार छंदों में ऐसा कुछ नहीं था, जिसे सांप्रदायिक कहा जा सकता। यदि ऐसा होता तो गांधी जी यह न कहते कि वंदे मातरम् बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सबसे शक्तिशाली युद्धघोष और साम्राज्यवाद विरोधी नारा था। नेहरू जी ने भी कहा था कि यह गीत भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। इसके बाद भी कांग्रेस की ओर से उसके दो छंद ही राष्ट्र गीत के रूप में स्वीकृत किए गए। गत दिवस प्रधानमंत्री ने इसका ही उल्लेख करते हुए कहा कि यहीं से विभाजनकारी राजनीति के बीज बोए गए। वंदे मातरम् से जुड़े इस विवाद के बाद भी संविधान सभा ने उसे राष्ट्रीय गीत और जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दी। इससे यह समझा जा सकता है कि इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में कितनी महती भूमिका निभाई।

अतीत में जन गण मन को लेकर भी ऐसी टिप्पणियां करके विवाद उठाए गए हैं कि उसकी रचना ब्रिटिश शासक के गुणगान के लिए की गई थी। अभी हाल में कर्नाटक के एक भाजपा सांसद ने फिर से ऐसा कहा। इस तरह की बातों से बचा जाना चाहिए। राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान को बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए। यह सभी को सुनिश्चित करना चाहिए कि न राष्ट्रीय गीत की अवहेलना हो और न ही राष्ट्र गान की। दुर्भाग्य से ऐसा रह-रहकर होता रहता है। कई बार संसद में कुछ सांसद वंदे मातरम् के गायन में शामिल नहीं होते। यह ठीक नहीं कि वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री की ओर से वर्ष भर चलने वाले आयोजन का शुभारंभ किए जाते ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने वंदे मातरम् को कभी सम्मान नहीं दिया। आखिर जब दोनों दल वंदे मातरम् की महत्ता से सहमत हैं और उसे राष्ट्र की चेतना को जगाने वाला गीत मानते हैं तो आरोप-प्रत्यारोप क्यों?

महाराष्ट्र में सपा नेता अबू आजमी ने वंदे मातरम् को धार्मिक गीत बताते हुए जिस तरह उसे गाने से इन्कार कर दिया, उससे पता चलता है कि कुछ लोग किस तरह राष्ट्रीय महत्व के प्रतीकों के सहारे विभाजनकारी राजनीति करने के आदी हो गए हैं। अबू आजमी ने वंदे मातरम् को नमाज के समतुल्य बताया। यह खेद की बात है कि जब भी कभी वंदे मातरम् को मान-सम्मान देने या फिर उसका स्मरण करने की पहल होती है, उसके खिलाफ कुछ बेतुके स्वर उभर ही आते हैं। महाराष्ट्र के अलावा ऐसे स्वर जम्मू-कश्मीर में भी सुनाई दिए हैं। ऐसे अवांछित-अनावश्यक स्वरों से वंदे मातरम् की महत्ता-लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यह अवश्य हो सकता है कि भाजपा ऐसे स्वरों को अपने पक्ष में भुनाने के लिए सक्रिय हो।

response@jagran.com

शेरू, मोती और झबरा के भी दिन बहुरे

हास्य-व्यंग्य

बारह बरस में घूरे के भी दिन फिर जाते हैं। कुत्तों की पूंछ इसका अपवाद है। वह बारह बरस तक नली में डाल कर रखी जाने पर भी टेढ़ी की टेढ़ी ही बनी रहती है, लेकिन एक नई खबर बताती है कि अब देसी कुत्तों के दिन फिर रहे हैं। खबर यह है कि सशस्त्र बलों के श्वान दस्तों में भारतीय नस्लों के कुत्ते भी भर्ती किए जाएंगे। लगता है देसी कुत्तों की पूंछ को छोड़कर उनका पूरा व्यक्तित्व बदल जाने वाला है।

अंग्रेजों के राज में अच्छे होटलों तक में कुत्तों और हिंदुस्तानियों का प्रवेश वर्जित होता था। इसी नियम के बूते पर दक्षिण अफ्रीका में एक गोरे मुसाफिर ने मोहनदास करमचंद गांधी को रेल की उच्च श्रेणी के डिब्बे से नीचे उतरने के लिए बाध्य किया था। बैरिस्टर गांधी ने इस भेदभाव के खिलाफ असहयोग की सफलता से उत्साहित होकर भारत वापस आकर भी यही राह अपनाई और महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हो गए।

काश गांधी जी ने देसी कुत्तों के साथ भेदभाव पर भी आपत्ति की होती। उन्हें तो केवल अपने तीन बंदरों और बकरी से प्यार था। उन्हें अपने प्यारे तीन बंदरों को साथ लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें अपने देश में आंख-कान बंद किए लोग हर जगह मिले। हां, गांधी जी की राह अपनाने के बाद भारतीयों ने अपना मुंह जरूर खोल लिया। अब तो यह स्थिति है कि करीब हर आदमी मुंह खोलकर दूसरों को गालियां देते हुए ही मिलता है।

अरुणेंद्र नाथ वर्मा

सड़कों से हटाए जा रहे कुत्तों को इससे संतोष करना चाहिए कि वे सुरक्षा बलों में सेवाएं देने के काबिल समझे जा रहे

इसके विपरीत अंग्रेजों को कुत्तों से बहुत लगाव था, लेकिन अपनी फौज में उन्होंने सिर्फ विदेशी कुत्तों को प्रवेश दिया और देसी कुत्तों को दूर रखा। अंग्रेज चले गए तो आजादी के 70 वर्षों बाद हाल में ही हमारे देसी कुत्तों का भाग्य खुल गया। सेना के साथ-साथ सीमा सुरक्षा दल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल जैसे अर्धसैन्य बलों में अब तक देसी नस्ल के कुत्तों का प्रवेश निषेध था। अब उनमें देसी कुत्तों की भर्ती का मार्ग खुल गया है। इन सैन्य बलों के दस्तों में अब तक जर्मन शेफर्ड, अल्सेशियन आदि बहादुरी, स्वामिभक्ति, आदेश पूर्ति और सूंघने की शक्ति जैसे गुणों से लबरेज नस्लों के कुत्ते भर्ती किए जाते थे। उन्हें अनाधिकृत प्रवेश रोकने और प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों की प्राण रक्षा, मादक पदार्थों और अपराधियों का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता था।

अभी तक माना जाता था कि देसी कुत्ते केवल दुम हिलाने में होशियार होते हैं, पर अंग्रेज जानते थे कि यह गुण तो अनगिनत भारतीयों के पास भी है। फिर देसी कुत्ते क्यों पाले जाएं? पर स्वतंत्र भारत में ऐसा क्यों किया गया?

कई देसी नस्ल के कुत्ते जैसे मुधोल हाउंड और रामपुरी कुत्ते भी बहादुरी, शक्तिसंपन्नता, आज्ञा पालन और सूंघने की अच्छी शक्ति जैसे गुणों में विदेशी कुत्तों से पीछे नहीं। अब फौजी कुत्तों के नाम भी विदेशी टामी, चार्ली, बडी की जगह देसी चलन के रखे जाएंगे। यह इस आशा से किया जा रहा है कि शायद शेरू, मोती और झबरा नाम वाले देसी कुत्ते विदेशी कुत्तों के आगे मेड इन इंडिया ब्रांड वाली हीनभावना से ग्रस्त नहीं होंगे, पर एक शंका अभी भी बचती है। देसी इंसान जिस तरह उत्तर भारतीय बनाम दक्षिण और मराठी बनाम भैया के झमेलों में फंसते जा रहे हैं, क्या देसी कुत्तों के दस्तों में भी देसी-विदेशी कुत्तों में युद्ध छिड़ सकता है। या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि औसत भारतीय नागरिक की तरह देसी कुत्ते अंग्रेजी में भौंकने वालों के सामने पड़ते ही दुम हिलाना शुरू कर देंगे? वैसे उन्हें इस पर संतोष होगा कि वे सार्वजनिक स्थलों से हटाए जा रहे तो सुरक्षा बलों में सेवाएं देने के काबिल समझे जा रहे।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

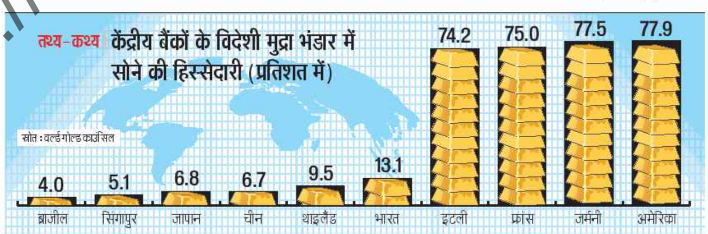

ऊर्जा

कालचक्र

सत्संग विमुख मानव भौतिकवादी संस्कृति की भूल-भुलैया में अपने यथार्थ मार्ग को ढूंढ़ पाने में भटक रहा है। एक कपोलकल्पित सांसारिक समुपलब्धि को प्राप्त करने में दिशाविहीन होकर अनवरत दौड़ में लगा हुआ है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई मान, कोई सुख की तलाश में, किंतु इस दौड़ का अंत कहां है? हमारे मनीषियों ने एक अद्भुत रूपक के माध्यम से इस सत्य को प्रकाशित किया है- एक मेंढक कीटादि को आहार बनाने के लिए दौड़ रहा है, उसे खाने के लिए उसके पीछे सर्प दौड़ रहा है, सर्प के पीछे मयूर, मयूर के पीछे सिंह और सिंह के पीछे शिकारी। वस्तुतः इन सबके पीछे काल ही सबको निगल रहा है। यह सिर्फ दृश्य मात्र जीव-जगत् की क्रिया नहीं, अपितु मानव जीवन का गूढ़ प्रतीक है। मेंढक भोग में लिप्त साधारण मनुष्य का प्रतीक है, सर्प उसकी वासना है, मयूर अहंकार है, सिंह क्रोध एवं शक्ति की लालसा है और शिकारी नियति या काल का प्रतीक है। हर जीव किसी का पीछा कर रहा है, कोई किसी से बचना चाहता है, किंतु सब एक ही दिशा में अग्रसर हैं, काल के आलिंगन की ओर। इससे यह स्पष्ट होता है कि संसार का प्रत्येक प्राणी क्षणभंगुरता की परिधि में बंधा है। जीवन का हर क्षण घट रहा है, किंतु मनुष्य इसे अनंत मानकर मोह में डूबा है।

सत्य यह है कि शरीर, संपत्ति और प्रतिष्ठा- सब नश्वर हैं, केवल आत्मा ही शाश्वत है। विचारणीय यह है कि मनुष्य इस आपा-धापी में थोड़ा विवेक-विचार से अपने भीतर झांके तो उसे यथार्थ का बोध हो जाएगा। आत्मचिंतन ही वह शक्ति है, जो काल के भय को समाप्त कर देती है। जो व्यक्ति मृत्यु की स्मृति रखते हुए भी धर्म, सत्य और आत्मबोध में स्थिर रहता है, वही जीवन को सार्थक बनाता है। जो काल को पहचान लेता है, वही अमरत्व को और जो जीवन की क्षणभंगुरता को समझ लेता है, वही अनंत, अखंड और परम शांति को समुपलब्ध होता है।

आचार्य नारायण दास

भरोसा नहीं

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता यही दावा कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि पिछले एक साल से ऐसा दावा इतनी बार किया जा चुका है कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है। भाजपा मुख्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच इस पर कोई खास चर्चा भी नहीं हो रही है। इस संबंध में नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं को कुरेदने पर उनका दर्द छलक जाता है। ऐसे ही एक नेता ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। उसके बाद संक्रांति शुरू हो जाएगी और संक्रांति खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल समेत छह राज्यों के विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। यानी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, जो पहले से ही काफी लंबा हो गया है।

वक्त के साथ बदला रंग

राजनीति में रिश्ते, विचार और रंग भी मौसम की तरह बदलते रहते हैं। कभी हरे रंग की सौगंध खाने

राजरंग

वाले तेज प्रताप यादव अब पूरी तरह से पीले रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। पुरानी पारिवारिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही परिवार से भी बेदखल होने के बाद उन्होंने नई पार्टी बनाई और पहचान का रंग भी तय कर लिया। अपनी नई पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' की पहचान के रूप में उन्होंने पीला गमछा अनिवार्य कर दिया है। अब तो उनके मंचों पर हरे की जगह पीले का ही जलवा है। जिस हरे गमछे को उन्होंने वफादारी की निशानी बताया था, अब वही रंग उन्हें बेवफाई का प्रतीक लगता है। नई पार्टी में जो साथी पीला गमछा नहीं रखता है, उसे वे 'जयचंद की पार्टी' वाला बताकर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जयचंद की पार्टी का मतलब उनके पिता लालू प्रसाद की पार्टी, जो अभी उनके भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रही है। यही तेज प्रताप हैं, जो जब राजद में थे तो हरे गमछे के बिना किसी को मंच पर चढ़ने नहीं देते थे। तब हरा उनकी पहचान थी, अब वही रंग उन्हें नागवार गुजरता है। वक्त बदला तो रंग भी बदल गया।

शुक्रिया से पहले सुन तो लो...

संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीश मामले में फैसला कुछ भी सुनाएं, लेकिन फैसले के बाद वकील हमेशा अदालत को धन्यवाद देते हैं। कई बार तो हक में फैसला आने पर वकील कोर्ट को धन्यवाद देते नहीं थकते। हालांकि कुछ उत्साही वकील अदालत के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की खासी जल्दबाजी भी कर देते हैं। पिछले दिनों ऐसा ही एक वाकया दिखा। एक मामले में कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाना शुरू किया और कहा कि मांग स्वीकार की जाती है, तत्काल एक उत्साही युवा वकील ने कोर्ट का धन्यवाद अदा करना शुरू कर दिया। जब कई बार हो गया तो न्यायाधीश ने कहा कि बहुत उत्साहित न हों, फैसले में और भी बहुत कुछ है। वकील साहब तुरंत चुप्पी साध गए।

पत्रकारों की शरण में अधिकारी

इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के पोस्ट की समीक्षा के दौर में कई मंत्रालयों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया। उनके वरिष्ठ अधिकारियों को कहा गया है कि वे वीडियो बनाकर, अच्छी हेडिंग लगाकर या कंटेंट को नया बनाकर विभिन्न तरीकों से मंत्रालय की सूचनाओं को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट करें। एक मंत्रालय से कहा गया कि उनके मंत्रालय से रोजाना 100 पोस्ट करने की गुंजाइश है, लेकिन सिर्फ दस किए जा रहे हैं। अब इस टास्क पर खुद को सक्षम साबित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी पत्रकारों से कंटेंट को इंटरनेट मीडिया पर चर्चित बनाने की कला पूछ रहे हैं। वीडियो बनाने के दौरान किसी सामग्री को किस रूप में पेश किया जाए कि अधिक से अधिक लोग उसे देखें, इस प्रकार की बातें अधिकारी पत्रकारों से पूछते नजर आ रहे हैं।

X पोस्ट

अपराधियों से राजनीति को मुक्त रखना है तो उन्हें जनता को ही हराना होगा ...तभी पार्टियां उन्हें उम्मीदवार बनाना बंद करेंगी। दरअसल जनता अपने क्षुद्र लाभ के लिए अपराधी, अनपढ़, अश्लील गायक-डांसर और उन सभी को अपना हीरो बनाती है, जिसका समाज में कोई योगदान नहीं। अनुरंजन झा@anuranjanj

कोई गलतफहमी हो तो उसे जल्दी दूर करें। अगर वक्त रहते मरहम नहीं लगाया तो घाव नासूर बन जाता है। रजत शर्मा@RajatSharmaLive

कर्मचारियों की सैलरी तो साल में एक बार या कभी-कभार बढ़ती है, लेकिन टेलीकाम कंपनियां हर कुछ महीनों में ही सिम रिचार्ज के दाम बढ़ा दे रही हैं, जिससे लोगों के लिए अपने मासिक खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। नलिनी उनागर@NalinisKitchen

हम यह कहते और जानते भी हैं कि हम युवा देश हैं। हमारे पास वर्किंग-एज पापुलेशन की भरमार है, लेकिन क्या उस आबादी के पास सही दिशा और मौके हैं? अवसर की यह खिड़की हमेशा नहीं होगी हमारे पास। मेधा यादव@Medhareports

जनपथ

अच्छी चीजें छोड़कर बुरी चीज की होड़,
शुरू हो रही है पुन: एटम बम की दौड़।
एटम बम की दौड़ ट्रंप अरु पुतिन कराएं,
देखादेखी और देश भी पीछे आएं।
देख मनुज संहार न दादा लोग पसीजें,
भला बढ़ें किस भांति विश्व में अच्छी चीजें!

\- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एगजीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 205

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

जनसत्ता सरोकार
इंडियन एक्सप्रेस समूह
विमर्श
दो
जनसत्ता | 9 नवंबर, 2025

शी को तवज्जो, हाशिये पर मोदी

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

पिछले दिनों शी जिनपिंग से अपनी मुलाकात से पहले और बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बराबरी का दर्जा दिया, जो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी नहीं देंगे। ट्रंप खुलकर बोले, जबकि जिनपिंग हमेशा की तरह रहस्यमयी दिखे। भारत बहुध्रुवीय विश्व के बारे में चाहे जो भी कहे, मगर दुनिया में केवल दो ही महाशक्तियां हैं, रूस उनके ठीक पीछे है। कल तक 'अमेरिकी सुरक्षा के लिए जो अस्तित्वगत खतरा' था, वह अब रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है।

आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग हैं। उसके बाद आते हैं व्लादिमीर पुतिन और बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा हो या बुरा, उनके शब्दों और कार्यों का उन देशों की सीमाओं से परे भी प्रभाव पड़ता है, जहां वे शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को इन नेताओं की कतार में खड़ा करना चाहते हैं– हालांकि, उनकी पार्टी का दावा है कि वे पहले से ही उनमें से एक हैं– लेकिन वास्तविकता अलग है।

आर्थिक सच्चाई

अमेरिका या चीन की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था (आकार के हिसाब से) छोटी है। रूस और इजराइल के मुकाबले *प्रति व्यक्ति* आय के मामले में भी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है। आंकड़े इस प्रकार हैं:

देश	सकल घरेलू उत्पाद का आकार	*प्रति व्यक्ति* आय
	(2025 में अनुमानित सांकेतिक–	*अमेरिकी डालर में)*
अमेरिका	30.51 ट्रिलियन	89,000
चीन	19.23 ट्रिलियन	13,800
रूस	2.54 ट्रिलियन	17,500
इजराइल	0.6 ट्रिलियन	54,000
भारत	4.19 ट्रिलियन	2,900

अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत से सात गुना और चीन की 4.5 गुना बड़ी है। भारत भले ही सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन यहां जीडीपी को दोगुना करने में भी अभी दस वर्ष लगेंगे। इस बीच, कम विकास दर (लेकिन बड़े आधार पर) पर भी अमेरिका और चीन की जीडीपी बड़ी हो जाएगी। ऐसे में भारत और अमेरिका तथा भारत और चीन के बीच जीडीपी का *अंतर* और बढ़ सकता है। रूस और इजराइल की जीडीपी भले ही कम हो, लेकिन वे ज्यादा अमीर हैं और उनकी *प्रति व्यक्ति* आय भारत से क्रमशः छह गुना और अठारह गुना अधिक है। यह गणित दुनिया के हर नेता को पता है, सिवाय भारत के मौजूदा शासकों के!

आश्चर्यजनक जी–2

दुनिया भारत का सम्मान इसलिए करती है, क्योंकि यह सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और साथ ही यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था, इतिहास, प्राचीन संस्कृति, शांति–प्रवर्तक के रूप में भूमिका तथा बाजार का आकार और उसकी संभावनाएं भी इसका कारण हैं– इसलिए नहीं कि भारत एक महाशक्ति है। दुनिया के देशों का व्यापार और क्षेत्रीय शांति में हित है। इसलिए, वे भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध बनाए रखेंगे, भले ही भारत का यह रुख हो कि 'अगर आप हमारे मित्र हैं, तो आपको पाकिस्तान से परहेज करना होगा।'

इसके अलावा, दुनिया तेजी से बदल रही है। वर्ष 2023 में भारत ने जी–20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी का ढिंढोरा पीटा। जी–20 की बैठक और नेताओं का शिखर सम्मेलन एक वार्षिक आयोजन है और मेजबान देश का चुनाव बारी–बारी से होता है। वर्ष 2024 में ब्राजील मेजबान देश था, नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका इस बैठक और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और 2026 में अमेरिका मेजबान होगा। जी–20 की मेजबानी कोई बड़ी बात नहीं है; कोई भी दूसरा देश इसे लेकर इतना *शोर* नहीं मचाता।

जी–8 और जी–7, जी–20 से ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। अब हमारे पास कुछ नया है– जी–2। पिछले दिनों शी जिनपिंग से अपनी मुलाकात से पहले और बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बराबरी का दर्जा दिया, जो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी नहीं देंगे। ट्रंप खुलकर बोले, जबकि जिनपिंग हमेशा की तरह रहस्यमयी दिखे। भारत बहुध्रुवीय विश्व के बारे में चाहे जो भी कहे, मगर दुनिया में केवल दो ही महाशक्तियां हैं, रूस उनके ठीक पीछे है। कल तक 'अमेरिकी सुरक्षा के लिए जो अस्तित्वगत खतरा' था, वह अब रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। इस नए सौहार्द के साथ, 'क्वाड' किनारे हो जाएगा।

जमीनी हकीकत :

– अमेरिका और चीन के बीच दुर्लभ धातुओं तथा सोयाबीन को लेकर एक छोटा व्यापार समझौता हुआ; दोनों देश टिक–टाक का मुद्दा भी संभवतः सुलझा लेंगे। वहीं, अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते पर 2025 में बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

– अमेरिका और चीन के बीच शुल्क संघर्ष चल रहा था (दोनों एक–दूसरे पर जवाबी शुल्क लगा रहे थे), लेकिन बुसान में हुई बैठक के बाद दोनों देशों के नेता प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निर्यात नियंत्रण और बंदरगाह शुल्क जैसे मुद्दों को लेकर एक समझौते पर सहमत हुए हैं, और दोनों देश आपसी सहमति से शुल्क में ढील देंगे। जबकि अमेरिका ने भारत पर लगाए गए शुल्क को खत्म या कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

– चीनी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहेंगे; और रूसी तेल खरीदने वाली भारतीय कंपनियों पर भी प्रतिबंध जस के तस रहेंगे।

– अमेरिका ने चीन के सामान तक तरजीही पहुंच को कम कर दिया है; इसी तरह, वर्ष 2019 में भारत को मिलने वाली सामान्यीकृत तरजीही प्रणाली (जीएसपी) को रद्द करना भी अंतिम प्रतीत होता है।

ठंडे बस्ते में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी बार 14 फरवरी, 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इसके बाद तीन मौके आए, जब मोदी–ट्रंप की मुलाकात हो सकती थी। पहला, कनाडा में जी–7 शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप ने मोदी को वाशिंगटन आने का न्योता दिया, जो स्वीकार नहीं किया गया; मुझे लगता है कि यह सही था। दूसरा, जब मोदी गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर के लिए मिस्र नहीं गए। तीसरा, इस साल अक्तूबर में कुआलालंपुर में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी ठोस कारण इस सम्मेलन को आभासी माध्यम से संबोधित करने का फैसला किया; मुझे लगता है कि यह गलत था। यह आम धारणा बन गई है कि प्रधानमंत्री मोदी अब ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक और यहां तक कि बातचीत से भी बचना चाहते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने अनगिनत बार यह दावा किया है कि उन्होंने 'द्विपक्षीय व्यापार बंद करने' की चेतावनी देकर भारत और पाकिस्तान को युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया, और इसके चौथे दिन युद्ध रोक दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक रूप से या संसद में इस दावे का खंडन नहीं किया है। इसके अलावा, मोदी ने कभी भी शी जिनपिंग के सामने यह नहीं कहा कि चीन के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है और वे अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए हैं।

ट्रंप और जिनपिंग के बीच रिश्तों की गर्मजोशी ने जापान, आस्ट्रेलिया तथा ताइवान के साथ–साथ भारत को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। व्यावहारिक रूप से देखा जाए, तो दक्षिण एशिया में भारत का कोई मित्र नहीं है। पश्चिम एशियाई देश भारत के बिना, आपस में और इजराइल के साथ नए समझौते कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि थोड़ी विनम्रता बरती जाए और नीतिगत रूपरेखा पर फिर से विचार किया जाए।

आरोप और सवाल

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

राहुल के इस बम में से सारी ऊर्जा निकल चुकी है। इसलिए कि कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। चुनावों में धांधली इस स्तर पर कभी नहीं हो सकती कि किसी राज्य का पूरा का पूरा चुनाव फर्जी हो जाए। इतने बुलंद हैं राहुल के हौसले कि अब आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल कर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भी चुनाव चोरी किए हैं।

कोशिश बहुत की है, लेकिन न जाने क्यों मुझे राहुल गांधी की वोट चोरी वाली बातों पर यकीन नहीं होता है। पिछले सप्ताह उन्होंने अपना 'बम' फोड़ा यह कह कर कि हरियाणा का पूरा चुनाव मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की सहायता लेकर कांग्रेस पार्टी से चुराया था पिछले साल। जैसे अक्सर करते हैं जब कोई नया 'बम' उनके हाथ लगता है। उन्होंने एक स्कूल अध्यापक की तरह बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े होकर पत्रकारों को अपने इस नए बम के बारे में बताया। स्क्रीन पर कई तस्वीरें थीं एक ही लड़की की और नेता प्रतिपक्ष ने बिल्कुल स्कूल शिक्षक के अंदाज में पूछा, 'क्या कोई बता सकता है मुझे कि यह लड़की कौन है और कहां की है? हरियाणा की लगती है क्या आपको?' फिर खुद ही उन्होंने इस लड़की का परिचय दिया। ब्राजील की एक माडल है यह, उन्होंने कहा। जैसे कि कोई बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हों, और आगे बताया कि इस लड़की ने कोई बाईस बार वोट किया हरियाणा के विधानसभा चुनावों में कभी स्वीटी के नाम से, कभी पिंकी बन कर, तो कभी सरस्वती।

इस खुलासे के अगले दिन ब्राजील की उस माडल ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया, जिसमें खूब मजे लेते हुए उसने बताया कि यह उसकी ही तस्वीर है, लेकिन कई साल पुरानी। उसने यह भी कहा कि उसको मालूम नहीं, क्यों इस तस्वीर को भारत की चुनावी चर्चा में घसीट लिया गया है। अगले दिन ऐसा हुआ कि कुछ खोजी पत्रकारों ने हरियाणा के उस गांव में जाकर तहकीकात की जहां यह 'फर्जी' मतदान हुआ था। वहां मालूम यह हुआ कि जिनके कार्ड राहुल ने अपनी स्क्रीन पर दिखाए थे, वे वास्तव में असली महिलाओं के थे और इनमें से एक महिला का नाम पिंकी ही था।

राहुल के इस बम में से सारी ऊर्जा निकल चुकी है। इसलिए कि कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। चुनावों में धांधली इस स्तर पर कभी नहीं हो सकती कि किसी राज्य का पूरा का पूरा चुनाव फर्जी हो जाए। इतने बुलंद हैं राहुल जी के हौसले कि अब आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल कर महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के भी चुनाव चोरी किए हैं। ऐसी शक्ति होती प्रधानमंत्री के हाथ में, तो क्या लोकसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल करने की कोशिश न करते? क्या वह चोरी ज्यादा काम न आती?

ऐसा कहने के बाद, लेकिन यह भी कहना जरूरी है कि जब नेता प्रतिपक्ष इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, तो उसका दायित्व है पूरी सफाई देना। पिछली बार जब राहुल ने कर्नाटक वाला बम फोड़ा था, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जवाब देने के बदले आक्रामक होकर कहा कि ठोस सबूत हैं अगर, तो उनके सामने राहुल जी अपने नाम से याचिका क्यों नहीं देते। ऐसे कहने के बदले अगर उन्होंने आश्वासन दिया होता कि नेता प्रतिपक्ष के तमाम आरोपों की पूरी जांच की जाएगी, तो शायद राहुल को बिहार में यात्रा निकाल कर न कहना पड़ता हर आमसभा में 'वोट चोर, गद्दी छोड़'। तालियां बजी थीं उनकी इस बात पर लेकिन वोट चोरी का आरोप चुनावी मुद्दा नहीं बना।

इसलिए जब बिहार में मतदान के ऐन एक दिन पहले राहुल अपना 'हाइड्रोजन बम' फोड़ते हैं, तो थोड़ा–सा उनके नौटंकीबाज होने का शक भी होता है और ऐसा भी लगने लगता है कि राहुल को बिहार के चुनावों में हारने के आसार दिखने लगे हैं। उनके महागठबंधन पर प्रधानमंत्री ने खुद आम सभाओं में आक्रामक अंदाज में कहा है कि वे 'घुसपैठियों' के वोटों से जीतने की उम्मीद रखते हैं और देश की आस्था का भी मखौल उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि छठी मैया का अपमान करते हैं कांग्रेस के आला प्रचारक और आज तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अयोध्या जाकर राम मंदिर में माथा टेकने की तकलीफ नहीं की है। प्रधानमंत्री ने अपनी आम सभाओं में लोगों को सावधान किया है कि महागठबंधन के आने से जंगलराज वापस आएगा।

कांग्रेस पार्टी के नेता जवाब में 'वोट चोरी' की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना है इस चुनाव में। काश कि इन्होंने जोहरान ममदानी की कमाल की जीत से कुछ सीखा होता। ममदानी जब न्यूयार्क का महापौर बनने चुनाव में उतरे थे, तो अमेरिकी राजनीतिक पंडितों ने कहा था कि उनकी हार पक्की है। उनके सामने था एक ऐसा व्यक्ति जो न्यूयार्क के एक पुराने राजनीतिक परिवार का वारिस था। एंड्रयू क्यूमो के पिता मारियो क्योमो, न्यूयार्क के राज्यपाल कई साल रहे थे। इस पद पर उनका बेटा भी रहा था, जिन्हें गंभीर आरोपों के बाद अपने पद से हटना पड़ा था।

ममदानी ने पिछले सप्ताह चुनाव जीत कर साबित किया कि जो राजनेता मतदाताओं की दिल की बातें करते हैं उनको जनता जरूर वोट देती है। ममदानी ने महंगाई की बात कीं और याद दिलाया कि न्यूयार्क में किराए इतने ज्यादा हैं कि लोग शहर के बाहर रह कर रोज घंटों सफर करने पर मजबूर हैं। न्यूयार्क के आम नागरिकों पर ध्यान देने की वजह से ममदानी जीते।

बिहार में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। रोजगार की इतनी कमी है बिहार में कि इस राज्य के नौजवान बाकी देश में नौकरी ढूंढ़ने पर मजबूर हैं। पलायन की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं सबसे ज्यादा और इसके उपाय भी रख रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन राजनीति में इतने नए हैं कि सर्वेक्षण बताते हैं कि उनके लिए जीत तकरीबन असंभव है। अफसोस कि ऐसा है। अफसोस कि बिहार के मतदाताओं के सामने कोई नया राजनेता जीतते नहीं दिख रहा है। अफसोस कि उनके सामने वही पुराने विकल्प हैं जो पिछले दो दशकों से रहे हैं।

अमूर्त से मूर्त का सफर

दस्तावेज

विभूति नारायण राय

कोई भी संविधान आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए दुनिया के हर संविधान के अंदर ही उसके संशोधन के प्रावधान भी निहित होते हैं। भारतीय संविधान ने भी संशोधन की संस्थाबद्ध व्यवस्था कर रखी थी। पचहत्तर वर्षों के प्रयोग के बाद भिन्न विचारधाराओं द्वारा स्वीकृति ही हमारे संविधान की सबसे बड़ी सफलता है।

भारतीय दर्शन के तमाम रहस्यवादी भाष्यों की तरह ही संविधान के साथ भी कई ऐसे आख्यान जुड़े हुए हैं, जिनका पुनर्पाठ बहुत ही दिलचस्प होगा। आज वे तमाम लोग इसकी कसमें खा रहे हैं, जो वर्ष 1949 में न सिर्फ इसके उद्देश्यों और कामयाबी को लेकर सशंकित थे, बल्कि जिन्होंने प्राणप्रण से इसे लागू करने का विरोध भी किया था। बहरहाल, बाबा साहब आंबेडकर के अनुयायियों, खासतौर से अनुसूचित जातियों से जुड़ा विशाल समुदाय यह मानता है कि संविधान सभा द्वारा पारित विधान के मुख्य निर्माता डाक्टर आंबेडकर थे। यह एक सामान्य जानकारी है कि वे संविधान की मसविदा समिति के अध्यक्ष थे और इसमें उनके अतिरिक्त अन्य सदस्य भी थे।

जब संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो तत्कालीन कांग्रेस के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल मसविदा समिति के अध्यक्ष पद के लिए एक जर्मन संविधान विशेषज्ञ का नाम लेकर महात्मा गांधी के पास वर्धा गए थे। आपसी बातचीत के दौरान महात्मा गांधी ने उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए डाक्टर आंबेडकर का नाम सुझाया और लंबे विमर्श के बाद यह नाम अंतिम रूप से तय हुआ। बाद में एक भाषण में आंबेडकर ने स्वीकार किया कि जब मसविदा समिति की अध्यक्षता का प्रस्ताव उनके सामने आया, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यह अलग बात है कि समिति के कई सदस्य अपने स्वास्थ्य या राजधानी में उपस्थित न होने की वजह से संविधान सभा की कार्यवाहियों में कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाए। अपनी मेधा एवं अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होने पर आंबेडकर ही सदन की सारी कार्यवाहियों में छाए रहे और शायद इसी वजह से यह धारणा बनी कि संविधान उन्होंने बनाया है। तब कांग्रेस के बहुमत वाली संविधान सभा पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में थी और वही हर प्रावधान पर लंबी बहसों के बाद अंतिम निर्णय लेती थी।

यह उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 को देश में लागू संविधान खुद आंबेडकर की भी पहली पसंद नहीं था। उन्होंने 'यूनाइटेड स्टेट्स आफ इंडिया' के संविधान के नाम से एक मसविदा तैयार किया था और उसे अपने कुछ मित्रों के बीच वितरित भी किया था। इसमें बीमा और बड़े उद्योगों का नियंत्रण राज्य के अंतर्गत रखने की बात की गई थी और हिंदू महिलाओं के उन सब अधिकारों का जिक्र था, जिसे वे चाहते हुए भी हिंदू कोड बिल में शामिल नहीं करा सके थे। कांग्रेस और नेहरू से उनकी दूरी के पीछे यह भी एक बड़ा कारण था।

भारतीय संविधान सभा जब देश के लिए एक नया और सही अर्थों में पहला संविधान बनाने बैठी, तो उसके सामने एक अनूठी चुनौती थी। इस चुनौती की तरफ खुद डाक्टर आंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष मसविदा समिति के अध्यक्ष की हैसियत से अपनी चिंता का इजहार किया था। जिसमें उनकी बात उस विसंगति की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रही थी, जिसमें राजनीतिक समानता की बात करने वाले देश में अभी सामाजिक समानता एक दूर का सपना बना हुआ था। जिस समाज के लिए यह संविधान बनाया जा रहा था, वह वर्ण व्यवस्था से संचालित होने वाला समूह था, जिसमें स्त्रियों समेत समाज के बहुसंख्यक वर्गों को एक सामान्य मनुष्य की तरह से जीने का भी अधिकार नहीं था। खुद आंबेडकर अपने पूरे प्रयास के बावजूद हिंदू महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिलाने वाले हिंदू कोड बिल के कई अंश पारित नहीं करा सके। लोकतंत्र का मुख्य आधार बराबरी होता है और आंबेडकर की यह चिंता जायज लगती है कि गैर–बराबरी को पवित्र धार्मिक मूल्य की तरह स्वीकृत करने वाले समाज में राजनीतिक लोकतंत्र तो आ गया, पर यह सामाजिक लोकतंत्र को किस तरह ग्रहण करेगा।

अगर हम संविधान सभा की बहसों को ध्यान से पढ़ें, तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा कि इसके निर्माण के पीछे मुख्य प्रेरणा वे मूल्य थे, जो आजादी की लड़ाई के दौरान विकसित हुए थे। यह एक चकित करने वाला तथ्य है कि तमाम धर्मों और जातियों में विभाजित भारतीय समाज ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के दौरान उन मूल्यों को विकसित किया, जो उसे एक आधुनिक और समावेशी समाज बना सकते थे। आजादी की लड़ाई मे 1857 के पहले संगठित सशस्त्र विद्रोह और 1920, 30 और 42 के बड़े आंदोलन इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के सम्मिलित प्रयासों ने औपनिवेशिक शासन के माथे पर चिंता की बड़ी लकीरें पैदा कर दी थीं। इसमें कोई शक नहीं कि मध्य युग में धार्मिक कट्टरता की जकड़बंदी एक मजबूत उपस्थिति की तरह समाज में थी, पर यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन तथा अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजी माध्यम से आधुनिक विषयों की शिक्षा ने धर्मनिरपेक्षता की एक नई समझ विकसित कर राज्य के कामकाज में धर्म के हस्तक्षेप से पूरी तरह से मुक्ति जैसी नई अवधारणाओं को भी मजबूत बनाया।

कोई भी संविधान आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए नहीं बनाया जा सकता। वजह स्पष्ट है कि उसे बनाने वाले की मेधा और जरूरतों के अलावा उनके समक्ष पेश चुनौतियां भी समय सापेक्ष होती हैं। इसीलिए दुनिया के हर संविधान के अंदर ही उसके संशोधन के प्रावधान भी निहित होते हैं। भारतीय संविधान ने भी संशोधन की संस्थाबद्ध व्यवस्था कर रखी थी। पचहत्तर वर्षों के प्रयोग के बाद भिन्न विचारधाराओं द्वारा स्वीकृति ही हमारे संविधान की सबसे बड़ी सफलता है। अगर हम ध्यान से देखें, तो सदन के नेता जवाहरलाल नेहरू और मसविदा समिति के अध्यक्ष भीम राव आंबेडकर की अगुआई में संविधान सभा ने भारतीय परंपरा को मैग्नाकार्टा से लेकर फ्रांसीसी क्रांति तक के वैश्विक लोकतांत्रिक आंदोलनों से जोड़कर एक अद्भुत और जीवंत दस्तावेज रचा, जिसकी प्रासंगिकता निरंतर बनी हुई है। उस पर काल्पनिक या वास्तविक संकट आते ही देश के असंख्य पीड़ित जन उसकी सुरक्षा के लिए तन कर खड़े हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज के लिए समानता जैसी अमूर्त अवधारणा को मूर्त स्वरूप में ढालने का एक अद्भुत प्रयास है यह संविधान।

मिलेगा तो देखेंगे

बाखबर

सुधीश पचौरी

मतदान के बाद की चर्चा रेकार्ड मतदान पर अटक गई और सवाल उछलने लगे कि ये बढ़ी हुई वोटिंग किसे जिताने वाली है? क्या यह नीतीश के खिलाफ 'सत्ता विरोधी रुझान' का परिणाम है या कि यह 'सत्ता समर्थन' का परिणाम है?

बिहार में मतदान का दिन। सात बजने वाले हैं। चैनल सुबह से मतदान केंद्रों पर कतारें लगती दिखा रहे हैं। सात बजते ही मत पड़ने शुरू हो जाते हैं। उधर दिल्ली में 'वोट चोरी कथा' जारी है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के चुनाव में इतने वोट हमें मिले... इतने से हम हारे... अगर इतने वोट चोरी न किए जाते, तो हमारी सरकार बनती। अचानक एक महिला की तस्वीर दिखाई जाने लगती है कि इस एक महिला ने हरियाणा के दस मतदान केंद्रों में बाईस बार वोट डाले। जानते हैं ये कौन है? ये ब्राजील की एक माडल है। हरियाणा के चुनाव में इनका क्या काम? लेकिन इसने वोट डाला। इस तरह वोटों की चोरी की गई। सरकार की चोरी की गई। हरियाणा के एक नेता ने पहले ही कहा था कि सारी व्यवस्था है... हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं... 'एक्जिट पोल' में हम जीत रहे थे... हमें ही जीतना था... ये कैसे जीत गए? वोट चोरी करके जीत गए! यही वोट चोरी माडल बिहार में अपनाया जाना है। 'वोट चोरी बम' फटता है और चैनलों में चर्चा का विषय बन जाता है। वोट पड़ते रहते हैं। संवाददाता नामी सीटों के लिए मतदाताओं की लगती लंबी कतारों को दिखाते रहते हैं। वे महिलाओं की लंबी कतारों की ओर इशारा करते हैं और महिलाएं भी गजब की हैं। पूछने पर सकुचाती नहीं, सीधे बोल देती हैं। हर औरत की आवाज मे एक नई खनक है। बहुतों के लिए जो 'मुफ्त की सौगात' हैं, 'रेवड़ी' हैं, 'रिश्वतखोरी' हैं, 'वोट खरीद' है, वही इन औरतों के लिए 'मदद' है। एक एंकर बिहार में 'खाजा' के लिए प्रसिद्ध शहर में 'खाजा' के एक दुकानदार से सबसे प्रसिद्ध 'खाजा' दुकान के बारे में पूछ लेता है कि पिछले वर्षों यहां कुछ हुआ कि नहीं, तो एक कहता है कि बहुत कुछ हुआ है, तो दूसरा कहने लगता है कि कुछ नहीं हुआ है... सिर्फ 'हिंदू मुसलमान' हुआ है! इसी बहसा–बहसी में 'खाजा दुकानों' की जाति भी खुलने लगती है और मालूम होता है कि खाजा की दुकानों में खाजा की खरीदारी भी जाति के हिसाब से चलती है। अपनी–अपनी जाति की दुकान से ही लोग 'खाजा' खरीदते हैं। दुकानदारों की ऐसी दो टूक बहसा–बहसी के बावजूद लोग आपस में हंसते दिखते हैं।

दूसरी ओर, जब फौज को भी जाति के नजरिए से परिभाषित किया जाता है तो एक नया मोर्चा खुल जाता है। एक चैनल पर एंकर इस पर 'अफसोस' जताते हुए एक पुराने फौजी अफसर से इस पर टिप्पणी करने का आग्रह करता है, तो वे अपने गुस्से को किंचित दबाते हुए बोलते हैं कि भगवान के लिए फौज को तो जातिवाद से बख्श दीजिए। फौजी की कोई जाति नहीं होती। इसीलिए हमारी फौज देश को हर तरह के संकट से बचाती आई है। अगर वहां भी 'जाति जाति' करेंगे तो फिर बचेगा क्या?

चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के एक शहर की सुबह एक बाहुबली द्वारा दूसरे बाहुबली को 'निपटा' दिया गया, तो हत्या के आरोप में गिरफ्तार बाहुबली को हीरो मानते हुए एक नेता ने नए लोगों को भी 'बाहुबली' बनने की सलाह देकर अपनी आफत बुलाई। चुनाव आयोग ने तुरंत जबाव–तलब किया। कुछ चैनलों में इसे लेकर 'तू–तू मैं–मैं' भी होती दिखी। ऐसे 'बाहुबलियों' के लिए एक चैनल ने कहा 'फुटानीबाज'। इसी तरह एक चैनल ने बिहार के शहर–दर–शहर खाक छानने के बाद वहां स्थानीय स्तर पर प्रचलित शब्द दिया 'गर्दा उड़ाना'। इसी बीच चुनावी खबर की भाषा में एक और शब्द जुड़ा– 'कट्टा'।

मतदान के बाद की चर्चा रेकार्ड मतदान पर अटक गई और सवाल उछलने लगे कि ये बढ़ी हुई वोटिंग किसे जिताने वाली है? क्या यह नीतीश के खिलाफ 'सत्ता विरोधी रुझान' का परिणाम है या कि यह 'सत्ता समर्थन' का परिणाम है? एक चैनल ने खबर निकाली कि पहले चरण में बिहार में भारी मतदान हुआ है जो अब तक के चुनावों के मतदान के फीसद के मामले में रेकार्ड तोड़ है। चैनलों में इतना अधिक मतदान के कारणों पर बहसें जारी रहीं, लेकिन इसी बीच एक विपक्षी मुख्यमंत्री ने बयान देकर बहसों को फिर दूसरे चरण के मतदान के अभियान की ओर यह कहकर मोड़ दिया कि कांग्रेस मुसलमान है और मुसलमान कांग्रेस है। जाहिर है कि बिहार चुनाव में अब तक इतना खुलकर हिंदू–मुसलिम नहीं हुआ था, जितना इस बयान के बाद हुआ। एक एंकर ने कहा कि यह चुनाव का ध्रुवीकरण करना है... यह तो कांग्रेस के भविष्य के लिए भी खतरनाक है..!

सत्ता प्रवक्ता कहते रहे कि हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन एक 'विश्लेषक' ने सावधान किया कि बढ़ा हुआ मतदान किसी ओर भी जा सकता है। परिणामों से पहले निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी ही कही जा सकती है। मौका मिलेगा तो देखेंगे।

साहित्य

■ मंगला रामचंद्रन

उत्तरजीविता

आखिर जिस बात से गीता डर रही थी वही हो गया। वैसे तो वो कभी अपने पति निर्मल को समाज सेवा करने से रोकती नहीं थी। वरन् वो भी साथ ही देती और उन्हें प्रोत्साहित ही किया करती थी। पर जब हालात ही इतने बदतर हो गये कि इंसान का दूसरे परिवार के इंसान से मिलने पर प्रतिबंध लग गया। यहाँ तक कि एक निश्चित दूरी भी बना कर रखनी पड़ रही थी तब तो नियमों का सख्त पालन, बेमन से ही सही, करना तो पड़ेगा। संक्रमण का हमला हो जाये उसके बाद डाक्टरों को भी, एक हद तक इलाज के बाद हाथ खड़े करने पड़ रहे हों तो उत्तम तो यही होगा कि संक्रमण से बचे रहें और इसलिए घर में ही सुरक्षित रहें। यही बात गीता निर्मल को बार-बार याद दिलाती रहती है।

'आप किसी की भी मदद फोन पर बातें करते हुए अथवा ऑनलाइन पैसे भेज कर करिये मैं कुछ नहीं कहूँगी। पर पचहत्तर वर्ष की उम्र में 'इन्फेक्शन' को मौका मत दीजिए कि आपको घेर ले वैसे भी आपको शुगर और बी.पी. है तो बहुत जल्दी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं।'

'मुझे कुछ नहीं होगा, भले ही मुझे डायबिटीज वगैरह है पर मैं ना कभी गंभीर बीमार पड़ा या अस्पताल में भर्ती हुआ । कभी जुकाम-खांसी तक तो नहीं हुआ, मेरे परिचित क्या कहते हैं पता है?'

गीता ने सिर्फ भौंह उठा कर मानो पूछा - 'क्या?'

'सब कहते हैं कि मुझे डायबिटीज या कोई भी बीमारी हो ही नहीं सकती, वरना इस उम्र में इतनी भाग-दौड़ करना और प्रसन्न रहना संभव ही नहीं है। तुम यूं ही परेशान होकर अपनी तबीयत खराब कर लोगी।

गीता जानती है कि बहस करने का कोई अर्थ है ही नहीं। निर्मल के अत्यंत प्रिय मित्र के बेटे को इस महामारी ने चपेट में ले लिया। साधारण दिन होते तो गीता भी उनके साथ अवश्य जाती। उस मित्र और उनकी पत्नी पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। जवान जहीन बेटा जिस पर उसके माता-पिता को अगाध स्नेह, गर्व था और भविष्य की आशाएं टिकी हुई थीं। गीता उनके गहन दुख की कल्पना करके ही सिहर जाती है। जिसका इकलौता बेटा कोरोना की भेंट चढ़ गया हो उसको दिलासा देना एक तरह से नामुमकिन कार्य है। पर उस दम्पति को अंत्येष्टि के समय मदद करने के लिए कम से कम कुछ लोगों की तो आवश्यकता होगी। जाते-जाते निर्मल जिस तरह द्रवित स्वरों में बोल गये - 'इस संकट की घड़ी में इस दम्पति का साथ न दूँ तो शायद स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाऊँगा। हो सकता है कल हमारे साथ ऐसा हो जाये।'

मानो उस समय निर्मल की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान रही हो और परमेश्वर देवी के कथन को कैसे झुठलाते?

देर शाम को निस्तेज और बुझे चेहरे के साथ निर्मल ने घर में प्रवेश किया और सीधे बाथरूम में नहाने चले गये। साधारणतया उन्हें नहाने में दस मिनिट से अधिक नहीं लगते थे पर उस दिन आधे घंटे तक वो निकले ही नहीं। गीता कुछ संशय और डर से बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज़ देने लगी। 'बस आ गया', - कहते हुए बाहर निकले। उनके उस निस्तेज, भावनाहीन चेहरे को देखकर गीता ने ये कब सोचा होगा कि एक तरह से वो उस चेहरे को सांसे लेती आखिरी बार देख रही होगी। इस तरह की उनकी हालत पहले भी एक बार भुगत या देख चुकी थी। आज से बीस वर्षों पूर्व, जब उन दोनों की आंखों का तारा, राजदुलारा अविनाश स्कूल में खेलते हुए चोटिल हो गया था। निर्मल अपने दफ्तर से सीधे स्कूल पहुँच गये थे और गीता घर से। तब भी निर्मल अधिक घबराये हुए थे और गीता ने ही उन्हें ढाढस दिलाते हुए कहा था - 'बच्चों को खेलते में चोट तो लग ही जाती है, दो चार दिन में सब ठीक हो जायेगा।'

उस एक महीने में दोनों पति-पत्नी आशा-निराशा के मिश्रण से बने भाव-समुद्र में डूबे एक-दूसरे को सहारा और तसल्ली देते रहे। अविनाश को सिर के पिछले भाग पर चोट लगी थी और खून का थक्का अंदर ही जम गया था। अंदरूनी चोट ज़हर बुझे शब्दों की तरह कितना घातक प्रहार करती है, इसका ज्वलंत उदाहरण बन गया था अविनाश। न जाने कौन-सी नस दब गई थी और डॉक्टरों की अथक कोशिशों के बावजूद अविनाश मात्र शारीरिक रूप से बच गया। पंद्रह वर्ष की उम्र तक पढ़ाई-खेल-कूद और अन्य सभी क्रियाकलापों में सबसे आगे रहने वाला अविनाश मात्र कठपुतली की तरह किसी के डोरी खींचने की राह देखने लगा। निर्मल गीता को मात्र एक संतान प्राप्ति का ही योग था वो भी जब निर्मल सैंतीस वर्ष के थे। कितने प्रसन्न थे, खुशी में फूले नहीं समा रहे थे।

'गीता, हमारे बालक ने हम दोनों को एकदम जवां ही कर दिया, मानो एक नई जान शरीर में आ गई। इतनी स्फूर्ति, इतनी एनर्जी आ गई कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ।' - उस समय तो निर्मल बच्चों या किशोरों की तरह किलक रहे थे। गीता उनकी हरकतें देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। बेटे का नाम भी निर्मल ने ही रखा 'अविनाश', और सदैव बेटे को पूरे नाम से पुकारते थे। गीता से भी कह दिया था कि लाड़-प्यार में उसके सुंदर से नाम को छोटा कर या बिगाड़ कर नहीं पुकारे। दफ्तर में इतनी मेहनत करते कि प्रिय होनहार बेटे को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दे सकें। पिता-पुत्र मिलकर जितनी मस्ती, जितना मजाक करते थे, उतना ही अविनाश की पढ़ाई पर भी ध्यान देते थे। गीता प्रतिदिन एक बार तो कम से कम मन में कहती - 'प्रभु हमारी खुशी इसी तरह बनी रहे, पिता-पुत्र का स्नेह यूं ही बना रहे।'

उस हादसे के बाद निर्मल-गीता और अविनाश के लिए जो वक्त रूक गया था उसी ने निर्मल की उम्र मानों बीस वर्ष अधिक कर दी। उनकी वो स्फूर्ति और जिन्दादिली मानों कहीं गिरवी में रख दी थी। बेटे को उन्होंने कभी न हारने के लिए हेनरी फोर्ड का कथन एक तरह से घुट्टी में पिला दिया था - 'जब सबकुछ आपके खिलाफ हो जाये तो याद रखिए कि हवाई जहाज भी हवा के विरुद्ध उड़ान भरता है, हवा के साथ नहीं।'

किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन पढ़ना, उससे प्रभावित होना और उदाहरण के रूप में बांटना अलग बात है। स्वयं को हताशा और निराशा के गर्त से निकालना इतना सरल नहीं होता। गीता किसी आशावादी की तरह, चमत्कार की हल्की रोशनी के इंतजार में बेटे की सखी, सहायक, रहनुमा बनी रही। निर्मल बेटे के पास जाकर उसे सहलाते, उसके मुस्कुराते, अबोध बालक की तरह निहारते चेहरे को देख अपने से चिपटा कर रो पड़ते।

'पापा, कहीं लग गई क्या, दुख रहा है क्या? आप आराम करो।' - अविनाश के शब्द सुनकर तो वो स्वयं को संभाल ही नहीं पाते। उसी समय से उनका समाजसेवा का दायरा बढ़ते गया, इतना बढ़ गया कि वे खुद नहीं जानते कि उन्होंने कितने दुखते दिलों पर मल्हम लेपने का कार्य किया है। कितनी ही बार किसी की मदद कर के उसके दुख से द्रवित होते हुए गीता ने उन्हें देखा और महसूस किया है। पर आज जिस तरह उनका बेरंग, फक्क और जीवनहीन या स्पंदनहीन चेहरा देखा उससे गीता कांप गई मानों कुछ अनहोनी होने को है। रात को खाना खाने से भी मना कर दिया। गीता ने ज़ोर देकर गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पिला दिया कि थकान मिट जाये। थकान तो क्या मिटी होगी; रात दो बजे के बाद शरीर ऐसा तप रहा था कि मानों फौलाद पिघलाने की भट्टी हो। कोविद 19 के संक्रमण का हमला हो ही गया था।

तपते बुखार में निर्मल का प्रलाप रुक-रुक कर जारी था। 'अविनाश, बेटा अविनाश, पापा आपको कितना प्यार करते हैं, पता है!'

बीच में कुछ बेसिर पैर की बेतुकी बातें। आखिर उन्हें एम्बुलेन्स में ले गये और कोई चारा भी नहीं था और कोविद वार्ड में किसी को आने भी नहीं दिया जाता। गीता और अविनाश को घर में ही 'क्वारेन्टाईन' कर दिया गया, दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली पर बहुत अधिक तकलीफ नहीं रही। गीता को सप्ताह भर बुखार और गले में तकलीफ रही और आश्चर्यजनक रूप से अविनाश ने ही उसे संभाला। निर्मल गीता से कहा करते थे कि 'अपना बेटा अपनी उम्र के बच्चों से कहीं अधिक समझदार है इसलिए देखना बुढ़ापे में हमें आराम ही मिलेगा।'

> अब जब दोनों मां-बेटे कोरोना पाज़िटिव होकर अपने घर में कैद कर दिए गए हों तो बेटे ने जिस स्नेह और ममता से मां को संभाला वो सहजता से भुलाया नहीं जा सकता। भले ही 35 वर्षीय बेटा बाकी लोगों की संतानों की तरह कमाऊ नहीं है, पर इंसानियत और संवेदना की भावना की तो उसमें कमी नहीं है। गीता का उसके साथ जो 'इन्टरएक्शन' होता था, जो परस्पर क्रिया होती थी उसी के फलस्वरूप बेटे का ऐसा आचरण उसे देखने को मिल रहा है।

पिछले बीस वर्षों से उनके इस कथन का कोई मूल्य ही नहीं रह गया था। दोनों को यही चिंता सताती थी कि उनके बाद बेटे को कौन संभालेगा! अब जब निर्मल को घर से दूर अस्पताल में रख कर इलाज होने लगा तो गीता मिश्रित विचारों में डूबी ना जाने कैसे-कैसे ऊटपटांग ख्यालों में आवागमन कर रही थी। कहीं निर्मल को कुछ हो गया तो? ये विचार उसके लिए सबसे भयंकर होते हुए भी सबसे प्रमुख हो गया। निर्मल-गीता जो कि ना जाने किस जन्म के पाप का प्रायश्चित कर रहे थे, उनके लिए इससे बुरी स्थिति क्या होगी? 'पैंतीस वर्षीय अबोध पुत्र', - गीता स्वयं को कोसते हुए कह उठती है।

ऐसी विकट परिस्थिति में इंसान भले-बुरे का ज्ञान ही नहीं गवां देता, बहुत कुछ गलत करने को भी तैयार हो जाता है। 'निर्मल को कुछ हो गया तो' इस विचार ने गीता के मनोमस्तिष्क को मथ के रख दिया। स्वयं को दोष भी देते जाती कि पति के लिए उसका यूं सोचना कितना गलत है।

बार-बार विचार को परे करती पर तूफान इतना जबरदस्त था कि मस्तूल में बंधे पाल की तरह फिर विचार लहरा कर आ जाता। गीता को लगता है कि पूरा माहौल जिस तरह संशय और सम्भ्रम की स्थिति में है, उसमें इंसान तो क्या ईश्वर भी 'कनफ्यूज़' लग रहा है। आखिर उसका एकमात्र सहारा निर्मल ही तो है यदि उसे सुरक्षित रखने की एवज में बेटे की कुर्बानी का विचार आया तो, ऐसा बेटा जिसके भविष्य की चिंता उन दोनों को खाए जा रही थी।

निर्मल की हालात में जब सुधार के लक्षण का पता चल रहा था और गीता का मन भी शांत हो रहा था तभी अचानक उसके आखिरी सांस लेने की खबर ने गीता को सुन्न कर दिया। क्या करे, कैसे करे ये सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। इस सर्वथा नई परिस्थिति से सभी को स्वयं ही के बूते पर निबटना था। स्वचालित मशीन की तरह उसने स्वयं पीपी किट पहन, मास्क पहना और अविनाश को भी पहनाने में मदद करने को सोच रही थी। पर देखा कि वो तो गमगीन मुखमुद्रा में पहले ही चाक-चौबंद खड़ा है। शमशान भूमि में ढ़ेरों चिताएं जल रही थीं, ढेरों स्पंदनहीन शरीर अपनी बारी की प्रतीक्षा में रखे हुए थे। जो शरीर भाग्यशाली थे उनका कोई अपना उनके बारी की प्रतीक्षा में उनके साथ थे। उस हिसाब से निर्मल भाग्यशाली रहे। उनके क्रियाकर्म को निपटाने में गीता जितनी कठिनाई की कल्पना कर रही थी, बेटे ने पूरी शिद्दत से उसे जैसा कहा गया, करता गया। साथ ही मां को तसल्ली और धैर्य भी बंधाता रहा जिसे अनुभव करते हुए वो स्वयं को धिक्कार रही थी कि उसके मन में पल भर को भी बेटे के प्रति ऐसी विपरीत कामना कैसे उठी!

वहां से लौटने से पहले उन्होंने देखा एक जवान स्त्री अपनी चार वर्षीया बालिका के साथ बदहवास सी बैठी थी और उसके सामने उसके पति का शव रखा हुआ था। पता चला कि वो इतनी गरीब और अबला है कि कफन खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। गीता का मन उस औरत की हालत से द्रवित हो रहा था, तभी अविनाश ने उससे कहा - 'मम्मी, आप उसकी कुछ मदद कर सकती हैं क्या? उसके साथ कोई भी नहीं है, छोटी सी बच्ची के साथ वो कैसे सब करेगी?'

अविनाश को अबोध मानने वाली गीता की आंखें भर आईं। अपने बेटे के मन के उजले पक्ष को साफ-साफ देख पा रही थी।

अब जब दोनों मां-बेटे कोरोना पाज़िटिव होकर अपने घर में कैद कर दिए गए हों तो बेटे ने जिस स्नेह और ममता से मां को संभाला वो सहजता से भुलाया नहीं जा सकता। भले ही 35 वर्षीय बेटा बाकी लोगों की संतानों की तरह कमाऊ नहीं है, पर इंसानियत और संवेदना की भावना की तो उसमें कमी नहीं है। गीता का उसके साथ जो 'इन्टरएक्शन' होता था, जो परस्पर क्रिया होती थी उसी के फलस्वरूप बेटे का ऐसा आचरण उसे देखने को मिल रहा है। निर्मल कितनी बार कहते थे - 'गीता तुम कितनी सहजता से अविनाश के साथ बातें कर लेती हो, खेल लेती हो! मैं तो उसे गले लगाकर रो पड़ता हूँ।'

गीता के व्यवहार के असर से अगर अविनाश की चेतना और संवेदना बनी रही तो इसका ये भी अर्थ होता है कि उसने पूरा प्रयास नहीं किया। अगर वो पूरा प्रयास करे तो अविनाश अवश्य ही इस लायक हो जाएगा कि वो स्वयं को पूरी तरह संभाल सके। गीता के मन में एक नया विश्वास, स्वयं के लिए और अविनाश के लिए भी पैदा हुआ। उसे महात्मा गांधी का कथन आज नए अर्थ के साथ समझ में आया। 'हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं, उसके बीच का अंतर दुनिया की ज्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त है।'

गीता को ओर अधिक प्रयास करना था, अब वही करेगी, अथक प्रयास करने से नहीं घबरायेगी। अविनाश और स्वयं के संयुक्त प्रयास से वो अवश्य ही बेटे की उत्तरजीविता के प्रयास को साकार रूप दे पायेगी। किसी ने सच कहा है 'महान उपलब्धियां आसानी से नहीं मिलतीं ओर आसानी से मिली उपलब्धियां महान नहीं हो सकतीं।'

परवीन शाकिर की ग़ज़लें

1

वो तो ख़ुश-बू है हवाओं में बिखर जाएगा
मसअला फूल का है फूल किधर जाएगा

हम तो समझे थे कि इक ज़ख़्म है भर जाएगा
क्या ख़बर थी कि रग-ए-जाँ में उतर जाएगा

वो हवाओं की तरह ख़ाना-ब-जाँ फिरता है
एक झोंका है जो आएगा गुज़र जाएगा

वो जब आएगा तो फिर उस की रिफ़ाक़त के लिए
मौसम-ए-गुल मिरे आँगन में ठहर जाएगा

आख़िरश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी
तेरा ये प्यार भी दरिया है उतर जाएगा

मुझ को तहज़ीब के बर्ज़ख़ का बनाया वारिस
जुर्म ये भी मिरे अज्दाद के सर जाएगा

2

पूरा दुख और आधा चाँद
हिज्र की शब और ऐसा चाँद

दिन में वहशत बहल गई
रात हुई और निकला चाँद

किस मक़्तल से गुज़रा होगा
इतना सहमा सहमा चाँद

यादों की आबाद गली में
घूम रहा है तन्हा चाँद

मेरी करवट पर जाग उठे
नींद का कितना कच्चा चाँद

मेरे मुँह को किस हैरत से
देख रहा है भोला चाँद

इतने घने बादल के पीछे
कितना तन्हा होगा चाँद

आँसू रोके नूर नहाए
दिल दरिया तन सहरा चाँद

इतने रौशन चेहरे पर भी
सूरज का है साया चाँद

जब पानी में चेहरा देखा
तू ने किस को सोचा चाँद

बरगद की इक शाख़ हटा कर
जाने किस को झाँका चाँद

बादल के रेशम झूले में
भोर समय तक सोया चाँद

रात के शाने पर सर रक्खे
देख रहा है सपना चाँद

सूखे पत्तों के झुरमुट पर
शबनम थी या नन्हा चाँद

हाथ हिला कर रुख़सत होगा
उस की सूरत हिज्र का चाँद

सहरा सहरा भटक रहा है
अपने इश्क़ में सच्चा चाँद

रात के शायद एक बजे हैं
सोता होगा मेरा चाँद

व्यंग्य

एक नफरत कथा

■ शंकर पुणतांबेकर

यह सही है कि 'हेट्रेड इज ब्लाइंड', वरना ख में ऐसा कुछ बुरा नही था कि उसे देख क उससे नफरत करने लगता. ख की जाति, वर्ण, दृष्टि, खानपान, बोली, त्योहार भिन्न थे पर बुरे नहीं. या यों कहें कि वे ऐसे ही अच्छे-बुरे थे जैसे क के. फिर भी क ख की नफरत में पड़ गया. क ने उसे एक फंक्शन में देखा जो उसी की जमात का था. यहां ख से क की चार आंखें हुईं और उसकी उससे नफरत हो गयी. यह एक प्रकार से फर्स्ट साइट हेट्रेड थी.

क ख की गली में चक्कर मारने लगा. दो-चार बार ख उसे दिखा पर उससे एकदम बात करने की हिम्मत नहीं हुई. जी मसोसकर रह गया. आखिर एक दिन उसने उसे छेड़ा, 'अबे ए साले' ख ने उसकी ओर देखा और कोई गुंडा है समझकर आगे बढ़ गया.

इसके दूसरे या तीसरे दिन क ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा 'अबे ए कहां जा रहा है?' कहीं भी, तुम्हें इससे क्या.' ख ने कहा. और उसे धक्का दे आगे बढ़ गया.

ख का नफरत-भरा धक्का पा. क के बदन में जो आग जगी उससे वह धन्य हो गया. पहले स्पर्श की अनुभूति कुछ और ही होती है.

क ने एक दिन ख का पीछा किया. क को अपना पीछा करते देख ख के कदम ख बस से उतरा, वह भी उतर गया. क को अपना पीछा करते देख ख के कदम तेज़ हुए. क के भी तेज़ हुए. ख एक बगीचे में घुस गया. क भी घुस गया.

'भागो नहीं', क ने आखिर निर्लज्ज होकर कहा, 'मैं तुम्हारा आशिक हूं. तुमसे नफरत करता हूं.' 'यह सभ्य आदमी के लक्षण नहीं है.' एक बेंच पर सिकुड़ते हुए बैठकर ख ने कहा, 'तुम्हें कोई काम-धंधा नहीं है जो ऐसे आशिक बने फिरते हो?'

'मेरे दुश्मन, तुम्हारी नफरत के पीछे मुझे कोई काम-धंधा नहीं सुहाता.' उसकी बगल में बेंच पर बैठते हुए क ने कहा, 'तुम नहीं जानते जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुमसे ऐसी नफरत हो गयी है कि रात को चैन से नींद भी नहीं आती.'

ख और सिकुड़ गया. उसने क को कनखियों से देखा. उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वह उसकी नफरत को स्वीकार करे.

'बोलो, मेरे दुश्मन कुछ तो बोलो! तुम्हारे साथ गाली-गलौच करने के लिए मेरा जी कितना तड़प रहा है. कहो तो मैं ही शुरू करूं?ज बदमाश, गुंडे, हरामखोरज'

ख उठकर एकदम भागा. क आह भरकर रह गया.

क ने ख को एक दिन बाज़ार में पकड़ लिया और घिसटकर उसे एक चाय की दुकान में ले गया.

'साले, तुम्हें मुझमें ऐसा कुछ नहीं दिखता कि तुम मुझसे नफरत करो?' आमने-सामने बैठे चाय पीते हुए क ने ख से कहा, 'मेरी तुमसे जात अलग है, मेरा तुमसे धरम अलग है. इससे बढ़कर और क्या चाहिए साले किसी से नफरत के लिए?'

ख चुप था.

'तुम साले मुझसे नफरत नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जाति को बुरा कहूंगा. तुम्हारे धरम को गालियां दूंगा. तुम्हारे त्यौहारों-उत्सवों पर पत्थरबाजी करूंगा. पूरी तरह गुंडेबाजी पर उतर आऊंगा तो देखता हूं, तुम मुझसे नफरत कैसे नहीं करते?'

ख ने जैसे-तैसे चाय खत्म की और हिम्मत करके बोला, 'मैं नफरत कैसे करूं.'

'जाति और धरम तो तुम्हारे भी मुझे बुरे नहीं लगते. पर तुम्हारे जाति धरम मेरे जाति-धरम से अलग हैं, यही हमारे लिए नफरत को काफी है. तुम मेरे जाति-धरम को गाली दो, मैं तुम्हारे जाति-धरम को गाली दूं, इस बात के लिए मैं कितने दिनों से पागल हूं, तुम नहीं जानते.'

एक दिन सचमुच क ने कुछ गुंडों को साथ ले ख की गली में पत्थरबाजी की. उस दिन कोई त्यौहार था. ख अपने मकान के बाहर आया. उसके सिर को पत्थर की चोट लगी.

'साले, गुंडे, बदमाश! मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोडूंगा.' क को देखकर ख दहाड़ा और अंदर से हॉकी स्टिक ले आया.

'उस दिन तुम्हारी नफरत पाकर मैं निहाल हो उठा मेरे दुश्मन!' एक दिन सिनेमा थिएटर पर क ख को देख उससे बोला, 'इधर कई दिनों से तुम दिखाई नहीं दिये तो मेरा जी कैसा-कैसा हो रहा था! तुम्हारी एक नफरत-भरी निगाह के लिए तरस गया. कहीं बाहर चले गये थे क्या?'

ख ने उससे बात नहीं की और हॉल में घुस गया.

लेकिन क ने उसे छोड़ा नहीं. फिल्म जब खत्म हो गयी तो रास्ते पर क उससे बोला, 'तुम कन्नी क्यों काटते हो मेरे दुश्मन, जब तुम भी मुझसे नफरत करने लगे हो?'

'क्या यह अच्छा है कि हम एक-दूसरे से नफरत करें?' ख बोला, हम एक ही देश के हैं, हम भाई-भाई हैं. हमारी परम्परा, हमारे राजनेता हमें रोकते हैं नफरत से.'

'भाड़ में जाये परम्परा और राजनेता. मुहब्बत की तरह नफरत को भी कोई रोक सका है भला! मैं इधर अब हाथापाई के लिए तड़प उठा हूं. कितनी बार सपने में देखा है कि मैं तुम पर सवार हूं, तुम मुझ पर सवार हो. दोनों ओर से लाठियां चल रही हैं.'

ख ने कहा, 'नहीं भाई, इस तरह के हनीमून से लाशें पैदा होती हैं.'

'होती रहें लाशें पैदा, हमारी बला से. अब जब हम एक-दूसरे से नफरत करते हैं तो उसके अंजाम से क्या डरना! अगले हफ्ते मेरी जात का त्यौहार है, तुम उस दिन पथराव करना. हम भी इधर तुम्हारा मुकाबला करने की तैयारी में रहेंगे. देखना चूकना नहीं.'

उस त्यौहार के दिन पथराव हुआ, स्टिकें चलीं, बोतलें चलीं, पुलिस आयी. दोनों ओर लाशें बिछीं.

क को संतोष था कि अब मेरी नफरत इकतरफा नहीं रही.

नवनीत से साभार

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीतकर न केवल खेल के मैदान में बल्कि देश के हर घर में गर्व, प्रेरणा और आत्मविश्वास का संचार किया है। यह विजय भारतीय खेल इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, एक ऐसा क्षण जिसने यह साबित कर दिया कि अब महिला खिलाड़ी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि भारतीय नारी शक्ति की नई परिभाषा है। इस ऐतिहासिक जीत ने भारत की लाखों लड़कियों के दिलों में एक नया सपना जगाया है। जहां कभी क्रिकेट को पुरुषों का खेल माना जाता था, आज के बाद महिला क्रिकेट को भी बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। 1983 की कपिल देव की टीम की तरह ही उन्होंने सिद्ध किया कि उनमें जोश जज्बे और देश के लिए कुछ करने के माद्दे की कमी नहीं है। अवसर को कैसे बनाया जाए इसकी मिसाल दी युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने, उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, अनुभवी स्मृति मंधाना की सधी हुई पारी और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी, मिताली का कैच, रेणुका सिंह ठाकुर की गेंदबाजी का जिक्र तो होगा ही, सबसे ज्यादा जिक्र होगा इन खिलाड़ियों की टीम स्पिरिट और खेल भावना के नायाब प्रदर्शन का। महिला क्रिकेट के संघर्ष और सफलता का विश्लेषण करता *आजकल* का यह खास अंक...

मुबारक हो उपेक्षित रात की स्वर्णिम सुबह

विश्लेषण

डॉ. घनश्याम बादल

स्वतंत्र पत्रकार

दो नवंबर 2025 की रोशन रात भारतीय खेल जगत की एक ऐतिहासिक एवं स्वर्णिम घटना के रूप में याद की जाएगी जो भारत और यहां की लड़कियों तथा महिला खिलाड़ियों के लिए एक स्वर्णिम सुबह लेकर आई। यदि इस जीत को हमने देश के महिला जगत एवं खेल जगत के लिए एक अवसर के रूप में इस्तेमाल कर लिया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह जीत यह एक 'टर्निंग प्वाइंट' सिद्ध होगी। भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने अफ्रीका की मजबूत क्रिकेट टीम को 52 रन के भारी अंतर से हराकर आईसीसी महिला विश्व क्रिकेट कप पर ही कब्जा नहीं किया अपितु यह सिद्ध किया है कि अब भारत की लड़कियां दुनिया के किसी हिस्से की लड़कियों से कम नहीं हैं।

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीतकर न केवल खेल के मैदान में बल्कि देश के हर घर में गर्व, प्रेरणा और आत्मविश्वास का संचार किया है। यह विजय भारतीय खेल इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, एक ऐसा क्षण जिसने यह साबित कर दिया कि अब महिला खिलाड़ी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि भारतीय नारी शक्ति की नई परिभाषा है।

भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने अफ्रीका की मजबूत क्रिकेट टीम को 52 रन के भारी अंतर से हराकर आईसीसी महिला विश्व क्रिकेट कप पर ही कब्जा नहीं किया अपितु यह सिद्ध किया है कि अब भारत की लड़कियां दुनिया के किसी हिस्से की लड़कियों से कम नहीं हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीतकर न केवल खेल के मैदान में बल्कि देश के हर घर में गर्व, प्रेरणा और आत्मविश्वास का संचार किया है। एक ऐसा क्षण जिसने यह साबित कर दिया कि अब महिला खिलाड़ी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं।

खेल से मंत्रमुग्ध किया

पूरे टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने अपने खेल से मंत्रमुग्ध किया। कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम ने हर चुनौती, हार-जीत और उतार चढ़ाव का डटकर सामना किया और लीग चरण से लेकर फाइनल तक अपनी रणनीति, अनुशासन और टीम भावना के बल पर देश को विश्व चैंपियन बनाया। इस विश्व कप के फाइनल में जीत का परचम लहराने वाली इन लड़कियों का सामना हार से भी हुआ और वह लगातार तीन मैच ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तथा दक्षिण अफ्रीका से हारी। जब वह हार रही थीं तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये शेरनियां पलट कर ऐसा वार भी कर सकती हैं। 1983 की कपिल देव की टीम की तरह ही उन्होंने सिद्ध किया कि उनमें जोश जज्बे और देश के लिए कुछ करने के माद्दे की कमी नहीं है। अवसर को कैसे बनाया जाए इसकी मिसाल दी युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने, उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, अनुभवी स्मृति मंधाना की सधी हुई पारी और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी, मिताली का कैच, रेणुका सिंह ठाकुर की गेंदबाजी का जिक्र तो होगा ही, सबसे ज्यादा जिक्र होगा इन खिलाड़ियों की टीम स्पिरिट और खेल भावना के नायाब प्रदर्शन का। सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को हराना ऐतिहासिक था।

टीम का जज्बा और संकल्प

फाइनल में 52 रन की बड़ी जीत इस टीम के जज्बे और संकल्प को रेखांकित करती है। इस मैच में भारतीय टीम ने न केवल तकनीकी श्रेष्ठता बल्कि मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया। हर खिलाड़ी ने टीम की सफलता में योगदान दिया, चाहे वह फील्डिंग में चपलता हो या आखिरी ओवरों में दबाव झेलने की क्षमता। इस विजय का सबसे बड़ा कारण टीम स्पिरिट और आपसी विश्वास था। हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका को बखूबी समझा और व्यक्तिगत उपलब्धियों से अधिक टीम की जीत को प्राथमिकता दी। इस टीम के कोच और देश के अंदरूनी क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर कहे जाने वाले अनमोल मजूमदार की कभी नीली जर्सी ना पहन पाने की टीस भी इन लड़कियों ने खत्म कर दी। उनकी कोचिंग, कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट टीम की भी खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तैयार करने में अहम भूमिका रही। टीम की यह एकजुटता और सामूहिक प्रयास उस परंपरा का प्रतीक है जिसमें सामूहिक सफलता को सर्वोच्च माना जाता है। महिला खिलाड़ियों ने यह दिखा दिया कि सफलता केवल व्यक्तिगत प्रतिभा से नहीं, बल्कि सामूहिक समर्पण और एक-दूसरे पर भरोसे से हासिल होती है। इस ऐतिहासिक जीत ने भारत की लाखों लड़कियों के दिलों में एक नया सपना जगाया है। जहां कभी क्रिकेट को पुरुषों का खेल माना जाता था, आज के बाद महिला क्रिकेट को भी बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि सरकार और समाज तथा प्रमोटर पैसे की बारिश कर सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है।

सामाजिक मानसिकता बदलेगी

'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' की तर्ज पर ही 'बेटी खिलाओ, बेटी बढ़ाओ' जैसे अभियान यथार्थ के धरातल पर चलाए जाने चाहिए। बेशक, यदि सब ठीक रहे तो यह जीत सामाजिक मानसिकता में बड़ा परिवर्तन लाएगी। अब माता-पिता अपनी बेटियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। महिला खेल अकादमियों की स्थापना व वृद्धि के साथ वहां की दशा एवं दिशा दोनों में सुधार की गति को बढ़ाना होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि यह जीत इन प्रयासों को और गति देगी। विश्व चैंपियन बनने के साथ ही भारतीय महिला क्रिकेट एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह विजय न केवल खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी बल्कि महिला क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ करेगी और विश्व कप की जीत से इसकी लोकप्रियता और निवेश दोनों में वृद्धि होगी, ऐसी उम्मीद करना अनुचित नहीं होगा।

सरकार को देना होगा ध्यान

नए स्पॉन्सर, बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक मैचों की संभावना आने वाले वर्षों में भारत को विश्व की सबसे मजबूत महिला क्रिकेट संरचनाओं में से एक बना सकता है। महिला क्रिकेट की इस अभूतपूर्व सफलता को बनाए रखने के लिए सरकार और समाज दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार को चाहिए कि वह महिला खिलाड़ियों को उचित आर्थिक सहायता, विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र और खेल उपकरण उपलब्ध कराए। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में महिला क्रिकेट अकादमियों की स्थापना से नई प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। साथ ही, खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरियों और प्रोत्साहनों से सम्मानित करना चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हुए अपने खेल पर पूरा ध्यान दे सकें। मीडिया और निजी क्षेत्र को भी महिला क्रिकेट को उसी स्तर की पहचान देनी चाहिए जैसी पुरुष क्रिकेट को दी जाती है। यह ट्रॉफी भारत के लिए केवल एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस जीत ने यह संदेश दिया है कि यदि अवसर मिले तो भारतीय महिलाएं किसी भी क्षेत्र में विश्व विजेता बन सकती हैं।

मगर याद यह भी रखना होगा कि जीत की परंपरा कायम रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसलिए इससे खुश होने के साथ-साथ इसे बरकरार रखने के लिए कड़े परिश्रम की भी जरूरत होगी।

क्रिकेट के आकाश पर छाई भारत की बेटियां

जय हो

रोहित माहेश्वरी

स्वतंत्र पत्रकार

नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला खेला गया। इसमें टीम इंडिया ने मेहमान टीम को 52 रनों से हराकर इतिहास रच दिया है। इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने ये करिश्मा करके दिखाया है। इसका जश्न आज पूरा भारत मना रहा रहा है। भारत की बेटियों की जय हो! वाह, क्या खेल दिखाया है? क्या जुझारू पारी और एकाग्रता की मिसाल कायम की है? विश्व कप में भारत की बेटियों ने जो खेल खेला है, वह वाकई अद्भुत, अप्रत्याशित, अभूतपूर्व, अकल्पनीय, अतुलनीय है! यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में बसी उम्मीदों का चरमोत्कर्ष था। यह आधी आबादी को संबल देने वाली जीत है जो नजीर बन गई उनके लिए जो एक मुकाम हासिल करना चाहती हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक फाइनल मुकाबले पर हर किसी की नजरें बनी हुई थीं। 25 साल के विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में एक बार फिर से महिला क्रिकेट टीम के सामने एक सुनहरा मौका था और उन्होंने इसमें बाजी मारते हुए विश्वे विजेता बनकर देश का मान और गौरव बढ़ा दिया है। विमेंस क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका जीत के लिए 299 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में पूरी मेहमान टीम 45.3 ओवर में 246 रनों पर सिमट गई और 52 रनों से टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया। भारत और हम भारतीयों को अपेक्षाएं ही नहीं थीं। हमने महिला क्रिकेट तो क्या, महिला खिलाडियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। फाइनल मैच से पहले सेमीफाइनल में भारत की बेटियों ने जो करिश्मा कर दिखाया। उसकी बात करना जरूरी जान पड़ता है। असल में वो मैच निर्णायक मैच तो था ही। वहीं उस मैच में मिली जीत ने टीम इंडिया के आत्मविश्वास का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया था। महिला टीम इंडिया ने 7 बार की विश्व चैम्पियन और लगातार 15 मैचों की अजेय ऑस्ट्रेलिया टीम को पराजित कर विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया, वो पल खेल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ग्रुप स्तर पर टीम इंडिया के 330 रनों का सफल चेज कर जीत हासिल की थी। लिहाजा सेमीफाइनल मुकाबले में किसी अतिरिक्त करिश्मे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स के रूप में मानो कोई फरिश्ता उतर आया और उसने अभूतपूर्व करिश्मा कर दिखाया। जेमिमा को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में 'ड्रॉप' किया गया था। जेमिमा की फॉर्म भी अच्छी नहीं थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने 70 से अधिक रन ठोके थे। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन का पहाड़-जैसा लक्ष्य दिया था। जवाब में जब टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज-शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना-अपेक्षाकृत कम स्कोर पर आउट हो गए, तो भारत की पारी डूबती-सी लगी। उन स्थितियों में जेमिमा ने नाबाद 127 रन (134 गेंद, 14 चौके) बनाकर न केवल विश्व कप का अपना पहला शतक लगाया, बल्कि कप्तान हरमनप्रीत कौर (88 गेंद पर 89 रन) के साथ तीसरे विकेट की साझेदारी में 167 रन (156 गेंद) बना कर 'पहाड़' की ऊंचाई को एक हद तक कम कर दिया।

विश्व कप में भारत की बेटियों ने जो खेल खेला है, वह वाकई अद्भुत, अप्रत्याशित, अभूतपूर्व, अकल्पनीय, अतुलनीय है! यह 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में बसी उम्मीदों का चरमोत्कर्ष था।

जेमिमा ने दीप्ति शर्मा के साथ 38 रन (34 गेंद), ऋचा घोष के साथ 46 रन (31 गेंद) और अमनजोत कौर के साथ नाबाद 31 रन (15 गेंद) जोड़े और एक अविश्वसनीय-सी लग रही जीत पर मुहर लगा दी। विश्व कप का यह सबसे बड़ा और सफल चेस रहा। भारत ने 1978 में पहली बार महिला विश्व कप में हिस्सा लिया था। 2005 व 2017 में मिताली राज की कप्तानी में भारत फाइनल तक पहुंचा, पर दोनों बार ट्रॉफी हाथ से फिसल गई। आखिरकार हरमनप्रीत की कप्तानी में टीम विश्व विजेता बन गई। महिला टीम की यह पहली आईसीसी ट्रॉफी है। यह जीत सिर्फ मैदान की नहीं, बल्कि मानसिकता की जीत है। अब गांव-शहर की लड़कियां क्रिकेट को करियर के रूप में देखेंगी। माता-पिता भी बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 'लड़की होकर क्रिकेट' जैसी पुरानी सोच को यह जीत हमेशा के लिए बदल देगी। शेफाली, दीप्ति और हरमनप्रीत जैसी खिलाड़ी अब हर लड़की की प्रेरणा बनेंगी। कोहली, गिल की तरह ही अब हमारी लड़कियां भी नए हेयरस्टाइल, टैटू के साथ युवाओं के लिए नई सुपरस्टार और रोल मॉडल होंगी। यह ट्रॉफी सिर्फ एक खिताब नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, समान अवसर और नए भारत की नारी शक्ति का उदाहरण बन जाएगी।

महिला क्रिकेट टीम ने रचा विश्व कप का नया इतिहास

कीर्तिमान

डॉ. प्रियंका सौरभ

स्वतंत्र पत्रकार

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर वर्ष 2025 का क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि उस अदम्य जज़्बे, संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है जिसने वर्षों से भारतीय बेटियों को खेल के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। यह क्षण हर भारतीय के लिए गर्व, उत्साह और प्रेरणा का है, क्योंकि यह सिर्फ मैदान की जीत नहीं, बल्कि मानसिकता की भी जीत है। भारतीय महिला क्रिकेट का यह गौरवशाली अध्याय उस लंबे सफर का परिणाम है, जो संघर्ष, सीमित संसाधनों और सामाजिक बाधाओं के बीच शुरू हुआ था। एक समय ऐसा भी था जब महिला क्रिकेट को गम्भीरता से नहीं लिया जाता था, न दर्शक होते थे, न प्रायोजक। लेकिन समय बदला, और इन बेटियों ने अपने खेल, समर्पण और प्रतिभा के बल पर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि खेल का मैदान किसी एक लिंग की बपौती नहीं है। आज जब भारत विश्व कप जीतकर विश्व का सिरमौर बना है, तो यह जीत हर उस बेटी की आवाज है जिसने अपने सपनों को समाज की बंदिशों से ऊपर रखा। यह जीत केवल एक खेल प्रतियोगिता की विजय नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक परिवर्तन का प्रतीक है जो भारत में महिलाओं की स्थिति और दृष्टिकोण को लेकर हो रहा है। कभी जिन बेटियों को कहा जाता था कि "खेल लड़कियों का काम नहीं", वही आज विश्व चैंपियन बनी खड़ी हैं।

यह जीत केवल एक खेल प्रतियोगिता की विजय नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक परिवर्तन का प्रतीक है जो भारत में महिलाओं की स्थिति और दृष्टिकोण को लेकर हो रहा है।

इस जीत ने समाज को यह संदेश दिया है कि अगर अवसर मिले तो भारतीय महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं। आज ये खिलाड़ी सिर्फ खेल नहीं रही हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता तैयार कर रही हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का यह गौरवशाली प्रदर्शन वर्षों के परिश्रम का परिणाम है। महिला आईपीएल ने खिलाड़ियों को मंच और आत्मविश्वास दोनों दिया। छोटे शहरों और कस्बों से आने वाली खिलाड़ी जैसे कि प्रतीका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, स्नेह राणा, राधा यादव और रेणुका ठाकुर ने दिखा दिया कि प्रतिभा किसी भौगोलिक सीमा की मोहताज नहीं होती। इन खिलाड़ियों ने न केवल मैदान में बल्कि देश के हर घर में प्रेरणा की नई कहानी लिख दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और खेल मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में महिला क्रिकेट को लेकर जो नीतिगत बदलाव किए हैं, वे इस सफलता की बुनियाद बने। समान वेतन नीति ने खिलाड़ियों को आत्म-सम्मान दिया, जबकि बेहतर कोचिंग सुविधाएँ और घरेलू टूर्नामेंट्स ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। यह देखना सुखद है कि अब महिला क्रिकेट को भी वही सम्मान और प्रसारण मिल रहा है जो पुरुष टीम को मिलता है।

जीत के जश्न का दमदार आगाज

मोनिका डागा

नई ऐतिहासिक जीत के जश्न का दमदार आगाज किया है,
घर में छुपी बंद मुस्कुराहटों को बिखेरने का साज दिया है,
बेटियों ने बेटियों को भविष्य का एक सुंदर ख्वाब दिया है,
बुलंद हौसलों से कठिनाइयों को मुँह तोड़ जवाब दिया है ।

तोड़कर बंदिशें तपस्या से दृढ़ संकल्प को संजीव किया है,
प्रतिभाशाली व्यक्तिव से जड़ों को मजबूत अतीव किया हैं
ख़्वाबों को हक़ीक़त की धरातल पर श्रम से रंगीन किया है,
खुशियों के आँसू दे धड़कनों को आनंद यूं नवीन दिया हैं।

पैनी नजर लक्ष्य की पकड़ संग धैर्य का समावेश किया है,
हार को जीत में ढालना है संभव श्रेष्ठतम परिवेश दिया हैं,
आत्म विश्वास और उत्साह की किरणों का प्रकाश दिया हैं,
अरबों आंखों में पल रहे रंगीन सपनों को आकाश दिया है ।

सर्पीले रास्तों पर पसीने का चमकता शीतल चंदन दिया है,
भारत का ही नहीं विश्व की धड़कनों को नया स्पंदन दिया है,
संगठन की ताकत और समर्पण का जज़्बा प्रस्तुत किया है,
जीत कर वूमेन्स वर्ल्ड कप अलग उदाहरण अद्भुत दिया हैं।

खुद पर करना होगा यकीं ऐसा महत्वपूर्ण अभ्यास दिया हैं,
जोर शोर हिलोर मचाने को रचने को नया इतिहास दिया है,
नीली जर्सी में बेटियों ने शानदार जीत को अंजाम दिया हैं,
दबी चाहतों को अर्जुन के तीर सा लक्ष्यभेदी पैगाम दिया हैं ।

म्हारी छोरियां, छोरों से कम नहीं...

इनामों की बरसात

आईसीसी महिला विश्व कप में भारतीय टीम की जीत के बाद से ही देश में जश्न है और लोग बेटियों को बधाई देते नहीं थक रहे हैं. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम पर लगातार इनामों की बरसात हो रही है।

▶▶ बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सम्मान के तौर पर 51 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसमें सभी खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ और राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य शामिल हैं।

▶▶ मध्यप्रदेश सरकार ने टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए एक करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।

▶▶ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया।

▶▶ रियल एस्टेट कंपनी ओमैक्स लिमिटेड ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमन प्रीत कौर को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है।

▶▶ उत्तर प्रदेश में दीप्ति शर्मा को उपाधीक्षक बनाया गया है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लिख डाली नई गौरव-गाथा

विश्व कप क्रिकेट

सुनील कुमार महला

स्वतंत्र पत्रकार

दो नवंबर 2025 का दिन अपने-आप में ऐतिहासिक बन गया और हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दरअसल, इस दिन हमारे देश की महिला क्रिकेट टीम 'विश्व विजेत्री' बन गई। रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में सात विकेट पर 298 रन बनाए तथा जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर में 246 रन पर ऑलआउट हो गई। इस मैच में साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन भारत ने यह मुकाबला 52 रन से जीत लिया और पहली बार महिला टीम वनडे विश्व कप का खिताब जीतने में कामयाब रही। हालांकि, लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वूलवार्ट ने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी। उन्होंने दबाव में रहते हुए भी शानदार बल्लेबाजी की और लगातार दूसरा शतक जड़ते हुए 101 रन बनाए। कहना ग़लत नहीं होगा कि उनकी पारी ने मैच को काफ़ी रोमांचक बनाए रखा, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका। इधर, हरमनप्रीत कौर ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया और अब वह कपिल देव, एमएस धोनी और रोहित शर्मा जैसे महान कप्तानों की श्रेणी में शामिल हो गई हैं, विशेष बधाई और शुभकामनाएं। वास्तव में, यह दर्शाता है कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से कम नहीं हैं। आज हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित कर रहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आज महिला सशक्तीकरण हो रहा है।

महिलाएं हर क्षेत्र में आगे

सच तो यह है कि आज महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। वे राजनीति, विज्ञान, शिक्षा, खेल, रक्षा, अंतरिक्ष और उद्योग जगत तक में उत्कृष्ट योगदान दे रही हैं। और तो और तकनीकी और चिकित्सा क्षेत्र में भी उनकी भूमिका तेजी से बढ़ी है। यह साबित करता है कि महिलाएं अब सीमाओं को तोड़कर हर क्षेत्र में अग्रणी बन चुकी हैं। हम यहां यह बात खुले दिल से कह सकते हैं कि महिला सशक्तीकरण का स्वर अब क्रिकेट के मैदानों में भी गूंजने लगा है। आज भारतीय महिला खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से विश्वभर में देश का नाम रौशन कर रही हैं। खेल के माध्यम से महिलाएं आत्मविश्वास, नेतृत्व और स्वतंत्र सोच का परिचय दे रही हैं। जहां तक क्रिकेट की बात है तो, क्रिकेट भी अब सिर्फ पुरुषों का खेल नहीं रहा है, बल्कि यह अब समान अवसर और सम्मान का प्रतीक बन गया है। यह बदलाव समाज में महिलाओं की बढ़ती ताकत और उनकी नई पहचान का सशक्त उदाहरण है। बताते चलें कि 25 जून 1983 को कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। वही इतिहास अब दोबारा लिखा गया है, पर इस बार बल्ला थामा हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को करारी शिकस्त देकर विश्व क्रिकेट में एक नया स्वर्ण अध्याय जोड़ दिया है।

महिला सशक्तीकरण का स्वर अब क्रिकेट के मैदान में भी गूंजने लगा है। आज भारतीय महिला खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से विश्वभर में आत्मविश्वास, नेतृत्व और स्वतंत्र सोच का परिचय दे रही हैं।

भारतीय नारी शक्ति की जीत

यह जीत सिर्फ एक खेल की जीत नहीं, बल्कि भारतीय नारी शक्ति की उड़ान का प्रतीक है। हर महिला खिलाड़ी ने मैदान पर ऐसा जज़्बा दिखाया, मानो 1983 की आत्मा फिर से जीवित हो उठी हो। करोड़ों भारतीयों के दिलों में गर्व और खुशी का सैलाब उमड़ पड़ा है। महिला क्रिकेट की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी कि मेहनत और हौसले से कोई भी सपना असंभव नहीं। अब भारत न केवल पुरुष क्रिकेट का, बल्कि महिला क्रिकेट का भी विश्व विजेता बन चुका है। कहना ग़लत नहीं होगा कि वास्तव में यह सच्चे अर्थों में 'नए भारत' का गौरव क्षण है। इस खिताबी जीत में शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा का अहम योगदान रहा। रोहतक की शेफाली ने पहले 78 गेंद पर 87 रन बनाए और फिर बाद में अपनी फिरकी का जादू चलाते हुए शीर्ष पांच में से दो साउथ अफ्रीकी बैटर्स के विकेट भी निकाले। दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए और शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी ऑफ-स्पिन से 39 रन देकर 5 विकेट भी लिए। वास्तव में सच तो यह है कि भारतीय जीत की वास्तुकार बनीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा।

उन्होंने ही निर्णायक क्षणों में शतकवीर वूलवार्ट का विकेट लिया, जिससे दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें टूट गईं। उनकी इस जादुई गेंदबाजी ने टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की। शेफाली वर्मा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जबकि दीप्ति शर्मा को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत से देशभर में महिलाओं के खेल के प्रति नजरिया और भी सकारात्मक होगा। यह जीत न केवल खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को नई ऊँचाइयाँ देगी, बल्कि आने वाली पीढ़ी की लड़कियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो यह जीत देश भर में महिला क्रिकेट के प्रति जागरूकता और समर्थन को भी बढ़ाएगी। उम्मीद है कि इस सफलता से महिला क्रिकेट को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा

https://t.me/AllNewsPaperPaid